हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

तेजपाल को सजा

आखिरकार बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने पूर्व मीडिया हस्ती तरुण तेजपाल को यौन दुराचरण मामले में दस साल कठोर कारावास की सजा सुना दी है। आरोपी पक्ष सजा को सर्वोच्च न्यायालय में जरूर चुनौती देगा, पर गौर करने की बात है, यहां तक पहुंचने में 12 वर्ष से ज्यादा वक्त लग गया। तरुण तेजपाल देश की एक चर्चित मीडिया हस्ती थे और उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के शोषण के लिए किया। उच्च न्यायालय ने तेजपाल के दुराचरण को बलात्कार माना है, जबकि सत्र न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था। एक बार फिर, तेजपाल के वकीलों ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। गोवा पीठ से अनुरोध किया गया कि वह उनके मुवक्किल के प्रति नरमी बरते, क्योंकि यह अपराध 13 साल पुराना है और अब वह 62 वर्ष के हो चुके हैं। साथ ही, यह भी बताने की कोशिश हुई कि तेजपाल के खिलाफ अन्य कोई मामला दर्ज नहीं है। खैर, तेजपाल के बचाव की हर कोशिश नाकाम हुई है और इंसाफ अपने मुकाम पर पहुंचा है।

तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उनकी पालना होनी ही चाहिए। ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाता है। पीड़िता तेजपाल की बेटी के उम्र की थी और उसके इनकार पर तेजपाल ने गौर नहीं किया। यह भूलना नहीं चाहिए, तेजपाल ने सीमाओं का उल्लंघन एक दिन नहीं, दो दिन किया। हम आज ऐसे दौर में हैं, जहां यह सुस्थापित बात है कि एक महिला के 'न' कहने का अर्थ केवल इनकार ही होता है और कुछ नहीं। समग्रता में यह मामला न्यायालयों की सामूहिक संवेदना को कठघरे में खड़ा करता है। न्याय न्यायमूर्ति के अपने विवेक पर निर्भर दिखता है। यह बात न्यायालय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि न्यायमूर्ति किन तथ्यों को देखना चाहते हैं। सत्र न्यायालय की सुनवाई और फैसले से ऐसा लगा कि पीड़िता को ही कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। दोष और दोषी के आचरण के बजाय पीड़िता के व्यवहार को देखने की कोशिश हुई थी। यही नहीं, पीड़िता को लिखे गए तेजपाल के माफीनामे को भी नजरंदाज कर दिया गया था। क्या दोष साबित करने के लिए माफीनामा पर्याप्त नहीं था?

यौन अपराध के मामलों में आरोपी के प्रति नरमी बरतने का कोई आधार नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उनकी पालना होनी ही चाहिए।

यह मुकदमा एक मिसाल बने। ऐसे मामलों में आरोपी के प्रति किसी भी तरह की नरमी बरतना गलत है। यह भी देखना चाहिए कि आरोपी ने बचने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए। सत्तारूढ़ दल पर आरोप भी लगाए, लेकिन इन बातों से अपराध की गंभीरता कतई कम नहीं हो जाती। जहां भी कानून का उल्लंघन होता है, वहां पूरी कड़ाई से फैसला लेने की जरूरत है। कॉरपोरेट दुनिया में ऐसी शिकायतों को आम तौर पर दबा दिया जाता है। पीड़ित पक्ष कानून की लंबी प्रक्रिया देखकर सहम जाता है। गौर कीजिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 90 प्रतिशत से अधिक घरेलू और यौन हिंसा के मामले छिपा लिए जाते हैं और कभी दर्ज नहीं हो पाते हैं। अगर सुनवाई और सजा जल्दी हो, तो निश्चित ही हर यौन अपराध दर्ज होने लगेगा, दुराचरण पर लगाम लगेगी और महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा होगा। इसी चर्चित मामले में हम देखें, तो अगर अंतिम फैसला दो या तीन साल के समय में ही आ जाता, तो जाहिर है, हमारे समाज पर कुछ ज्यादा असरदार होता। खैर, अंतिम रूप से इस मामले में फैसले के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि यह इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 07 अगस्त, 1951

राष्ट्रपति का भाषण

संविधान के अनुसार जब भी संसद का नया अधिवेशन शुरू होता है, राष्ट्रपति को उद्घाटन भाषण देना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस रिवाज का पालन करते हुए संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन की कार्रवाई शुरू की है। अपने भाषण में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रश्नों की सरसरी चर्चा की है: विभिन्न प्रश्नों के बारे में भारत सरकार जिस नीति का अनुसरण करती आ रही है, राष्ट्रपति ने उसी की पुष्टि की है। किसी प्रश्न पर उन्होंने सरकार के किसी बड़े निश्चय की घोषणा नहीं की है। राष्ट्रपति ने पिछली बार संसद के अधिवेशन में जो भाषण दिया था, उसमें निश्चित शब्दों में यह घोषणा की थी कि इस वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में आम चुनाव होंगे, किन्तु सरकार आम चुनावों के इस घोषित समय पर कायम नहीं रह सकी। राष्ट्रपति के भाषण में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने एक अनिश्चित-सी बात कहकर सन्तोष कर लिया है कि कुछ महीनों के भीतर आम चुनाव होंगे। उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि इन चुनावों में हमारे देश के लोगों को एक बड़ी कसौटी पर उतरना होगा। राष्ट्रपति को आशा है कि देशवासी अपनी जिम्मेदारी को भली-भांति निभायेंगे और कल्पनाशील, प्रामाणिक और उच्च सिद्धान्तों वाले व्यक्ति चुने जायेंगे। सिद्धान्तों पर उन्होंने जो बल दिया है, यह आवश्यक था।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अधिकतर ध्यान घरेलू समस्याओं पर ही केन्द्रित किया है। जिन विदेशी समस्याओं को उन्होंने स्पर्श किया है, उनमें कोरिया का पहला स्थान है। कोरिया में युद्धबन्दी की जो वार्ता चल रही है, राष्ट्रपति उसकी सफलता की कामना करते हैं। किन्तु युद्धबन्दी को ही वह आदि और अन्त नहीं समझते। दूर-पूर्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए और कदम उठाना आवश्यक होगा। इन समस्याओं के स्थायी हल के लिए यह आवश्यक होगा कि इस क्षेत्र से संबंधित देशों का आज की दुनिया में उचित स्थान स्वीकार किया जाये। राष्ट्रपति का इशारा चीन की ओर है, जिसको अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ से बहिष्कृत रखा जा रहा है। राष्ट्रपति के विचार से जापान की शान्ति संधि ऐसी होनी चाहिए जो तनाव को कम करने में सहायक हो और पूर्व के राष्ट्रों के आपसी सहयोग में वृद्धि कर सके। लक्षणों से प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की यह आशा शायद ही पूरी होगी।

शेख हसीना ने ढाका की बेचैनी बढ़ाई

सवाल केवल शेख हसीना की वतन-वापसी का नहीं है। क्या उनके लौटने से बांग्लादेश में राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा को नई धार मिलेगी या फिर वह और अधिक बंट जाएगी?

यहां स्कैन करें

संजय के भारद्वाज | प्रोफेसर, जेएनयू

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बुधवार का संबोधन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान होने के साथ-साथ अपने समर्थकों के मन को टटोलने का एक गंभीर प्रयास था। उन्होंने एलान किया कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी और इसके लिए गिरफ्तारी, जेल या जान का खतरा उठाने को भी तैयार हैं। अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की विरासत और 1971 के मुक्ति-संग्राम को याद करके वह भावुक भी हुईं। हालांकि, यह उनका पहला निर्वासन नहीं है। 1981, 1983, 1985 और 2007 का हवाला देते हुए उन्होंने खुद कहा कि पहले भी वह गिरफ्तारी, निर्वासन और जानलेवा हमलों का सामना कर चुकी हैं।

बड़ा सवाल केवल उनकी वतन-वापसी का नहीं है। क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा को नई धार देगी या पहले से बंटी हुई सियासत को और गहरे बांट देगी? इस सवाल का जवाब न सिर्फ अवामी लीग का भविष्य तय करेगा, बल्कि बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और नई दिल्ली के साथ ढाका के रिश्तों को दिशा भी देगा।

अपने संबोधन में हसीना ने तीन मुख्य मांगें रखी हैं- अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए, राजनीतिक कैदियों को फौरन रिहा किया जाए और न्यायपालिका व मीडिया की आजादी बहाल की जाए। मोहम्मद यूनुस के बयान का हवाला देते हुए, जिसमें उन्होंने जुलाई के आंदोलन को 'सुनियोजित' बताया था, हसीना ने 2024 के आंदोलन के पीछे के सियासी षड्यंत्र का प्रमाण भी दिया। न्यायिक जांच को रोके जाने का आरोप लगाकर उन्होंने अंतरिम सरकार को घेरा और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाए।

इन सबके दो निहितार्थ हैं- पहला, सन् 1971 की मूल भावना के साथ मुक्ति संग्राम के 'जीत के महीने', यानी 16 दिसंबर के गहरे प्रतीकात्मक महत्व को वह फिर से स्थापित करना चाहती हैं, क्योंकि यह एक ऐसी विरासत है, जिसे अवामी लीग मजबूती से आगे बढ़ाती रही है। दूसरा, अपनी वतन वापसी के लिए उन्होंने राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। गौरतलब यह भी है कि अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भी 1971 की विरासत पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया है। बीएनपी के मुताबिक, सशस्त्र संघर्ष जियाउर रहमान और उनकी सेना ने किया था और रेडियो पर बांग्लादेश की मुक्ति की घोषणा भी उन्होंने ही की थी। वैसे, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि 1975 के बाद बांग्लादेश की राजनीति में जियाउर रहमान की सत्ता के दौरान ही इस्लामी राजनीति को पाकिस्तानी तर्ज पर स्थापित करने का सांविधानिक व राजनीतिक प्रयास किया गया।

इस सूरते-हाल में, क्या हसीना का दिसंबर 2026 में उसी जोशो-खरोश से स्वागत हो सकेगा, जैसे 2007 में आम लोगों ने किया था? निस्संदेह, फरवरी के चुनाव में यदि सभी दलों की सहभागिता होती, तो अवामी लीग कम से कम दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक जमात जरूर होती। कानूनी प्रतिबंधों और नेतृत्व के संकट के बावजूद तकरीबन 30 फीसदी वोटरों पर उसका प्रभाव रहा है। ऐसे में, अपनी नेता का स्वागत करने के लिए अवामी लीग के समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर आ सकते हैं।

तारिक रहमान सरकार इससे वाकिफ है। यह भी एक वजह थी कि हसीना के संबोधन को बांग्लादेश में प्रसारित नहीं होने दिया गया। दरअसल, आम अवाम में तारिक रहमान की पकड़ अब तक नहीं बन सकी है। वह करीब 17 साल तक बांग्लादेश से बाहर रहे हैं, इसलिए उनके पार्टी काडर भी उनसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं। उन्हें बस वैकल्पिक नेता माना गया है। इसीलिए शेख हसीना की वापसी की घोषणा से सियासी फिजां में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अवामी लीग को फिर से देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा? लोकतांत्रिक रूप से जनता से फिर से जुड़ने के मौके तलाशना इस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी।

इन सबका असर भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ेगा। भारत ने शेख हसीना को सुरक्षा और शरण दी है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और भारत की जनता, दोनों का आभार व्यक्त किया, लेकिन दूसरी तरफ, नई दिल्ली ने ढाका के साथ अपना संपर्क भी बनाए रखा है। पिछले डेढ़ दशक में जहां भारत-बांग्लादेश संबंध काफी हद तक हसीना सरकार के साथ राजनीतिक विश्वास पर टिके रहे, वहीं हाल-फिलहाल केंद्र सरकार का प्रयास ढाका के साथ रिश्तों में फिर से गर्माहट लाने का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया भी है।

हालांकि, भारत के नजदीक आने में तारिक रहमान की उलझन जाहिर होती रही है। फरवरी, 2026 में पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने पहले मलेशिया और फिर चीन को चुना, जबकि भारत ने उन्हें पहले ही निमंत्रण भेजा था। उनकी चीन-यात्रा में मोंगला बंदरगाह जैसे संवेदनशील मसलों पर समझौते हुए, जिनसे भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हैं। इस समय दोनों देशों में कई मुद्दों पर मतभेद हैं- पहला, 1996 की गंगा जल संधि, जिसकी समय-सीमा आगामी दिसंबर में खत्म हो रही है। दूसरा, पिछले पंद्रह वर्षों से लंबित तीस्ता जल बंटवारा समझौता। तीसरा, शेख हसीना का आधिकारिक प्रत्यर्पण और चौथा, सीमा-पार व्यापार को सामान्य बनाना।

जाहिर है, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। उसे अपनी संधि संबंधी जिम्मेदारियों, रणनीतिक हितों और द्विपक्षीय संबंधों के बीच संतुलन रखना होगा। नई दिल्ली ने उचित ही प्रत्यर्पण को लेकर सवाल उठाए हैं। संधि में राजनीतिक अपराधों और प्रत्यर्पण से इनकार का आधार है। विशेषकर, संधि का अनुच्छेद-6 भारत को राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार की अनुमति देता है। हालांकि, हत्या, गैर-इरादतन हत्या, हत्या के लिए उकसाने और आतंकवाद से जुड़े अपराध इस अपवाद से बाहर हैं।

इन सबका यह भी अर्थ है कि दोनों देश एक-दूसरे को आंकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का बांग्लादेश में बड़ा निवेश है, वह सामरिक रूप से भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है और चीन का वहां बढ़ता प्रभाव भी चिंतनीय है। ढाका की चुनौती है कि वह अपने सियासी मतभेदों का हल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून के दायरे में खोजे। इससे न केवल शेख हसीना का भविष्य, बल्कि बांग्लादेश के लोकतंत्र की दशा-दिशा भी तय होगी। देखना है, वह इस परीक्षा में कैसे सफल होता है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हथकरघा से देश का समृद्ध भविष्य बुनते बुनकर

यहां स्कैन करें

गिरिराज सिंह | केंद्रीय वस्त्र मंत्री

एक विकसित राष्ट्र का निर्माण सिर्फ तकनीक से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अपनी स्थायी खूबियों को प्रगति के वाहक के रूप में बदल सकने की उसकी क्षमता से भी होता है। अब जब हमारा देश 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, तब हम अत्याधुनिक तकनीक में तो निवेश कर ही रहे हैं, अपनी समृद्ध विरासत में भी नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

हमारी हथकरघा परंपरा उन बड़ी खूबियों में से एक है, जो हमेशा से हमारे साथ रही है। आज जब देश अपना 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है, तब इस कुटीर उद्योग को एक ऐसे रणनीतिक क्षेत्र के तौर पर देखने का यह उपयुक्त अवसर है, जो स्थायित्व, प्रामाणिकता और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला को महत्व देने वाली दुनिया के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है, वह आत्मनिर्भरता, समावेशिता व सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर आधारित है। हथकरघा विरासत और नवाचार को जोड़कर इस सपने को साकार कर रहा है। यह देश की स्त्रियों के नेतृत्व में विकास, उद्यमिता, आजीविका और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता को बढ़ावा दे रहा है।

आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। यह कुटीर उद्योग देश के 35 लाख से अधिक बुनकरों और कामगारों की आजीविका का सहारा है।

हथकरघा महज एक शिल्प नहीं है, बल्कि भारत की महान सभ्यतागत विशेषताओं में से एक है। सबसे पहले कपास की खेती और बुनाई करने वाली सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर विश्व व्यापार में भारतीय कपड़े के दबदबे वाली 18वीं सदी तक, भारत ने वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्माण की उत्कृष्टता के मानक स्थापित किए। बंगाल के प्रसिद्ध मलमल के साथ-साथ बनारसी सिल्क, कांचीपुरम की बुनाई, पोचमपल्ली इकत और अनगिनत क्षेत्रीय परंपराओं ने भारत को दुनिया भर में पहचान व प्रशंसा दिलाई। आज जब दुनिया प्रामाणिक, टिकाऊ व हाथ से बने उत्पादों की ओर मुड़ रही है, तब हमारे पास अग्रणी स्थान फिर से हासिल करने का ऐतिहासिक मौका है। हमारी हथकरघा क्रांति में वस्त्र ही नहीं, कारीगरी, विरासत, नवाचार और भरोसे का भी निर्यात होना चाहिए, ताकि हर उत्पाद 'ब्रांड इंडिया' की पहचान बने।

हथकरघा हमारे देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। यह देश के 35 लाख से अधिक बुनकरों व उनसे जुड़े कामगारों की आजीविका का सहारा है। इन कामगारों में से लगभग 72 प्रतिशत महिलाएं हैं। पिछले दशक में सरकार ने कच्चा माल आपूर्ति योजना, 797 हथकरघा क्लस्टरों, 1.24 लाख से अधिक उन्नत करघों, लगभग 97,000 कारीगरों के कौशल विकास, जीआई टैग वाले उत्पादों, हैंडलूम मार्क, इंडिया हैंडमेड सर्टिफिकेशन, अर्बन हाट और डिजाइन रिसोर्स सेंटर जैसी पहल के जरिये इस क्षेत्र को सुदृढ़ किया है। आज 29 बुनकर सेवा केंद्र प्रशिक्षण, कौशल-उन्नयन, डिजाइन के विकास, कच्चे माल संबंधी सहायता और बाजार से जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं, 11 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी' को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि उन्नत प्रशिक्षण बढ़ाया जा सके व अधिक मूल्य वाले हथकरघा उत्पाद बनाए जा सकें।

नवाचार हमेशा से हथकरघा की यात्रा का हिस्सा रहा है। महात्मा गांधी के चरखे ने सूत कातने के काम को आसान, तेज और अपेक्षाकृत अधिक कुशल बनाया। इससे आत्मनिर्भरता का विजन आगे बढ़ा। हाल में, असम के मैना करघे और शिवसागर में विकसित चित्तरंजन करघे ने यह दर्शाया है कि करघे के बेहतर डिजाइन से बुनाई का काम कैसे आसान व अधिक उत्पादक हो सकता है। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर बनाया गया 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी' ऐसे करघे विकसित कर रहा है, जो हल्के, मजबूत और उपयोग में आसान हैं।

तकनीक को कारीगरों की जगह लेने के बजाय उनके सशक्तीकरण का जरिया बनना चाहिए। बेहतर ब्रांडिंग, मूल्य वर्धन और बाजार तक सीधी पहुंच के जरिये इस क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार बुनकरों की आय में काफी वृद्धि कर सकते हैं। हम अपने बुनकरों का सम्मान सिर्फ अपनी विरासत के संरक्षक के रूप में नहीं, बल्कि देश की प्रगति के शिल्पकार के रूप में भी करें। हमारे द्वारा खरीदा गया हर हथकरघा उत्पाद सदियों पुरानी परंपरा को संजोता है और भारत की कहानी को दुनिया तक पहुंचाता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

लगाव बुरी बात नहीं

किसने कहा कि लगाव होने पर विकास नहीं होगा? धरती पर आसक्त होकर जब पेड़ अपनी जड़ों को माटी के अंदर गहराई में फैलाता है, तभी वह स्वस्थ रूप में पनपता है, अनेक पक्षियों को आश्रय देता है। हवा में प्राण-वायु का प्रवाह करता है। फल देकर दूसरों का उपकार करता है। यदि उसे धरती से अलग कर दें, उखाड़कर फेंक दें, तो वह नष्ट हो जाता है।

आपके विषय में भी यही बात सही है। किसी के कहने में आकर यदि आप अपने को किसी स्नेह-बंधन से जबर्दस्ती छुड़ा लेंगे, तो निश्चित रूप से स्वयं को घायल कर लेंगे। आसक्ति रखने पर दुख कब होता है? आपके बच्चे को स्कूल से ला रहा रिक्शा आपकी आंखों के सामने उलट जाता है। तब आप क्या करेंगे? रिक्शे की ओर भागेंगे। गिरे हुए बच्चों में से पहले अपने बच्चे को उठा लेंगे। बच्चों के प्रति स्नेह रखने का आपका दावा हो, तो आप किसी भी बच्चे को उठा सकते थे। असल में, वहां बच्चों के प्रति स्नेह काम नहीं कर रहा था। यह अपना बच्चा है। उसके साथ निजी संबंध जोड़ने वाली भावना ने आपको संचालित किया था। सामने 'बच्चा' नहीं था, 'मैं, मेरा' के विचार आगे खड़े थे।

जब तक कोई व्यक्ति आपका मित्र रहता है, तब तक उससे स्नेह करते हैं। जब वह दुश्मन बन जाता है, तब उसके प्रति नफरत पैदा होती है। दरअसल, क्या आपने उस व्यक्ति विशेष से स्नेह किया था? नहीं। अपना मित्र होने के नाते आपने उससे स्नेह किया था। किसी भी रिश्ते में खुद को आगे रखते हुए ही लगाव बना था। इस तरह, तंग दायरे में अपने को समेटते वक्त आसक्ति रखें, तब दिक्कत होती है।

जब वायु और सुगंध एक-दूसरे पर पूर्ण आसक्त होकर एकाकार होती हैं, तब एक को दूसरे से अलग करके देखना संभव नहीं होता। किसी पर आपकी आसक्ति में यही गहनता रहनी चाहिए। आप उनके साथ यूं एकाकार हो जाएं कि दोनों को अलग करके देखा न जा सके। तब यह प्रश्न भी नहीं उठता कि उस पर आसक्ति रखें या न रखें। फिर काहे का दुख और कैसा दर्द? अनासक्त होकर सबसे अलग-थलग रहना स्वतंत्रता नहीं है, विकास नहीं है। सबको आत्मसात करते हुए विश्व-रूप लेकर चलना ही विकास है।

जब वायु और सुगंध एक-दूसरे पर पूर्ण आसक्त होकर एकाकार होती हैं, तब एक को दूसरे से अलग करके देखना संभव नहीं होता। किसी पर आपकी आसक्ति में यही गहनता रहनी चाहिए।

पसंद-नापसंद के नाम पर अपने दृष्टिकोण को संकुचित बना लेने से कितनी ही अनोखी बातें आपकी पसंद की सूची में स्थान नहीं पातीं। नतीजतन, इस जगत की पूर्णता का अनुभव करना आपके लिए कभी संभव नहीं होता। कोई भी जान-बूझकर मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं जीता। अनजाने में वे मूर्खता में फंस जाते हैं। विवेचन करके देखने की परिपक्वता आ जाए, तो उसके बाद कोई भी वैसे नहीं जिएगा।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

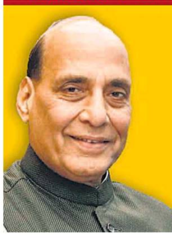

किसी भी सेना की शक्ति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि उन समर्पित अदृश्य लोगों से भी आती है, जो प्रत्येक परिस्थिति में उसके पीछे खड़े रहते हैं। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा उन शक्तियों में से एक है।

जनहित पर भारी पड़ता सियासी टकराव

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संसद है। यही वह मंच है, जहां सरकार अपनी नीतियां प्रस्तुत करती है, विपक्ष उनकी समीक्षा करता है और जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर विमर्श होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर संसदीय सत्र का कमोबेश एक ही हश्र होता रहा है- हंगामा, नारेबाजी, स्थगन और अंततः बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयकों का पारित हो जाना। यह स्थिति लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। वर्तमान मानसून सत्र भी इसी संकट का सामना कर रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा। परिणामस्वरूप, कई महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना और वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करना भी है। यदि विपक्ष केवल हंगामे तक सीमित रह जाए, तो वह अपनी सांविधानिक जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन नहीं करता। दूसरी ओर, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष की उचित मांगों को सुने और सदन में व्यापक चर्चा का अवसर दे। लोकतंत्र संवाद से चलता है, टकराव से नहीं। संसदीय कार्यवाही के आंकड़े स्वाभाविक ही चिंता बढ़ाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता कई सत्रों में हंगामे के कारण प्रभावित हुई है। संसदीय समितियों की रिपोर्टें बताती हैं कि कानूनों पर विस्तृत चर्चा और विशेषज्ञों की राय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाती हैं। इसलिए, जब विधेयक बिना पर्याप्त बहस के पारित होते हैं, तो कानूनों की गुणवत्ता व स्वीकार्यता, दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

विडंबना यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संकट, साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे विषय व्यापक चर्चा की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए संसद भेजती है, न कि केवल टकराव का प्रदर्शन देखने के लिए। आज सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक दलों के लिए सुर्खियां बटोरना पहले से आसान हो गया है, इससे यही जान पड़ता है कि सदन के भीतर बहस की अपेक्षा उनका जोर राजनीतिक संदेश देने पर अधिक रहता है। हालांकि, यह आलोचना केवल विपक्ष तक सीमित नहीं है; सरकार पर भी चर्चा से बचने या विधेयकों को शीघ्र पारित कराने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए, सभी को समझना होगा कि संसद में संवाद, बहस व सहमति की संस्कृति मजबूत करना आवश्यक है। तभी लोकतंत्र भी मजबूत होगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

संसदीय गतिरोध

मानसून सत्र में लोकहित के कई काम हुए

यह सच है कि संसद का मौजूदा मानसून सत्र राजनीतिक टकराव, विरोध-प्रदर्शनों और बार-बार की कार्यवाही-स्थगन के कारण सुर्खियों में है। और, पहली नजर में यही लगता है कि यह सत्र केवल राजनीतिक संघर्ष का मंच बनकर रह गया है, लेकिन गहराई से देखने पर नजर आता है कि इस टकराव के बीच भी संसद ने कई महत्वपूर्ण जनहितकारी काम किए हैं। यही लोकतंत्र की शक्ति है कि तीखी असहमति के बावजूद शासन और कानून-निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है।

मौजूदा मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार हुए और वे पारित किए गए। सबसे उल्लेखनीय सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 रहा, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना है। देश में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं, ऐसे में न्यायपालिका की क्षमता बढ़ाना सीधे तौर पर आम नागरिकों के हित से जुड़ा कदम है। इसी प्रकार, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल को लोकसभा ने पारित किया, जो औपनिवेशिक काल के पुराने कानून का स्थान लेगा। डिजिटल बैंकिंग और आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के दौर में पुराने कानूनों को बदलना समय की आवश्यकता है। यह सुधार आर्थिक मामलों में साक्ष्य संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े संशोधन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की पहल की है। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य छोटे उद्योगों को भुगतान में होने वाली देरी को कम करना और उनके लिए विवाद निपटान प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, इस क्षेत्र को मजबूत करना जनहित का विषय है।

मानसून सत्र की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखे मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे संसद के केंद्र में बने हुए हैं। संसद में बहस का अर्थ केवल कानून पारित करना नहीं होता; यह सरकार को जवाबदेह बनाने और जनता की चिंताओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की प्रक्रिया भी है। निस्संदेह, बार-बार के हंगामे और स्थगन आदर्श स्थिति नहीं हैं। जनता यह अपेक्षा करती है कि संसद में बहस हो, समाधान निकले और समय का सदुपयोग हो। फिर भी, यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक संघर्ष के बीच भी जनहित से जुड़े विधेयक आगे बढ़े।

स्वीकृति, टिप्पणीकार

एनर्जी ड्रिंक एहतियात से पिएं

स्कूली बच्चों और युवाओं को एनर्जी ड्रिंक खूब भा रहे हैं। कभी बाजार में इक्का-दुक्का एनर्जी ड्रिंक होते थे, आज इनके ढेरों विकल्प हैं। हालांकि, सेहत पर होने वाले नुकसान को देखते हुए देश के कई राज्यों में कुछ नियमों के साथ इनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। क्या है इन एनर्जी ड्रिंक में और इनसे मिलने वाली ताकत का सच क्या है, बता रही हैं अवंतिका सिंह

कोई लड़का झटपट दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो कोई तीन-तीन लोगों के साथ एक हाथ से टेबल टेनिस खेल ले रहा है। इतना ही नहीं, एक कैन पीते ही थकान गायब, दिमाग सुपरफास्ट और शरीर में जबरदस्त ऊर्जा... कुछ इस अंदाज में एनर्जी ड्रिंक युवाओं को परोसे जा रहे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। हालांकि, इन ड्रिंक से मिलने वाली यह ऊर्जा अस्थायी होती है और इसका बार-बार सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्या है एनर्जी ड्रिंक का फॉर्मूला

एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद जो आप किक महसूस करते हैं, वो इनमें मौजूद कैफीन, शुगर, टॉरिन व अन्य उत्तेजक पदार्थ और विटामिन बी के कॉम्बिनेशन के कारण होती है। इसमें भी मुख्य है कैफीन। जब आप थकते हैं, तो दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो थकान और नींद का एहसास कराता है। कैफीन दिमाग में जाकर एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है। इसके कारण दिमाग को थकान का सिग्नल नहीं मिलता और आप जागा हुआ व सतर्क महसूस करते हैं।

वाराणसी में बीएचयू यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विजय नाथ मिश्रा बताते हैं कि एनर्जी ड्रिंक की एक केन औसतन 200 एमएल की होती है। इसमें 50 से 70 मिलीग्राम कैफीन और बहुत अधिक चीनी या कृत्रिम मिठास होती है। हालांकि, कुछ ब्रांड्स शुगर फ्री का दावा भी करते हैं। एनर्जी ड्रिंक का अधिक सेवन जीवनशैली से जुड़े रोगों के साथ मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। नियमित शुगर और कैफीन सेवन से दिमाग की कोशिकाओं को इनकी आदत लग जाती है। कैफीन की अधिकता के कारण संवेदनशील लोगों में मिर्गी तक आ सकती है।' एनर्जी ड्रिंक पीने के लगभग 10 मिनट बाद कैफीन शरीर में असर दिखाना शुरू कर देता है। इससे हृदय गति और रक्तचाप कुछ बढ़ सकते हैं। 30-45 मिनट के भीतर इसका असर सबसे ज्यादा होता है, जिससे व्यक्ति सतर्क और ऊर्जावान महसूस करता है। करीब एक घंटे बाद यह असर कम होने लगता है। यदि ड्रिंक में चीनी अधिक है, तो पहले रक्त में शुगर तेजी से बढ़ती है और फिर इंसुलिन के कारण जल्दी गिर जाती है। शुगर तेजी से कम होने से थकान, सुस्ती व कमजोरी महसूस होती है। इसे ही 'शुगर क्रैश' कहते हैं।

एनर्जी ड्रिंक बनाम स्पोर्ट्स ड्रिंक

स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक दोनों ही बाजार में लिक्विड एनर्जी या रिफ्रेशमेंट के नाम पर बेचे जाते हैं। इनका शरीर पर काम करने का तरीका और इनमें मौजूद सामग्रियां पूरी तरह अलग हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक का मकसद शारीरिक मेहनत, खेल-कूद या भारी कसरत के बाद शरीर में हुई पानी और जरूरी मिनरल की कमी को पूरा करना होता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो शरीर से पानी के साथ-साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स इसी कमी को दूर कर शरीर को तुरंत रिहाइड्रेट करते हैं। इनमें बहुत हल्की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट (शुगर) होता है, जो थकी हुई मांसपेशियों को तुरंत ऊर्जा देता है। ये ड्रिंक आमतौर पर पूरी तरह कैफीन-मुक्त होते हैं, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

एनर्जी ड्रिंक का रिहाइड्रेशन या खेल-कूद से कोई लेना-देना नहीं होता। इनका एकमात्र मकसद इंसान को मानसिक रूप से सतर्क करना और सुस्ती को तुरंत दूर करना होता है। एनर्जी ड्रिंक सिर्फ दिमाग को भ्रम में डालते हैं। हां, इनमें जो शुगर होती है, उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है, वो भी कुछ देर बाद क्रैश हो जाती है। ये बॉडी को ताकतवर नहीं बनाते। ये बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते, बल्कि ज्यादातर मामलों में शरीर में पानी की कमी कर देते हैं। इनका शौक लत बन सकता है।

लखनऊ के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉ.अनिल कुमार बताते हैं, 'बच्चों को एनर्जी ड्रिंक के सेवन से बचाना जरूरी है। शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना है, तो पौष्टिक आहार सबसे जरूरी है। स्पोर्ट्स ड्रिंक भी सामान्य लोगों के लिए रोजाना पीने की चीज नहीं हैं। इनका उपयोग लंबी अवधि के कठिन व्यायाम के दौरान या बाद में ही उचित माना जाता है।'

क्या कहते हैं आंकड़े

अमेरिका में पेय पदार्थों की श्रेणी में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री अब दूसरे स्थान पर है और भारत भी उसी राह पर है। ईरान युद्ध में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 38 दिनों के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने 20 लाख एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल किया। एनर्जी ड्रिंक रेड बुल ने साल 2025 में दुनिया भर में लगभग 14 बिलियन (1400 करोड़) कैन बेचे, जबकि साल 2011 में यह आंकड़ा सिर्फ 4 बिलियन कैन के आसपास था।

मोरडोर इंटेलिजेंस के मुताबिक, भारतीय एनर्जी ड्रिंक बाजार का आकार साल 2026 में 0.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। 2.25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ते हुए साल 2031 तक 0.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

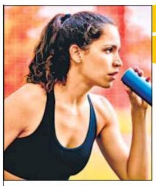

व्यायाम के दौरान बिल्कुल भी न पिएं

अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की हाइड्रेशन गाइडलाइंस के अनुसार व्यायाम के समय एनर्जी ड्रिंक पीने से बचना चाहिए। व्यायाम के दौरान उत्प्रेरक पेय पदार्थ पीना शरीर में पानी की कमी और धमनियों पर तनाव पैदा कर सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स की अधिकता पानी की पूर्ति करने के बजाय शरीर में इसकी कमी कर सकती है। खासकर गर्मियों में इनके सेवन से बचें।

कहां-कहां लगाई गई इन पर रोक

राजस्थान: हाल में आठ लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री और प्रचार पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध दुकानों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लागू है।
महाराष्ट्र: सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में कैफीन की अधिकता वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। इनके नुकसान के बारे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा।
पंजाब: 2025 में पंजाब पहला राज्य बना, जहां बच्चों में अधिक कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक बेचने की मनाही है। इन्हें स्कूल कैंटीन और आसपास की जगहों पर बेचना पूरी तरह मना है।
कंबोडिया: स्कूलों के भीतर व आसपास एनर्जी ड्रिंक्स के सेवन और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
पोलैंड: 2024 से 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को एनर्जी ड्रिंक्स बेचे जाने पर प्रतिबंध है।

सावधानी बरतें

- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं
- हाई बीपी के मरीज, हृदय रोगी और मिर्गी के मरीज
- घबराहट और बेचैनी से जूझ रहे लोग

देसी विकल्प आजमाएं

अगर तुरंत एनर्जी चाहिए, तो नारियल पानी, नीबू पानी व छाछ पिएं। संतरा, अनार व अनन्नास खाएं या उनका जूस पिएं। गुड़ और पुदीने का शरबत या सत्तू के शरबत से भी तुरंत ऊर्जा मिलती है। साथ ही नियमित रूप से अच्छे पोषण, व्यायाम और नींद पर भी ध्यान दें, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे।

अधिक सेवन से शरीर पर होने वाला असर

1. दिल
एनर्जी ड्रिंक में मौजूद कैफीन व उत्तेजक तत्व कुछ लोगों में दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ज्यादा सेवन से हृदय पर दबाव बढ़ने का खतरा रहता है।

2. किडनी
कैफीन व उत्तेजक पदार्थों के ज्यादा सेवन से पेशाब अधिक आता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम कर सकता है।

3. दिमाग
एनर्जी ड्रिंक्स कुछ समय के लिए ही सतर्कता बढ़ाते हैं। इनकी लत पड़ने पर घबराहट, बेचैनी, हाथ कांपना, चिड़चिड़ापन व अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है।

4. लिवर
एनर्जी ड्रिंक में मौजूद अधिक शुगर का नियमित सेवन, लिवर में फैट जमा होने के खतरे को बढ़ा सकता है। इस कारण फैटी लिवर की समस्या हो सकती है।

5. पाचन तंत्र
ये पेय अम्लीय (एसिडिक) होते हैं। ज्यादा या खाली पेट इनके सेवन करने से एसिडिटी, पेट में जलन और मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

6. दांत
इनमें मौजूद शुगर और एसिड दांतों की ऊपरी परत (इनेमल) को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे सड़न और संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

(लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ.भुवन चंद्र तिवारी के अनुसार)

सवाल-जवाब

अपने पैरों पर ज्यादा चर्बी न चढ़ने दें

डॉ. नीरज निश्चल
प्रोफेसर (मेडिसिन), एम्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली

सवाल : मेरी उम्र 38 साल है। पैरों व जांघों में लगातार चर्बी बढ़ रही है और भारीपन रहता है। वजन कम करने के बावजूद पैरों का आकार देखने में अजीब लगता है। क्या यह लिपेडेमा है? क्या यह गंभीर समस्या है? मैं क्या करूं?

जवाब : आपके बताए गए लक्षण लिपेडेमा की ओर संकेत कर सकते हैं, पर इन्हीं के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

लिपेडेमा क्या है?
यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर के निचले हिस्से खासकर जांघ और पैरों में असामान्य रूप से वसा जमा होने लगती है। ऐसा महिलाओं में अधिक होता है। अक्सर हार्मोनल बदलाव (किशोरावस्था, गर्भावस्था या मेनोपॉज) के दौरान ऐसा अधिक होता है।

क्या यह गंभीर बीमारी है?
लिपेडेमा आमतौर पर जानलेवा नहीं होती, पर समय पर पहचान और देखभाल न हो तो दर्द, चलने-फिरने में कठिनाई और कभी-कभी लसीका (लिम्फ) की समस्या भी जुड़ सकती है, इसलिए शुरुआती अवस्था में विशेषज्ञ से परामर्श लेना बेहतर रहता है।

यदि पैरों में सूजन केवल एक तरफ और अचानक बढ़ रही है, त्वचा लाल व गर्म है या तेज दर्द के साथ सांस फूल रही है, तो तुरंत जांच कराएं। यह किसी अन्य समस्या का संकेत हो सकता है। बेहतर है कि आप किसी विशेषज्ञ से मिलकर ढंग से जांच कराएं।

अपने स्तर पर क्या करें?
संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जारी रखें। इससे वजन नियंत्रित रहेगा, भले ही लिपेडेमा की चर्बी पूरी तरह कम न हो। रोजाना पैदल चलें। तैराकी या साइकिल चलाना जैसे व्यायाम लाभदायक हो सकते हैं। अगर डॉक्टर सलाह दें, तो कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से भारीपन और सूजन में राहत मिल सकती है। लंबे समय तक खड़े रहने या बैठे रहने से बचें। पैरों को बीच-बीच में आराम दें।

भेजें अपने सवाल
सेहत से जुड़े सवाल tanmanhindustan@gmail.com पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं- तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, 201301

---

35 के बाद खुद को कैसे रखें फिट

आज पहले से कहीं अधिक 35 से ऊपर की आयु वाले खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए हैं। खिलाड़ियों की तरह बढ़ती उम्र में फिट और सही शेप में कैसे रहा जाए, जानें श्रेणिक अवलानी से

हाल में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान 39 साल के लियोनेल मेसी फुटबॉल के मैदान पर किसी युवा की तरह दौड़ते दिखे। 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन में एक और ग्रैंड स्लैम सेमी-फाइनल खेला। 44 वर्षीय सेरेना विलियम्स की प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी देखने को मिली। वहीं भारत के एम.एस. धोनी 45 वर्ष के हो चुके हैं और अब भी आईपीएल का हिस्सा हैं।

महामारी के दौर के बाद आज पहले से कहीं अधिक 35 से अधिक आयु वाले खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए हैं। लोगों में व्यायाम, पोषण और रिकवरी के बारे में जागरूकता बढ़ी है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी काफी तरक्की हुई है।

बढ़ती उम्र के बदलाव

35 की उम्र के बाद वजन बढ़ने और शरीर की शेप में बदलाव के संकेत नजर आने लगते हैं। जोड़ों में दर्द, हार्मोनल बदलाव, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, हाई बीपी और नींद से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगती हैं। मांसपेशियों की बनावट और लचीलेपन में भी बदलाव आते हैं।

मुंबई के केडीए अस्पताल में स्पोर्ट्स साइंस व रिहैबिलिटेशन के प्रमुख वैभव डागा कहते हैं, 'इस समय शरीर में तेज मूवमेंट देने वाले 'फास्ट-ट्विच मसल फाइबर्स' स्वाभाविक रूप से कम होने लगते हैं, जिससे शरीर की गति धीमी होने लगती हैं।

खिलाड़ी जिस उच्च स्तर के प्रदर्शन के आदी होते हैं, उसे बनाए रखने के लिए वे अपनी ट्रेनिंग, रिकवरी व पोषण में बदलाव करते हैं। वे भारी वजन उठाने (जैसे भारी स्क्वैट्स) के बजाय टेंडन्स की सुरक्षा के लिए जॉइंट मोबिलिटी व कोर स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं। सूजनरोधी आहार और आंतों की अच्छी सेहत पर ध्यान देते हैं, जिससे टिश्यू की मरम्मत में तेजी आती है। अंत में, रिकवरी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। खिलाड़ी कुदरती रूप से ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाने व टॉक्सिन्स साफ करने के लिए क्रायोथेरेपी, हाइपरबेरिक चेम्बर्स और स्ट्रिक्ट स्लीप ट्रैकिंग जैसी नई तकनीकों का सहारा लेते हैं।

mint

मानसिकता की बड़ी भूमिका

बढ़ती उम्र के साथ सक्रिय व फिट रहना चाहते हैं, तो सोच भी बदलें। धोनी, विलियम्स व रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी पीक परफॉर्मेंस के बजाय लंबी उम्र तक फिट रहने पर ध्यान देते हैं। कल्ट फिट के फिटनेस एक्सपर्ट ध्रुव शिवकुमार कहते हैं, 'अपने शरीर को समझना जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी वर्क, स्ट्रेचिंग, अच्छा पोषण, गुणवत्तापूर्ण नींद और पर्याप्त रिकवरी वाली संतुलित दिनचर्या ढलती उम्र में स्वस्थ रखने में मदद करती है। साथ ही उन गतिविधियों को चुनें, जिन्हें करना अच्छा लगता है, इससे व्यायाम में निरंतरता बनी रहती है।

खांसी की वजह पेट तो नहीं

अगर आपको लंबे समय से खांसी, गले में खराश, आवाज बैठना या बार-बार गला साफ करने की समस्या है, तो इसकी वजह सिर्फ सर्दी या एलर्जी ही नहीं, आंतों की खराब सेहत भी हो सकती है।

फ्लोरिडा के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सलहाब के अनुसार, ये लक्षण लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स या साइलेंट रिफ्लक्स की ओर इशारा कर सकते हैं। कई बार पेट का एसिड भोजन नली से होकर गले व वॉइस बॉक्स तक पहुंच जाता है, जिससे वहां जलन होती है। सामान्य एसिड रिफ्लक्स की तरह इसमें हर बार सीने में जलन नहीं होती, इसलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते।

अच्छी आदत डालें

- भोजन के साथ ज्यादा पानी पीने से बचें। पानी थोड़ा-थोड़ा करके पिएं। भोजन के लगभग 30 मिनट बाद ही अधिक मात्रा में पानी लें।
- कार्बोनेटेड या फिजी ड्रिंक्स न पिएं, इससे एसिड बढ़ता है।
- भोजन के बाद शुगर-फ्री च्यूइंग गम चबाने से लार बढ़ती है। इससे एसिड को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है।
- रात में बायीं करवट सोएं। बायीं करवट सोने से रात में होने वाला रिफ्लक्स कम हो जाता है।
- डॉ. सलहाब के अनुसार, सोडियम एल्जिनेट सस्पेंशन व कुछ अन्य सिरप भी आते हैं, जो एसिड को वापस गले तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे लगातार खांसी, गला साफ करने की आदत, आवाज बैठने और गले में गांठ जैसा महसूस होने जैसे लक्षणों में सुधार हो सकता है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष: धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। वाणी में मधुरता रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आय में बढ़ोतरी होगी।

वृष: मन प्रसन्न रहेगा, फिर भी बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, पर कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। आय भी बढ़ेगी।

मिथुन: आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। वाहन के रख-रखाव पर खर्च बढ़ेंगे।

कर्क: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पर मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी।

सिंह: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। पढ़ाई में बाधा आ सकती है। सचेत रहें। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या: लंबे समय के बाद किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, पर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकतीहै।

तुला: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। भागदौड़ बढ़ेगी।

वृश्चिक: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। बेकार के वाद-विवाद से बचें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी।

धनु: संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। कारोबार में बदलाव हो सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। खर्च भी बढ़ेंगे।

मकर: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, पर धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार का विस्तार हो सकता है, परंतु किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा।

कुंभ: मन अशांत रहेगा। मन में बुरे विचारों से बचें। माता व जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। वाहन के रख-रखाव पर खर्च बढ़ेंगे।

मीन: आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। भवन सुख बढ़ेगा।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

07 अगस्त, शुक्रवार, **शक संवत्** : 16 श्रावण (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 23 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 23 सफर, 1448, **विक्रमी संवत्**: श्रावण कृष्ण नवमी तिथि सायं 04.38 बजे तक पश्चात दशमी तिथि, कृतिका नक्षत्र सायं 06.44 मिनट तक पश्चात रोहिणी नक्षत्र, गर करण, चंद्रमा वृष राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 03.19 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

बेटी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, तो वास्तु के ये नियम ध्यान रखें-

- कन्या संतान के लिए वायव्य कोण अच्छा माना जाता है, पर यह दिशा पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं होती। पढ़ाई के लिए उत्तर पूर्व या पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थान बनाना सही रहता है। अगर बेटी के लिए इस दिशा में कमरा बनवाना संभव नहीं हो, तो उनके कमरे में ही पढ़ने का स्थान इस दिशा में रखना सही रहेगा।
- कमरे में उत्तर दिशा में एक तोते का चित्र लगाएं।
- बेटी के कमरे की पूर्व दिशा में अशोक स्तंभ का चित्र लगाएं।

वर्ग पहेली : 8413

■	1	■	2	3		4		5
6			■		■		■	
■		■	7		■	8		
9		■		■	10	■	■	
	■	11					■	
	■	■		■		■	12	
13		14	■	15		■		■
	■		■		■	16		
17						■		■

बाएं से दाएं
2. युक्ति सफल न होना; वश न चलना; स्वार्थ सिद्ध न होना (2,1,3)
6. पर्पट; दालों के आटे से बनी पतली मसालेदार चपाती जिसे भून या तल कर खाते हैं (3)
7. अपर्याप्त; अल्प; छोटा; तनिक (2)
8. अत्यल्प; अल्प; कम; जरा; थोड़ा (3)
9. अंदाज; ढंग; तर्ज; हावभाव; नखरा (2)
11. जिसमें कमानी हो; नवचंद्राकार (5)
12. दोस्त; मीत; सखा (2)
13. थपथपाहट; थाप; धीरे-धीरे ठोंकने की क्रिया (3)
15. ठौर; रहने की जगह; निवास का ठिकाना (2)
16. शरीर को सुगठित करने वाला नियमित श्रम; कसरत; वर्जिश (3)
17. आकलन करना; गिनती करना; हिसाब करना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. परदाहीन; बिना परदे के (4)
3. रास; बागडोर (3)
4. अंकशास्त्र; हिसाब; गिना हुआ; जोड़ा हुआ (3)
5. चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज; नामजदगी पत्र (4,2)
7. करिश्मा; चमत्कार (4)
9. जुदा; तटस्थ; दूरी पर; नितांत एकाकी (3,3)
10. विशाल हृदयता; दानशीलता (4)
12. बकरी का बोलना; गिड़गिड़ाना (4)
14. बोलना; प्रकट करना; सुनाना; आदेश (3)
15. प्रस्तर; ओला; रत्न; कठोर पदार्थ (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8412

1 स	■	2 घ	■	3 स	4 ह	ज	हो	5 ना
6 ह्रा	स्य	र	स	■	ला	■	■	च
रा	■	च	■	7 स	ह	म	जा	ना
■	8 नी	ल	क	म	ल	■	■	च
9 सी	■	ना	■	झ	■	10 दू	■	न्न
ना	■	■	11 अ	दा	क	र	ना	■
12 ता	क	त	व	र	■	क	■	13 स
न	■	■	स	■	14 प	र	स्प	र
15 ना	श	क	र	ना	■	ना	■	स

सुडोकू : 8367

*कठिन

4		2						
			2		1			9
	9	6	3				4	
		7					9	4
		5				8		
9	6					3		
	1				3	4	8	
2			6		7			
						9		2

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8366

9	8	2	6	5	3	4	7	1
6	4	7	2	9	1	8	5	3
3	1	5	8	7	4	9	2	6
5	7	6	4	8	2	1	3	9
1	2	9	5	3	6	7	8	4
8	3	4	9	1	7	5	6	2
2	9	8	1	6	5	3	4	7
4	5	3	7	2	9	6	1	8
7	6	1	3	4	8	2	9	5

कल्पमेधा

जीवन एक साइकिल चलाने की तरह है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा।

– अल्बर्ट आइंस्टीन

संवाद का रास्ता

एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार होता है। सच यह है कि असहमति और उसकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति से ही लोकतंत्र जीवन पाता है और मजबूत होता है। मगर कुछ मसलों पर सरकारी तंत्र का रुख कई बार इस हद तक उदासीन और उपेक्षापूर्ण हो जाता है कि आम लोगों को अपनी बात दर्ज करने के लिए आंदोलन एक जरूरी विकल्प लगने लगता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर सरकार ने नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर उभरे विरोध के बाद समय रहते आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता अपनाया होता, तो क्या स्थिति को संभाला जा सकता था! आमतौर पर सरकार की ओर से टालमटोल के रवैये की वजह से ही संवादहीनता की स्थिति पैदा होती है और इसके बाद कभी-कभी आंदोलन की दिशा भी नियंत्रित नहीं रह पाती। हैरानी की बात यह है कि मतविरोध या सवालों के सामने आने पर सरकार अपनी ओर से बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाती, लेकिन जब लोग सड़क पर उतर जाते हैं, तब कथित हिंसा पर काबू पाने के नाम पर पुलिस के जरिए बलप्रयोग का सहारा लेने से भी नहीं हिचकती।

दरअसल, नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर विद्यार्थियों के आंदोलन के दौरान जो भी अराजकता और पुलिस की कार्रवाई देखने में आई, वह सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवादहीनता का ही नतीजा थी। इसी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की कि अगर कुछ गुमराह लोग पत्थरबाजी भी करते हैं, तो भी युवाओं को शांत करने और उनसे बातचीत करने की जरूरत है। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जिस तरह लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, उस पर तीखे सवाल उठे। इसके बाद पुलिस की ओर से यह सफाई दी गई कि आंदोलनकारियों की भीड़ अराजक और हिंसक हो गई थी। सवाल है कि क्या सिर्फ इस दलील से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, बेरहमी और यहां तक कि कई छात्राओं के प्रति भी अफसोसनाक बर्ताव को उचित ठहराया जा सकता है! खबरें यहां तक आईं कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर 'पैलेट गन' भी चलाई गई, जिसका उपयोग हर लिहाज से गलत था।

अव्वल तो इस स्थिति से बचने के लिए हर तरह के वैकल्पिक उपायों का सहारा लेने की जरूरत थी, लेकिन क्या यह नौबत सिर्फ संवाद की उपेक्षा करने या इसके प्रति उदासीन होने की वजह से ही नहीं आई। पुलिस की सख्ती सवालों के घेरे में आने के बाद मुद्दा जब राजनीतिक शक्ल अख्तियार करने लगा और विपक्षी दलों ने भी इस मसले पर आवाज उठाई, तब विद्यार्थियों की मांग के मुताबिक आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और आंदोलनकारियों से बातचीत भी की गई। संवाद के जरिए हल तक पहुंचने की कोशिश करने का जो काम सरकार ने स्थिति बिगड़ने के बाद किया, क्या वही वह प्रदर्शन के पहले नहीं कर सकती थी? क्या इसी अपरिपक्वता और समय पर बातचीत के तकाजे की अनदेखी का ही नतीजा नहीं था कि प्रदर्शनकारियों ने 'संसद मार्च' का आह्वान किया और फिर एक अप्रिय और दुखद स्थिति पैदा हुई? इस लिहाज से देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह संवाद को तरजीह देने पर जोर दिया है, वह दरअसल सबसे शुरुआती और लोकतांत्रिक तकाजा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसे एक सबक के तौर पर देखेगी।

अंधविश्वास की जंजीरें

जिस दौर में विज्ञान की उपलब्धियों के सहारे आम जनजीवन की समूची बुनियाद बदलने की एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें महज अंधविश्वास की वजह से किसी की जान चली जाए या लोग अंधविश्वास की जड़ता में डूबे हों, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीते मंगलवार को मानसिक रूप से बीमार एक महिला की मौत इसका उदाहरण है कि हम लाख अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का हवाला देते रहें, समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी अंधविश्वास की कूपमंडूकताओं में डूबा हुआ है और इसके बेहद तकलीफदेह खमियाजे भी भुगत रहा है। हैरान करने वाली घटना में महिला को इलाज के नाम पर दस दिनों तक खंभे से बांध कर रखा गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उपचार के लिए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगर महिला के परिजनों या वहां के लोगों के बीच बीमारी और इलाज की सामान्य जानकारी भी होती, तो वे महिला को उपचार के लिए किसी चिकित्सक के पास ले जाते और उसकी जान बच सकती थी।

आज भी झाड़-फूंक के सहारे इलाज का अंधविश्वास कायम है, तो आखिर इसकी जड़ें कहां मौजूद हैं? आम लोगों की अमूमन हर गतिविधि को किसी तकनीक पर निर्भर करने और डिजिटल दुनिया के दौर में भी लोगों के ज्ञान का दायरा इतना सिमटा हुआ क्यों है कि वे किसी बीमारी का इलाज झाड़-फूंक या तंत्र-मंत्र में ढूंढ़ते हैं? कई बार मानसिक रोगी का मनोचिकित्सक से उपचार नहीं कराया जाता और परिवार के सदस्य ही उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। समाज से अधिक यह सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि देश में मानसिक रोग के उपचार के लिए पर्याप्त अस्पताल और चिकित्सक क्यों नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ज्यादातर लोगों का जागरूक नहीं होना भी एक बड़ी चुनौती है। हैरानी की बात यह भी है कि तेज रफ्तार आधुनिक संचार के इस दौर में सरकार जहां अपनी किसी बात या प्रशासनिक फैसले को लागू करने वाले तंत्र को बिना किसी देरी के दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचा देती है, वहां वह अंधविश्वास की जकड़न से घिरे लोगों के बीच वैज्ञानिक चेतना की रोशनी क्यों नहीं पहुंचाती?

बदलाव की राह पर नेपाल की विदेश नीति

अब जब नेपाल के नए प्रधानमंत्री का भारत दौरा लगभग तय है, तो अमेरिका और चीन का चौकन्ना होना स्वाभाविक है। राजनीतिक विश्लेषकों की दृष्टि में यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है।

यशोदा श्रीवास्तव

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की विदेश यात्राओं की वरीयता को लेकर काठमांडो के राजनीतिक गलियारों में चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया है, क्योंकि उनकी भारत यात्रा पर अब मुहर लग गई है। दरअसल, भारत ने बालेन शाह को यहां आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। नेपाल की राजनीति में भारत और खासकर बालेन शाह की विदेश नीति को लेकर इसे बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहे चीन और अमेरिका बालेन की प्रथम विदेश यात्रा पर टकटकी लगाए हुए थे, वे उनकी विदेश यात्रा में अपने-अपने देश को प्राथमिकता में मान रहे थे। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह की सरकार चलाने की कार्यशैली कुछ ऐसी थी कि उन्हें और उनकी विदेश नीति को समझ पाना मुश्किल था। अब जब भारत का उनका दौरा लगभग तय हो गया है, तो अमेरिका और चीन का चौकन्ना होना स्वाभाविक है। राजनीतिक विश्लेषकों की दृष्टि में यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है।

प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही यह संदेश दिया था कि विदेशी राजदूतों और राजनयिकों की प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीधी पहुंच समाप्त की जाएगी और किसी भी विदेशी प्रतिनिधि से निजी मुलाकात नहीं की जाएगी। मगर अब उन्होंने अपनी शुरुआती नीति में बदलाव करते हुए करीबी सलाहकारों के माध्यम से भारत और चीन से सीधे संपर्क स्थापित करने की पहल शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपने करीबी सलाहकारों तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं खासकर पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने और विदेश मंत्री शिशिर खनाल से चर्चा के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत को प्राथमिकता दी है। दरअसल, प्रधानमंत्री बालेन शाह के प्रमुख सलाहकार कुमार व्यंजनकार की जुलाई के पहले सप्ताह में नई दिल्ली की यात्रा के बाद ही उनकी भारत यात्रा के कार्यक्रम में तेजी आई। यह सब इतना गोपनीय रखा गया कि इसकी भनक नेपाल के विदेश मंत्रालय तक को नहीं लगने दी गई। नेपाल के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेशक बालेन शाह की भारत यात्रा की रूपरेखा गोपनीय रखी गई, लेकिन इसकी जानकारी पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने को जरूर रही होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आमंत्रण पर भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर गए थे।

नेपाल में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, तो वहां के नए प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा की प्राथमिकता पर भारत, चीन और अब अमेरिका की नजर जरूर रहती है। नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगातार सक्रियता बढ़ा रहे ये तीनों देश बालेन शाह की अपने-अपने देश की यात्रा को लेकर सक्रिय थे। पिछले दिनों अमेरिका और चीन के राजनयिक तथा शीर्ष नौकरशाह काठमांडो पहुंचे थे, लेकिन बालेन शाह की मुलाकात किसी से नहीं हुई। उन्होंने नेपाल की आंतरिक और बाह्य समस्याओं के समाधान में व्यस्तता के बीच विदेशी प्रतिनिधियों से मिलना जरूरी नहीं समझा। बालेन शाह की भारत यात्रा की पुष्टि के बाद नेपाल की विदेश नीति में बदलाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री

बालेन शाह के भारत दौरे के पीछे जो प्रमुख कारण हो सकता है, वह यह कि भारतीय मीडिया में हाल के दिनों में उनकी सरकार को लेकर लगातार आलोचनात्मक खबरें आई हैं। कुछ रिपोर्टों में सरकार की लोकप्रियता घटने और उसके अधिक समय तक न टिक पाने के दावे किए गए, जिससे सरकार के भीतर नई कूटनीतिक पहल की आवश्यकता महसूस की गई।

> **नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालने के बाद जो सख्त रुख अख्तियार किया था, अब उसमें कई बदलाव देखे जा रहे हैं। केवल विदेश नीति ही नहीं, बल्कि आर्थिक सुधारों पर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब वे अपनी शुरुआती नीतियों से हटकर अलग रास्ता अपनाने, हर मामले में सक्रिय रहने तथा प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की कूटनीति में यह बदलाव आर्थिक समृद्धि, द्विपक्षीय स्पष्टता और संस्थागत संबंधों पर केंद्रित है। नए नेतृत्व के तहत नेपाल अपनी विदेश नीति को पुराने तौर-तरीकों से बदलकर राष्ट्रीय हितों और विकास पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा है।**

इसके अलावा नेपाल की मौजूदा सरकार पर घरेलू स्तर पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। भूमिहीनों के पुनर्वास, पासपोर्ट छपाई विवाद, गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बालेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर संतुलन बनाने की कोशिश में हैं, जिसकी शुरुआत के क्रम में भारत यात्रा भी शामिल है। उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य दो तरफा है। दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनका समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। भारत और नेपाल के बीच संबंध चूंकि मैत्रीपूर्ण हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है, भौगोलिक दृष्टि से भी नेपाल भारत के बेहद करीब है, ऐसे में दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि वे एक-दूसरे से दूरी बनाकर रहें। दोनों देशों के बीच अभी जिन ताजा मसलों पर चर्चा की संभावना है, उसमें सीमा विवाद, हवाई मार्ग और जलविद्युत परियोजनाएं प्रमुख हैं।

द्विपक्षीय बातचीत में सीमा विवाद पर उत्तराखंड का भू-क्षेत्र लिपुलेख लिंपियाधुरा और काला पानी का मुद्दा प्रमुख हो सकता है। मानसरोवर मार्ग से भारत-चीन के बीच व्यापारिक समझौते पर नेपाल को आपत्ति है। नेपाल के पश्चिमी हवाई क्षेत्र पर भी बातचीत संभव है, जहां से पोखरा और भारतीय सीमा से सटे भैरहवा हवाई अड्डे के लिए नए रूट पर बात हो सकती है। जल विद्युत परियोजनाओं और नेपाल से बिजली निर्यात के समझौते की समीक्षा भी संभव है। प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह ने जो सख्त रुख अख्तियार किया था, अब उसमें कई बदलाव देखे जा रहे हैं। केवल विदेश नीति ही नहीं, बल्कि आर्थिक सुधारों पर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। देखने में आया है कि कई मामलों में वित्त मंत्रालय को दरकिनार कर बालेन शाह सीधे निजी क्षेत्र से संवाद कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने उद्योगपतियों, निर्माण व्यवसायियों, ऊर्जा उत्पादकों, होटल व्यवसायियों, महिला उद्यमियों, जूता उद्योग, शेयर बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों और प्रतिभूति बोर्ड के साथ लगातार बैठकें की हैं।

शेयर बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान बालेन शाह ने स्वीकार किया कि सरकार की नीतियों के कारण निवेशकों के भरोसे में कमी आई है। प्रधानमंत्री पहले अपने निर्णय को ही अंतिम और बेहतर मान रहे थे, मगर अब उनके फैसलों में भी बदलाव देखने को मिला है। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र और अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर समसामयिक राजनीतिक मसलों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा, निजी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों पर लगाए गए तीन फीसद समता कर को लेकर व्यापक विरोध के बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इसे वापस लेने की घोषणा की और बाद में मंत्रिपरिषद ने भी इस निर्णय को औपचारिक मंजूरी दे दी। इन सभी घटनाक्रमों के बीच नेपाल की राजनीति में यह चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह अब अपनी शुरुआती नीतियों से हटकर अलग रास्ता अपनाने, हर मामले में सक्रिय रहने तथा प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की कूटनीति में यह बदलाव आर्थिक समृद्धि, द्विपक्षीय स्पष्टता और संस्थागत संबंधों पर केंद्रित है। नए नेतृत्व के तहत नेपाल अपनी विदेश नीति को पुराने तौर-तरीकों से बदलकर राष्ट्रीय हितों और विकास पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा है।

सहजता का सरोकार

मुकेश पोपली

किसी दौर में हम सुबह उठकर अपने घर के बड़े-बुजुर्गों के पांव छूते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए रोजमर्रा की सामान्य बातचीत के दौरान परिवार और समाज की स्थिति से संबंधित ज्ञान बटोरते थे। बुजुर्गों के अनुभव सुनते हुए हम अपनी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते थे और साथ ही उनकी आज्ञा को भी शिरोधार्य करते थे। इसी प्रकार, स्कूल और कालेज में भी गुरुजन हमारे ही हित के बारे में सोचते थे, भले ही उनकी डांट-फटकार, सवाल पूछने आदि सख्ती हमें तब प्रताड़ना या उपेक्षा लगती रही हो। उनके पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सिखाना नहीं होता था, बल्कि वे हमारे सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते थे। समाज में हम आदर प्राप्त कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श भी बन सकें, वे अपने स्तर पर हमें ऐसे व्यक्तित्त्व में ढालने का प्रयास करते थे। हम समाज के विकास के लिए समाज से जुड़े किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा किया करते थे, जिनसे हमारे व्यक्तित्व के विकास का रास्ता भी खुलता था। हम ऐसी गोष्ठियों और सभाओं में भी अवश्य जाते थे, जहां सामाजिक, शारीरिक और बौद्धिक विषयों की चर्चा हुआ करती थी। अपने कार्य के दौरान या नौकरी करते हुए भी हम एक आदर्श का पालन करते थे और अनुभवी लोगों से उनके अनुभव को आधार बनाते थे।

मगर आज वक्त बदल गया है और इस बदले हुए वक्त में पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी वाले बच्चों की भी अपेक्षाएं आसमान पर हैं। बल्कि कहा जाना चाहिए दो-तीन या चार दशक पहले जो इच्छाएं-अपेक्षाएं जमीनी हकीकतों से दो-चार थीं, वे अब नए स्वरूप में पूरी तीव्रता से उड़ान भर रही हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग स्वयं को परम ज्ञानी मानते हैं। बाहर से वे भले ही विद्वान बने रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनके भीतर झांक कर देखा जाए, तो वहां खोखलापन नजर आता है। दरअसल, उनमें वह अदब ही नहीं होता, जो उनकी शिक्षा, व्यवहार कुशलता और विनम्रता के लिए आवश्यक है। इसमें अगर उनकी कमी को कोई इंगित करता है, तो वे सारा दोष अपने गुरुओं पर ही डाल देते हैं और यह कहते हुए बचकर निकलने का प्रयास करते हैं कि हमें यही सिखाया गया है। किसी भी गुरु या बुजुर्ग से ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त शिष्य का समर्पण भाव है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें उनकी ही समर्पण भावना में कमी रही है। वह स्वयं अपना आकलन नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर स्वार्थ पनप रहा होता है। जहां उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, उन्हें वही अपने हितैषी नजर आते हैं। वे उन तथाकथित परोपकारियों को ही अपना गुरु मान लेते हैं।

कहा गया है कि चाहे जितने ही वेद और पुराण पढ़ लिए जाएं, लेकिन उनका गूढ़ अर्थ समझाने वाला कोई गुरु तो होना ही चाहिए और उसे सीखने के लिए खुद को भी निस्वार्थ भाव से तैयार करना चाहिए। जैसे सूरज और चंद्रमा अपने मार्ग पर हमेशा प्रशस्त रहते हैं, क्योंकि उन दोनों में परोपकार की भावना विद्यमान है, वह स्वार्थी नहीं हैं। इसी प्रकार हवा और पानी का कोई तोड़ नहीं है और वे हमारा जीवन स्वस्थ बनाने में लगे रहते हैं। इसी तरह ज्ञान और शिष्टाचार का सबक हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आधा अधूरा ज्ञान तो वैसे भी खतरनाक होता है। जब हम यह सोच लेते हैं कि अब हम ज्ञानी हो गए हैं, उसी दिन हमारी बुद्धि के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवनपर्यंत बनी रहनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार शिष्टाचार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए ऐसी औषधि है, जिसका असर हमारे भावी जीवन पर भी बना रहता है। शिष्टाचार की कोई एक श्रेणी नहीं है, उसमें अनेक प्रकार का मिश्रण होता है। हमारे घर, विद्यालय, समाज, कार्यालय आदि विभिन्न क्षेत्रों में, जिनका संबंध हमसे है। हमसे शिष्टाचार की आशा की जाती है। प्रत्येक स्थान पर इसके अलग नियम हो सकते हैं, कहीं कहीं यह कठोर भी होंगे, लेकिन हमारी पहचान और हमारा आदर इसी शिष्टाचार में निहित है।

वर्तमान में समाज में भ्रष्टाचार और दुर्भावनाएं विकराल रूप ले रही हैं और इसका वास्तविक कारण यही है कि ऐसा करने वालों की समस्या को सही रूप में पहचाना ही नहीं जा रहा है। इसके अभाव में समाधान कहां से आएगा? ऐसे में उन्हें उनकी योग्यता के मूल्यांकन की और इससे संबंधित पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। इस रोग का असली इलाज उन्हें सुविधाओं को मुहैया कराना मात्र नहीं है, इसके लिए उन्हें सच्चे गुरु और मार्गदर्शक की आवश्यकता है। यदि हम किसी पर परोपकार करना चाहते हैं या उसे कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं या उसकी सेवाओं की आवश्यकता हमें है, तो संबंधित कार्यों में उसका पारंगत होना एक महत्त्वपूर्ण आधार है। हर कार्य के लिए हमको पारंगत या संपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति मिले, इसकी तो संभावना लगभग नगण्य ही है, फिर भी उसकी इच्छाशक्ति, समर्पण भावना और अनुभव आदि का मूल्यांकन हमें कर ही लेना चाहिए। इस मूल्यांकन से ही हम उसके भीतर के शिष्टाचार को पहचान सकते हैं। किसी भी अशिष्ट से तिलिस्म की आशा करना व्यर्थ ही है। कहा भी गया है जो बे-अदब है और उसमें इच्छाशक्ति भी नहीं है, तो वह बे-नसीब ही रहेगा। इसके विपरीत बा-नसीब वही बन सकता है जो बा-अदब होगा और जिसे अपनी उपलब्धियों पर लेशमात्र भी घमंड नहीं है।

दुनिया मेरे आगे

> **किसी भी अशिष्ट से तिलिस्म की आशा करना व्यर्थ ही है। कहा भी गया है जो बे-अदब है और उसमें इच्छाशक्ति भी नहीं है तो वह बे-नसीब ही रहेगा। इसके विपरीत बा-नसीब वही बन सकता है जो बा-अदब होगा और जिसे अपनी उपलब्धियों पर लेशमात्र भी घमंड नहीं है।**

जड़ता की सोच

विद्यार्थी आंदोलन के बाद सार्वजनिक जीवन में अपशब्दों के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है। गलियां किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य हैं। छात्र आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग लड़कियों की आलोचना कर रहे हैं। जंतर मंतर पर अपशब्दों का इस्तेमाल लड़कों ने भी किया, लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इस सबमें सोशल मीडिया पर सभी लोग लड़कियों को ही घेर रहे हैं। यह प्रकरण रूढ़िवादी सोच को उजागर करता है, जिसके अनुसार नैतिकता का सारा भार महिलाओं पर है। समाज में फिर से पुरुषवादी सत्ता को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान एक नेता का वीडियो खूब प्रसारित हुआ, जिसमें वे आंदोलनकारी छात्रों को रास्ते में रोक कर धमकाते तथा उन्हें गालियां देते हुए दिखे। गालियां ऐसी कि सुनी न जा सकें। वीडियो खुद गाली देने वाले ने बनाया और फिर उसे प्रसारित किया। क्या यह कार्य नैतिक था? असभ्यता उसमें भी थी, लेकिन किसी ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। अपशब्द कोई भी बोले, उसे हतोत्साहित ही किया जाना चाहिए। इसे लैंगिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

– भगवती, नासिक, महाराष्ट्र

नतीजे का संकेत

उपचुनाव के नतीजों के राजनीतिक संकेत गहरे होते हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं, क्योंकि यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्यसभा सदस्य बनने के उपरांत रिक्त हुई थी। यह लंबे समय से पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। बांकीपुर में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत ने उसे आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है। उनकी जीत यह भी बताती है कि पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों के बीच मतदाता नए विकल्पों को आजमाने के लिए तैयार हैं। युवाओं के मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, स्थानीय समस्याएं और सरकार के प्रति असंतोष जैसे मुद्दों ने चुनावी परिणाम को बदल दिया। बांकीपुर का संदेश सत्ता पक्ष के लिए सतर्क होने और जनता से संवाद बढ़ाने का संकेत है। अब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

संवाद का तकाजा

झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य को लेकर उठे गंभीर सवालों के केंद्र में आ गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र अनशन और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आंदोलनरत छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद जब वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो पेपर लीक, भ्रष्टाचार, प्रभावशाली लोगों की दखलंदाजी और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आज का युवा केवल रोजगार नहीं चाहता, बल्कि वह निष्पक्ष अवसर और न्यायपूर्ण व्यवस्था की भी मांग कर रहा है। यदि सरकार और छात्रों के बीच संवाद के माध्यम से समाधान निकलता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का संकेत होगा।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

चर्चा की जगह

'बहस के बिना' (संपादकीय, 4 जुलाई) पढ़ा। इसमें उचित चिंता व्यक्त की गई है कि संसद में गंभीर बहस के बजाय हंगामा, स्थगन और जल्दबाजी में विधेयक पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह ध्यान देना होगा कि संसद केवल कानून बनाने की मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र के सामूहिक विवेक का मंच है। प्रतिनिधि जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। यदि जन-जीवन को प्रभावित करने वाले विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा ही न हो, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। यह बात दोनों ही पक्षों को नहीं भूलना चाहिए। सरकार को संख्या-बल के अहंकार और विपक्ष को निरंतर व्यवधान की राजनीति से ऊपर उठना होगा। क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को बार-बार अपने दायित्व याद दिलाने के लिए कभी न्यायपालिका, कभी नागरिक समाज, तो कभी किसी आंदोलन से सीख लेनी पड़ेगी?

– बृज भूषण गोयल, लुधियाना

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चिंतन

भारतीय कानून का सम्मान करें सोशल मीडिया कंपनियां

किसी लोकतंत्र में यह अधिकार किसके पास होना चाहिए कि कौन-सी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और कौन-सी नहीं? जनता के पास, संविधान के पास, कानून के पास या फिर कैलिफोर्निया में बैठे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिद्म के पास? पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार और मेटा के बीच चल रहा टकराव इसी मूल प्रश्न के इर्द-गिर्द घूम रहा है। खासकर कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने पैसे लेकर जिस तरह से खास तरह के कंटेंट को असामान्य रूप से बढ़ावा दिया, जबकि दूसरी तरह के कंटेंट की पहुंच सीमित रही, उसने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। इन आरोपों के पक्ष या विपक्ष में अभी कोई सार्वजनिक तकनीकी जांच सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया वीडियो कई घंटों के लिए हटा दिया गया। मेटा ने इसे तकनीकी भूल बताते हुए सार्वजनिक माफी भी मांग ली। लेकिन क्या केवल माफी इस पूरे विवाद का समाधान है? शायद नहीं। यही वजह है कि पिछले दो दिनों से मेटा की वैश्विक टीम भारत में डेरा डाले हुए है। गुरुवार को भी सरकार के साथ उसकी लंबी बैठकों का दौर जारी रहा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की। सरकार ने सिर्फ प्रधानमंत्री का वीडियो हटने का कारण नहीं पूछा, बल्कि उससे कहीं बड़े सवाल सामने रख दिए हैं। मेटा के एल्गोरिद्म कैसे काम करते हैं? कंटेंट मॉडरेशन का आधार क्या है? भारतीय कानूनों का पालन कैसे सुनिश्चित होता है? डीपफेक और बाल यौन शोषण सामग्री जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने की व्यवस्था क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मेटा वास्तव में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा का हकदार है? ये सवाल केवल मेटा से नहीं हैं। ये हर उस वैश्विक डिजिटल कंपनी से हैं जिसने भारत में करोड़ों उपयोगकर्ता तो बना लिए, लेकिन जवाबदेही के मामले में अक्सर अपनी वैश्विक नीतियों की आड़ लेती रही है। दरअसल, पिछले एक दशक में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा। यह राजनीति, चुनाव, सामाजिक आंदोलनों, व्यापार और जनमत निर्माण का प्रभावशाली मंच बन चुका है। पहले यह काम अखबारों और टीवी चैनलों के संपादक करते थे। आज यह जिम्मेदारी एल्गोरिद्म निभा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अखबार का संपादक सामने दिखाई देता था, उसकी जवाबदेही तय होती थी। एल्गोरिद्म अदृश्य है। वह किस आधार पर निर्णय लेता है, किसे ऊपर लाता है और किसे नीचे धकेल देता है, यह किसी को पता नहीं। यही अपारदर्शिता सबसे बड़ी चिंता है। भारत सरकार का यह कहना बिल्कुल उचित है कि भारत में कारोबार करने वाली किसी भी कंपनी को भारतीय कानूनों के तहत ही काम करना होगा। सरकार की जवाबदेही भी है कि नियमन के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक अंकुश न लगे। इसलिए कानून का उद्देश्य विचारों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि नियमों को निष्पक्ष और समान रूप से लागू करना होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र है। यहां कानून संसद बनाती है, जनता सरकार चुनती है और संविधान सर्वोच्च है। इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी का एल्गोरिद्म भारतीय लोकतंत्र से बड़ा हो जाए।

जयंती
आज

राष्ट्र निर्माण में ओपी जिन्दल का योगदान

राष्ट्र का निर्माण केवल सरकारी नीतियों से नहीं होता; उसे आकार देते हैं वे दूरदर्शी व्यक्तित्व, जो अपने कर्म, विचार और मूल्यों से समाज को नई दिशा देते हैं। ऐसे ही युग निर्माताओं में ओम प्रकाश जिन्दल का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी 96वीं जयंती केवल एक महान उद्योगपति को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उस जीवन-दर्शन को नमन करने का समय है, जिसने उद्योग को राष्ट्र सेवा का माध्यम, शिक्षा को सशक्त समाज की नींव और सेवा को विकास का सर्वोच्च उद्देश्य माना।

हरियाणा के हिसार स्थित नलवा गांव के एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले ओम प्रकाश जिन्दल की जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि बड़े सपने, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम किसी भी व्यक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदलते हुए एक ऐसे औद्योगिक समूह की स्थापना की, जिसने भारतीय इस्पात उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल उद्योगपति की नहीं थी। उन्होंने ऐसी कार्य-संस्कृति विकसित की, जिसमें ईमानदारी, गुणवत्ता, नवाचार, मानवीय संवेदनशीलता और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे। यही मूल्य आज भी उनकी विरासत की सबसे बड़ी पहचान हैं।

ओपी जिन्दल का विश्वास था कि मजबूत उद्योग किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का आधार होते हैं। उद्योग केवल उत्पादन नहीं बढ़ाते, बल्कि रोजगार, कौशल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास के नए अवसर भी पैदा करते हैं। आज जब भारत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब उनके विचार पहले से अधिक प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय उत्पादक राष्ट्र बनना होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जिन्दल समूह उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात, आधुनिक विनिर्माण, तकनीकी उत्कृष्टता और औद्योगिक नवाचार के माध्यम से देश के रेलवे, ऊर्जा, अवसंरचना, निर्माण और रक्षा क्षेत्रों के विकास में निरंतर योगदान दे रहा है। ओपी जिन्दल का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं और उनकी शिक्षा से तय होता है। उनके लिए शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि नेतृत्व, नैतिकता, संवेदनशीलता और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने का साधन थी। आज जब भारत ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब उनकी सोच और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। उनकी प्रेरणा से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों ने हजारों युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और नेतृत्व के अवसर प्रदान किये हैं।

ओपी जिन्दल का विश्वास था कि विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उनके लिए उद्योग और समाज एक-दूसरे के पूरक थे। इसी सोच के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, खेल प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर कार्य किये जाते रहे हैं। उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व को केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि विकास की मूल भावना माना। आज का औद्योगिक विकास केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है; वह पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और तकनीकी नवाचार से भी जुड़ा है। जिन्दल समूह भी इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा दक्षता, तकनीकी आधुनिकीकरण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और टिकाऊ औद्योगिक प्रक्रियाओं पर लगातार कार्य कर रहा है। यह दृष्टिकोण श्री ओ.पी. जिन्दल जी की दूरदर्शी सोच का ही विस्तार है, जिसमें विकास और पर्यावरण साथ-साथ चलते हैं।

भारत आज विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। यह पीढ़ी नवाचार, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए युग का नेतृत्व कर रही है। ऐसे समय में ओ.पी. जिन्दल का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं होनी चाहिए; उसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना भी होना चाहिए। एक सफल उद्योगपति होने के साथ-साथ ओपी जिन्दल सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रहे। हिसार से विधायक, कुरुक्षेत्र से सांसद और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने विकास, ग्रामीण प्रगति, रोजगार और जनकल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनके लिए सार्वजनिक जीवन का अर्थ सत्ता नहीं, बल्कि सेवा था। उनका जीवन आज भी यह संदेश देता है कि विकसित भारत का निर्माण सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और समाज की साझी भागीदारी से ही संभव है। आज भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आज उनकी 96वीं जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें- राष्ट्र को सर्वोपरि रखें, उत्कृष्टता को अपना लक्ष्य बनाएं और विकास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लें।

ओपी जिन्दल का जीवन हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव उद्योग, शिक्षा और सेवा के समन्वय से तैयार होती है। यही उनका जीवन-दर्शन था, यही उनकी अमर विरासत है और यही विकसित, आत्मनिर्भर तथा समावेशी भारत का मार्ग भी है।

संतुलन साधती मौद्रिक नीति

आर्थिकी
सतीश सिंह

केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख 'न्यूट्रल' बनाए रखते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि फिलहाल न तो ब्याज दरों में जल्दबाजी में कटौती की आवश्यकता है और न ही उन्हें बढ़ाने का कोई औचित्य दिखाई देता है। आरबीआई ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई अभी भी उसके लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि महंगाई का प्रमुख स्रोत मांग में अत्यधिक वृद्धि नहीं, बल्कि खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव है। यदि आने वाले महीनों में महंगाई अनुमानित दिशा में घटती है, खाद्य आपूर्ति सामान्य रहती है और वैश्विक जोखिम नियंत्रित होते हैं, तो आरबीआई के पास भविष्य में अधिक अनुकूल नीतिगत कदम उठाने की पर्याप्त गुंजाइश होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और उसकी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5 अगस्त की समीक्षा बैठक में व्यापक बाजार अपेक्षाओं के अनुरूप रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा। इस नीति समीक्षा का केंद्रीय संदेश यह है कि आरबीआई ऐसे समय में अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहता है, जब एक ओर महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है और दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत विकास की ओर अग्रसर है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख 'न्यूट्रल' बनाए रखते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि फिलहाल न तो ब्याज दरों में जल्दबाजी में कटौती की आवश्यकता है और न ही उन्हें बढ़ाने का कोई औचित्य दिखाई देता है। आरबीआई ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई अभी भी उसके लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि महंगाई का प्रमुख स्रोत मांग में अत्यधिक वृद्धि नहीं, बल्कि खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव है।

यही कारण है कि केंद्रीय बैंक कोर महंगाई को लेकर अपेक्षाकृत आश्वस्त दिखाई देता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआई ने खुदरा महंगाई के औसत अनुमान को 5 प्रतिशत पर रखा है। उसके तिमाही अनुमानों के अनुसार दूसरी तिमाही में महंगाई 4.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में 5.5 प्रतिशत रह सकती है। यह अनुमान बताता है कि आरबीआई खाद्य एवं आपूर्ति पक्ष से उत्पन्न दबावों को अस्थायी मान रहा है और उसे उम्मीद है कि समय के साथ इनमें नरमी आएगी। महंगाई को लेकर सतर्क रुख के बावजूद आरबीआई आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर पहले की तुलना में अधिक आशावाद है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है। तिमाही आधार पर पहली तिमाही में 7 प्रतिशत, दूसरी में 6.4 प्रतिशत, तीसरी में 6.5 प्रतिशत और चौथी में 6.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति अभी भी संतोषजनक बनी हुई है। इस आशावाद के पीछे कई ठोस कारण हैं। विनिर्माण क्षेत्र के शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं, सेवा क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है, निजी उपभोग मजबूत बना हुआ है तथा विवेकाधीन खर्च में भी सुधार देखा जा रहा है। सार्वजनिक निवेश और अवसंरचना परियोजनाओं का प्रभाव भी आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है। ऐसे परिदृश्य में ब्याज दरों में अनावश्यक बदलाव की आवश्यकता नहीं है। रेपो दर के साथ-साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) दर 5 प्रतिशत तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) एवं बैंक दर 5.5 प्रतिशत पर भी अपरिवर्तित रखी गई हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक ढांचे में किसी बड़े परिवर्तन का इच्छुक नहीं है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका 'न्यूट्रल' नीति रुख है।

इसका अर्थ यह है कि आरबीआई किसी पूर्वनिर्धारित दिशा में नहीं बढ़ रहा, बल्कि आने वाले आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप

निर्णय लेने की रणनीति पर कायम है। हालांकि रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, फिर भी आरबीआई ने यह संकेत दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) अथवा अन्य उपयुक्त साधनों का उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय बैंक का आकलन है कि बैंकिंग प्रणाली में धन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन की तत्काल आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ महीनों के दौरान मनी मार्केट दरों और सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिफल दरों में नरमी आई है। यह संकेत है कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई है। साथ ही उद्योग, सेवा और खुदरा- तीनों क्षेत्रों में ऋण मांग संतोषजनक बनी हुई है। यद्यपि जमा और ऋण दरों के बीच अंतर घटने से कुछ बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव देखा गया है, फिर भी बैंकिंग प्रणाली की समग्र वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसका अर्थ है कि बैंकों के पास ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता बनी हुई है और अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह फिलहाल संतुलित है। आरबीआई की सतर्कता का सबसे महत्वपूर्ण कारण वैश्विक आर्थिक वातावरण है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव, वैश्विक व्यापार नीतियों में अनिश्चितता, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियां तथा जलवायु संबंधी जोखिम- विशेषकर अल नीनो- आने वाले महीनों में महंगाई और विकास, दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि होतीहै, तो उसका सीधा असर घरेलू महंगाई, चालू खाते के घाटे और राजकोषीय संतुलन पर पड़ेगा। फिलहाल होम लोन, ऑटो लोन तथा अन्य फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋणों की मासिक किस्तों (ईएमआई) में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी प्रकार सावधि जमा पर ब्याज दरों में भी तत्काल व्यापक परिवर्तन की उम्मीद कम है। उद्योग जगत के लिए राहत की बात यह है कि ऋण उपलब्धता बनी रहेगी और बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कोई गंभीर कमी नहीं है। निवेशकों के लिए भी यह नीति अपेक्षाकृत स्थिर ब्याज दर वातावरण का संकेत देती है, जिससे पूंजी बाजारों में अनिश्चितता सीमित रह सकती है। अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि आरबीआई ने महंगाई नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता-इन तीनों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। एक ओर उसने विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती पर भरोसा जताया है, वहीं दूसरी ओर संभावित महंगाई जोखिमों को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती से परहेज किया है। साथ ही पर्याप्त तरलता बनाए रखने का आश्वासन देकर उसने बैंकिंग प्रणाली को विश्वास भी दिया है, किंतु अतिरिक्त नकदी प्रवाह से बचकर मौद्रिक अनुशासन को भी कायम रखा है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह नीति न तो अत्यधिक उदार कही जा सकती है और न ही अनावश्यक रूप से कठोर। यह ऐसी संतुलित रणनीति है, जिसमें अल्पकालिक लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। यदि आने वाले महीनों में महंगाई अनुमानित दिशा में घटती है, खाद्य आपूर्ति सामान्य रहती है और वैश्विक जोखिम नियंत्रित होते हैं, तो आरबीआई के पास भविष्य में अधिक अनुकूल नीतिगत कदम उठाने की पर्याप्त गुंजाइश होगी।

(लेखक वरिष्ठ बैंकिंग एवं आर्थिक स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

गुरु बिना न भक्ति सार्थक और न ही मुक्ति संभव

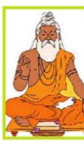

संकलित
दर्शन

कागा सब तन खाइयो, चुनि चुनि खाइयो मांस। दुइ अखियां मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस।।

इश्क हकीकी हो या इश्क मिजाजी, यह इश्क का चरम है। इश्क के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें, तो भी थोड़ा है, कम है। इतिहास गवाह है कि इश्क करने वालों ने मरना कुबूल किया, पर इश्क से मुंह मोड़ना मंजूर नहीं किया। सांसारिक प्रेम के दीवाने हों या फिर रब्बी इश्क के मतवाले। खुदा की खोज स्वयं की खोज है। इसलिए स्वयं को स्वयं तक पहुंचने के लिए जरूरत होती है पूर्ण सद्गुरु और सच्चे रहबर तक पहुंचने की। सद्गुरु बेखबर इनसान को खबर देते हैं कि ये रहा निरंकार। तुम इसे चाहे कुछ भी नाम दे दो, है ये एक ही। खुदा भी यही, प्रभु भी यही, ऑलमाइटी गॉड भी यही तो वाहेगुरु भी यही। यही महबूब है हर रूह का, जिसे पाने के लिए आत्मा ने जाने कितने जन्म लिए हैं। इसे पाने के बाद ही भक्ति शुरू होती है और इसको जान लेने से ही मुक्ति मिलती है। इसके बिना न भक्ति सार्थक है और न मुक्ति संभव है। सद्गुरु मिलते ही सारे भ्रम-भुलेखे समाप्त हो उठते हैं। प्रेम और इश्क करने वालों के हिस्से तो सजा ही आया करती है। सजा से डरकर वे अपना समर्पण छोड़ नहीं दिया करते। यहां कवि ने ऐसे ही समर्पण को अपनी दो पंक्तियों में इस तरह व्यक्त किया है कि हां, मैंने मोहब्बत की है। यह मेरा गुनाह है तो खुलकर सजा दे दो। मेरे तन की बोटी-बोटी नोच लो, पर ख्याल रहे कि ये आंखें सलामत रहें, इन आंखों को मत छूना क्योंकि ये आंखें पिया की बाट जोह रही हैं।

प्रभावी संवाद के लिए संवेदनशीलता जरूरी

संकलित
प्रेरणा

प्रभावी संवाद के लिए संवेदनशीलता तथा समझदारी, दोनों गुणों में निपुणता आवश्यक है। कुछ लोग अति संवेदनशील होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी बुद्धिमता खो देते हैं। उनकी वाणी में अस्पष्टता होती है और उसमें अस्फुटता झलकती है। इसमें आपकी मनःस्थिति का भी योगदान है। आप केवल क्रोध कर के किसी को सुधार नहीं सकते। इससे केवल आपके मन की शांति ही भंग होगी। जब आप लोगों से मिलते हो तो प्रायः आप उनसे बुद्धि के स्तर पर ही संवाद करते हो। यही, जब आप प्रकृति के साथ होते हो तो आप स्वतः ही गाना आरंभ कर देते हो तथा प्रकृति के साथ अपने दिल से संवाद स्थापित कर लेते हो। जब आप लोगों के साथ होते हो तो बुद्धि के स्तर पर ही बातचीत अथवा गपशप ही करते रहते हो। किंतु आप यदि प्रकृति के संग हो तो आप गुनगुनाने लगते हो और आपका संवाद दिल से निकलता है। और जब आप गुरु के सान्निध्य में होते हो तो आप खाली हो जाते हो, सभी प्रश्न भूल जाते हो! तब उस मौन में आत्मा के स्तर पर संवाद होता है। संसार में जन्म लेते ही, जैसे ही हम अपनी प्रथम श्वास लेते हैं, हम संवाद करना आरंभ कर देते हैं। हमारा पहला क्रंदन अपनी मां और इस दुनिया से हमारे प्रथम संवाद का द्योतक है कि मैं आ गया हूं। और अपनी अंतिम सांस तक हम निरंतर संवाद करते रहते हैं। तथापि, अच्छे स्तर का संवाद केवल शब्दों से कहीं ऊपर होता है। यह एक कला है और प्रभावी संवाद के लिए, केवल बोले गए शब्द की जगह बहुत से अन्य आयाम होते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती हो

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती होना चाहिए। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो इसके लिए सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कानून के तहत लगभग 25 हजार जुर्माना और लगभग तीन साल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि सरकार और प्रशासन इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। स्कूलों में इसके लिए बच्चों को जागरूक भी किया जाए और स्कूलों से विद्यार्थियों के माता-पिता को इसके लिए नोटिस भी भेजे जाए कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। दोपहिया वाहन एक्सीडेंट का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर एक्टिवा चलाते समय हैलमेट का प्रयोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, न कि चालान के डर से। *- दया ठाकुर, रायपुर*

करंट अफेयर

रानी-प्रिया कपूर विवाद, आपसी सहमति से समझौते की उम्मीद

उच्चतम न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक न्यास को लेकर जारी विवाद में बृहस्पतिवार को कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया 'काफी संतोषजनक' ढंग से बढ़ रही है और उसे 'उम्मीद' है कि यह विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मध्यस्थ की ओर से दाखिल शुरुआती मध्यस्थता रिपोर्ट पर गौर किया। पीठ ने कहा, हमने देखा है कि अबतक मध्यस्थता की प्रक्रिया छह सत्रों में हुई है। मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है। हमें यह जानकर खुशी है कि मध्यस्थता काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है।

हमें इस बात से भी खुशी है कि सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि मध्यस्थ ने दो नवंबर तक मध्यस्थता के लिए समय देने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा, संबंधित पक्षों को खुले मन और दिल से मध्यस्थ के पास जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी लंबे कानूनी विवाद में न फंसें। मध्यस्थता को बढ़ने दें, हम एक और रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान 'आर.के. फैमिली ट्रस्ट' से किया जाए।

ऑफ बीट

मिंजर मेला : संस्कृति और धार्मिक आस्था की अनूठी झलक

श्रावण की पहली फुहारों और रावी नदी के अनहद नाद के बीच दूसरे रविवार को चंबा के ऐतिहासिक मैदान में अंतरराष्ट्रीय मिंजर महोत्सव का शुभारंभ होता है।

शोभायात्रा में स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आस्था की अनूठी झलक देखने को मिलती है। माना जाता है कि किसी महत्वपूर्ण विजय और समृद्ध फसल की खुशी में लोगों ने राजा का स्वागत धान और मक्की की बालियों के प्रतीक 'मिंजर' से किया। 'मिंजर' रेशमी धागों से तैयार की जाने वाली एक विशेष लटकन होती है, जो धान और मक्की की नई बालियों का प्रतीक मानी जाती है। इसे अच्छी फसल, खुशहाली और समृद्धि का संदेश देने वाला शुभ प्रतीक माना जाता है। शोभायात्रा में भगवान लक्ष्मीनारायण और भगवान रघुनाथ मंदिर में मिंजर अर्पित की जाती है। मेले के दौरान लोग इसे अपने वस्त्रों पर धारण करते हैं और मंदिरों में अर्पित करते हैं। मेले का समापन विशेष धार्मिक अनुष्ठान के साथ होता है। अंतिम दिन शोभायात्रा रावी नदी के तट तक पहुंचती है, जहां मिंजर, नारियल, मौसमी फल और शुभ सामग्री जल में अर्पित की जाती है। यह परंपरा प्रकृति के प्रति आभार, अच्छी फसल और सुख-समृद्धि की कामना का प्रतीक मानी जाती है। धीरे-धीरे यह परंपरा एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में बदल गई, जो आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।

X ट्रेंड f

'गोबरधन' योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23,731 करोड़ की लागत वाली 'गोबरधन' योजना को मंजूरी देना 'आत्मनिर्भर भारत', स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। **- योगी आदित्यनाथ**, सीएम, उप्र

बीजेपी-स्टाइल

यह बीजेपी-स्टाइल की तरक्की की नई हवा है... जिस सड़क का उद्घाटन कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसकी मरम्मत अभी से करनी पड़ रही है और मरम्मत को सुखाने के लिए तेज रफ्तार वाले पंखे इस्तेमाल किए जा रहे हैं- यह भी हंसी की बात है। **-अखिलेश यादव**, सांसद, सपा

हम छात्रों के साथ

कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। चाहे झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो या कोई और जगह, हम अपने छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। चाहे हमारे गठबंधन के साथी हों या विपक्ष, हम छात्रों और युवाओं के साथ खड़े हैं। हम उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। **- मल्लिकार्जुन खड़गे**, अध्यक्ष, कांग्रेस

निष्पक्ष जांच हो

पिछले छह सालों में जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं, जिनमें सीजीएल, उत्कर्ष सिपाही और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं, उन्हें तुरंत रद्द किया कर उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। **-बाबूलाल मरांडी**, पूर्व सीएम, झारखंड

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की जरूरत

नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि में शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में दोनों सदनों का काम लगातार जिस तरह बाधित है, वह बेहद चिंताजनक है. जंतर-मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया, लेकिन इससे जुड़े मुद्दे अब भी संसदीय गतिरोध की वजह बने हुए हैं. दरअसल छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का रुख आक्रामक है और वह इस मामले में गृह मंत्री का जवाब चाहती है. राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. इस मुलाकात के पीछे परिसीमन बिल पर विपक्ष का मन टटोलने की मंशा भी थी.

लोकसभा में नेता विपक्ष से वार्ता की सरकार की पहल अच्छी थी. सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसकी पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है. उसी तरह विपक्ष को भी अपनी जिद छोड़ संसदीय कामकाज को चलने देना चाहिए.

सरकार और विपक्ष के बीच बने मौजूदा टकराव को देखते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष से वार्ता की सरकार की पहल अच्छी थी. सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसकी पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है. उसी तरह विपक्ष को भी अपनी जिद छोड़ संसदीय कामकाज को चलने देना चाहिए. दरअसल विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहता है, जबकि सरकार चाहती है कि संवैधानिक संशोधन और अन्य प्रमुख विधेयकों को जल्द पारित कराया जाये. सरकार संसद के इस सत्र में एफसीआरए बिल को भी पारित कराने की कोशिश में है. यह कानून भारत में व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों की ओर से विदेशी फंड लेने और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करता है. इस सत्र में अभी तक लोकसभा में एक भी प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका है. जबकि प्रश्नकाल का सबसे ज्यादा महत्व खुद विपक्ष के लिए होता है, क्योंकि इससे सरकार की जवाबदेही तय करने में मदद मिलती है, मंत्रियों से सीधे सवाल पूछे जाते हैं और जनता के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाता है. इस सत्र में पांच बिल बिना चर्चा के पास हुए हैं. बेशक विधेयक पारित हो रहे हैं और सरकार अपने विधायी कार्य आगे बढ़ा रही है, लेकिन यह तस्वीर लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है. संसदीय परंपरा में बहस और चर्चा सदन की कार्यवाही के सबसे जरूरी अंग हैं. इसकी अनदेखी ठीक नहीं. ऐसे में, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों को ही मौजूदा गतिरोध खत्म करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए.

कांग्रेस में निर्णय की डोर अब भी दिल्ली के हाथ

रशीद किदवई
वरिष्ठ पत्रकार
rasheedkidwai@gmail.com

समय पर स्पष्ट फैसले ही किसी सियासी दल का भविष्य तय करते हैं. लेकिन कांग्रेस लगातार अनिश्चितता और अनिर्णय के भंवर में फंसी हुई नजर आती है. चाहे वह कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार का मसला हो या फिर पंजाब में संगठन से जुड़े हुए विवाद, पार्टी की अंदरूनी दुविधा ने शीर्ष नेतृत्व की साख पर सवाल खड़े कर दिये हैं. अभी कांग्रेस के लिए चुनौती यही है कि वह कर्नाटक में अपनी सियासी जमीन बचाकर रखे तथा पंजाब में सत्तारूढ़ आप को शिकस्त देने की तैयारी करे.

समय पर स्पष्ट फैसले ही किसी सियासी दल का भविष्य तय करते हैं. लेकिन कांग्रेस लगातार अनिश्चितता और अनिर्णय के भंवर में फंसी हुई नजर आती है. चाहे वह कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार का मसला हो या फिर पंजाब में संगठन से जुड़े हुए विवाद, पार्टी की अंदरूनी दुविधा ने शीर्ष नेतृत्व की साख पर सवाल खड़े कर दिये हैं. कर्नाटक की बात करें, तो वहां डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बने दो महीने से ज्यादा हो चुका है. तीन जून को उन्होंने पद संभाला था और अब दो महीने बीतने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. लेकिन तब भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. उन्नीस नये मंत्रियों के शपथ लेने के बाद से कई विधायक और उनके समर्थक खुलकर विरोध पर उतर आये हैं. इस संकट को टालने और विधायकों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतरना पड़ा है. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद और कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी बागी नेताओं से अलग-अलग मुलाकातें की हैं. जब हाईकमान का विश्वासपात्र माना जाने वाला एक सशक्त और चुना हुआ मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल को पूर्ण आकार देने में असहाय महसूस करे, तो इससे सरकार और पार्टी, दोनों की छवि पर विपरीत असर पड़ना स्वाभाविक है. मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तक हालत यह थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री-विधायक बार-बार दिल्ली के चक्कर काट रहे थे. कुछ दिन पहले तक भी राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के लिए दिल्ली के गलियारों में नेताओं की लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थी. ऐसे में यहां बुनियादी सवाल यह उठता है कि आखिर एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार जैसे संवैधानिक अधिकार के लिए भी बार-बार दिल्ली की बाट क्यों जोहनी पड़ती है?

राजनीति में किसी दल के भीतर अंदरूनी खींचतान कोई असामान्य बात नहीं है. यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के पद से अपनी विदाई से न तब संतुष्ट थे और न आज हैं. इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में उनके खेमे की तरफ से तरह-तरह के राजनीतिक पेच फंसाया जाना लाजिमी था. लेकिन नेताओं की आपसी रस्साकशी भी राज्य की सीमा के भीतर ही होनी चाहिए. छोटे-छोटे मसलों को लेकर नेताओं का बार-बार दिल्ली की तरफ दौड़ लगाना दरअसल संगठन के कमजोर ढांचे को ही उजागर करता है. मंत्रिमंडल का विस्तार करना वैसे भी मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार और दायित्व है. इसके लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संगठन महासचिव और अन्य पदाधिकारियों का भी सहयोग रहा होगा. फिर आज के दौर में फोन, व्हाट्सएप और अन्य संचार माध्यमों से भी समन्वय करना आसान है. गौर करना चाहिए कि कर्नाटक स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह राज्य भी है. इसके बावजूद यदि मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों के लिए भी राज्य सरकार को दिल्ली के हुक्म का मोहताज रहना पड़े, तो यह कांग्रेस की विकेंद्रीकृत व्यवस्था के दावों की पोल खोलता है. इससे न केवल पार्टी की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, बल्कि यह राहुल गांधी की नेतृत्व शैली के विरोधाभास को भी सतह पर ले आता है. राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करते आये हैं, लेकिन जब उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर निर्णय लेने की बात आती है, तब वही पुरानी दिल्ली केंद्रित संस्कृति हावी दिखाई देती है.

पंजाब की स्थिति तो और भी चिंताजनक नजर आ रही है. राज्य में हर गुजरते दिन के साथ चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही. स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि प्रदेश प्रभारी के सामने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मारपीट तथा हुड़दंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. इसके विपरीत, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में अपनी पैठ लगातार मजबूत कर रही है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं और पंजाब का काम भी देख चुके हैं. आम आदमी पार्टी के साथ सीजेपी के संबंधों की बात आ रही है और माना जा सकता है कि जंतर-मंतर के प्रदर्शनों के बाद सीजेपी की प्रतिष्ठा में हुए इजाफे का फायदा पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है. दूसरी ओर भाजपा भी तेजी से अपनी रणनीति पर काम कर रही है. उसने हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिशें तेज कर दी हैं. इसके लिए जहां राघव चड्ढा जैसे चेहरों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू भी पूरी शिद्दत से जमीन पर सक्रिय हैं. जब विरोधी पक्ष अपनी गोटियां पंजाब में इतनी तेजी से सेट कर रहा हो, तब कांग्रेस का अंदरूनी कलह और आत्ममुग्धता में उलझे रहना उसके लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है. लगातार ऐसी अटकलें भी लग रही हैं कि किसी बड़े पार्टी नेता के ऊपर गाज गिर सकती है. कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह की अनिश्चितता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है.

कांग्रेस को यहां यह समझना होगा कि पंजाब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण राज्य है. आगामी विधानसभा चुनाव में यदि वह पंजाब में वापसी नहीं कर पाती है, तो यह उसके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा. अगले साल पंजाब के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं. उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता में परिवर्तन होता भी है, तो वह कांग्रेस की जीत नहीं होगी. उसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव को जायेगा. जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो वहां कांग्रेस के पास कोई बहुत प्रभावशाली चेहरा या मजबूत जनाधार नहीं है. समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद वहां हिंदुत्व की राजनीति और अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है. ऐसे में उस राज्य में कांग्रेस की चुनावी जीत की संभावना तो और भी कम नजर आती है. पंजाब ही ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस के लिए संभावनाएं हैं. पंजाब में जीत ही कांग्रेस की जीत मानी जायेगी. तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस के लिए चुनौती यही है कि वह कर्नाटक में अपनी सियासी जमीन बचाकर रखे और पंजाब में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर सत्ता में वापसी करे. इसके बाद ही वह केंद्र की राजनीति में अपनी सम्मानजक स्थिति की उम्मीद कर सकती है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

सतर्कता का संकेत है आरबीआइ का यथास्थिति फैसला

सतीश सिंह
वरिष्ठ बैंकिंग एवं आर्थिक स्तंभकार
satish5249@sbi.co.in

अगस्त, 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा स्पष्ट करती है कि आरबीआइ ने महंगाई नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है. एक ओर उसने विकास दर का अनुमान बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती पर भरोसा जताया है, दूसरी ओर संभावित महंगाई जोखिमों को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती से परहेज किया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) और उसकी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पांच अगस्त की समीक्षा बैठक में व्यापक बाजार अपेक्षाओं के अनुरूप रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा. इस नीति समीक्षा का केंद्रीय संदेश यह है कि आरबीआइ ऐसे समय में अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहता है, जब एक ओर महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आयी है और दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत विकास की ओर अग्रसर है. आरबीआइ ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित खुदरा महंगाई अभी भी उसके लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि महंगाई का प्रमुख स्रोत मांग में अत्यधिक वृद्धि नहीं, बल्कि खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव है. यही कारण है कि केंद्रीय बैंक कोर महंगाई को लेकर अपेक्षाकृत आश्वस्त दिखाई देता है.

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआइ ने खुदरा महंगाई के औसत अनुमान को पांच प्रतिशत पर रखा है. उसके तिमाही अनुमानों के अनुसार दूसरी तिमाही में महंगाई 4.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में 5.5 प्रतिशत रह सकती है. यह अनुमान बताता है कि आरबीआइ खाद्य एवं आपूर्ति पक्ष से उत्पन्न दबावों को अस्थायी मान रहा है. महंगाई को लेकर सतर्क रुख के बावजूद केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर पहले की तुलना में अधिक आशावादी है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है. तिमाही आधार पर पहली तिमाही में सात प्रतिशत, दूसरी में 6.4 प्रतिशत, तीसरी में 6.5 प्रतिशत और चौथी में 6.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति अभी भी संतोषजनक बनी हुई है. इस आशावाद के पीछे कई ठोस कारण हैं. विनिर्माण क्षेत्र के शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं, सेवा क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है, निजी उपभोग मजबूत बना हुआ है तथा विवेकाधीन खर्च में भी सुधार देखा जा रहा है. सार्वजनिक निवेश और अवसंरचना परियोजनाओं का प्रभाव भी आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है. ऐसे परिदृश्य में ब्याज दरों में अनावश्यक बदलाव की आवश्यकता नहीं है.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि रेपो दर के साथ-साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर पांच प्रतिशत तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एवं बैंक दर 5.5 प्रतिशत पर भी अपरिवर्तित रखी गयी है. यह स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक ढांचे में किसी बड़े परिवर्तन का इच्छुक नहीं है. पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका 'न्यूट्रल' नीति रुख है. इसका अर्थ यह है कि आरबीआइ किसी पूर्व निर्धारित दिशा में नहीं बढ़ रहा, बल्कि आने वाले आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की रणनीति पर कायम है. हालांकि, रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, फिर भी केंद्रीय बैंक ने यह संकेत दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में कमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन अथवा अन्य उपयुक्त साधनों का उपयोग किया जा सकता है. फिलहाल केंद्रीय बैंक का आकलन है कि बैंकिंग प्रणाली में धन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन की तत्काल आवश्यकता नहीं है. पिछले कुछ महीनों के दौरान मनी मार्केट दरों और सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिफल दरों में नरमी आयी है. यह संकेत है कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई है. साथ ही, उद्योग, सेवा और खुदरा-तीनों क्षेत्रों में ऋण मांग संतोषजनक बनी हुई है. यद्यपि, जमा और ऋण दरों के बीच अंतर घटने से कुछ बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआइएम) पर दबाव देखा गया है, फिर भी बैंकिंग प्रणाली की समग्र वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है.

आरबीआइ की सतर्कता का सबसे महत्वपूर्ण कारण वैश्विक आर्थिक वातावरण है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव, वैश्विक व्यापार नीतियों में अनिश्चितता, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियां तथा जलवायु संबंधी जोखिम आने वाले महीनों में महंगाई और विकास, दोनों को प्रभावित कर सकते हैं. भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है. ऐसे में यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि होती है, तो उसका सीधा असर घरेलू महंगाई, चालू खाते के घाटे और राजकोषीय संतुलन पर पड़ेगा. फिलहाल होम लोन, ऑटो लोन तथा अन्य फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋणों की मासिक किस्तों में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. इसी प्रकार, सावधि जमा पर ब्याज दरों में भी तत्काल व्यापक परिवर्तन की उम्मीद कम है. कुल मिलाकर, अगस्त, 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा स्पष्ट करती है कि आरबीआइ ने महंगाई नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है. एक ओर उसने विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती पर भरोसा जताया है, दूसरी ओर संभावित महंगाई जोखिमों को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती से परहेज किया है. साथ ही, पर्याप्त तरलता बनाये रखने का आश्वासन देकर बैंकिंग प्रणाली को विश्वास भी दिया है, किंतु अतिरिक्त नकदी प्रवाह से बचकर मौद्रिक अनुशासन भी कायम रखा है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

शैक्षिक आदान-प्रदान को अमेरिका राजनीतिक रंग दे रहा है

अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट का दावा है कि चीनी छात्रों के लिए वीजा पर रोक लगाने से अमेरिकी छात्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत लाभ होगा. सच तो यह है कि सामान्य शैक्षिक आदान-प्रदान को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाया जा रहा है. अमेरिका के सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की तीन अगस्त को जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले वर्षों की तुलना में मई और अगस्त, 2025 के बीच भारतीय और चीनी नागरिकों को बहुत कम एफ-1 स्टूडेंट वीजा जारी किया. मई-अगस्त का समय इसलिए चुना गया, क्योंकि प्रतिवर्ष इसी अवधि में बड़ी मात्रा में एफ-1 वीजा जारी किये जाते हैं. यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हैं? इस बारे में उपरोक्त रिपोर्ट कोई सबूत नहीं देती है. अमेरिका में छात्र वीजा नीति अत्यधिक विवादित और राजनीतिक मुद्दा बन गयी है. कुछ अमेरिकी जहां शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाये रखने के लिए खुलेपन की वकालत करते हैं, वहीं कुछ भयभीत हैं कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के कारण नौकरी के अवसर कम हो जायेंगे. कुछ जहां अंतरराष्ट्रीय छात्रों को नवाचार को बढ़ावा देने वाले मानते हैं, वहीं कुछ उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं. अमेरिकी राजनीतिक चालों की कीमत निर्दोष अंतरराष्ट्रीय छात्रों को चुकानी पड़ रही है. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग पर निर्भर करती है, जबकि अकादमिक तरक्की विचारों के आदान-प्रदान और उनके मेल-जोल से आगे बढ़ती है. किसी देश को असल में मजबूत दीवारें नहीं, प्रतिभा को आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता बनाती है. जब कोई रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में कमी को जीत बताती है और दावा करती है कि इससे अमेरिकी छात्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लाभ होगा, तो वास्तव में यह दूसरों से किसी खतरे को नहीं, बल्कि अपनी घबराहट को व्यक्त करती है.

गांधी की ऐतिहासिक यात्रा का शताब्दी वर्ष मनाता भागलपुर

कुमार कृष्णन
स्वतंत्र लेखक
kkrishnanang@gmail.com

बिहार का भागलपुर महात्मा गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. यहां वे 1917, 1920, 1925 और 1934 में आये. उनकी भागलपुर यात्राएं आज भी यही संदेश देती हैं कि स्वराज केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता, नैतिक जागरण और मानवीय मूल्यों की निरंतर साधना का नाम है.

भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल सत्ता परिवर्तन का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के नैतिक पुनर्जागरण की विराट गाथा भी है. महात्मा गांधी की बात करें, तो उन्होंने स्वराज को केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति ही नहीं माना, बल्कि उसे सत्य, आत्मसम्मान, मातृभाषा, सामाजिक न्याय, शिक्षा और मानवीय मूल्यों से जोड़कर भी देखा. उनके लिए राष्ट्र का निर्माण नागरिकों के चरित्र और समाज की नैतिक चेतना से होता है. इसी कारण महात्मा गांधी की यात्राएं केवल राजनीतिक अभियान भर नहीं थीं, बल्कि वे भारत की आत्मा से संवाद की यात्राएं थीं. बिहार का भागलपुर गांधी के जीवन का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां वे 1917, 1920, 1925 और 1934 में आये. भागलपुर की उनकी इन चारों यात्राओं का उद्देश्य भले ही भिन्न रहा था, परंतु लक्ष्य एक ही था- भारतीय समाज का नैतिक निर्माण.

पंद्रह अक्तूबर, 1917 को भागलपुर के कटहलबाड़ी में आयोजित बिहारी छात्र सम्मेलन में गांधी ने मातृभाषा को स्वराज की पहली शर्त बताया था. उन्होंने कहा था कि, 'मातृभाषा का अनादर, मां के अनादर के बराबर है.' उनका विश्वास था कि शिक्षा तभी लोकतांत्रिक और सार्थक होगी, जब वह जनता की अपनी भाषा में उपलब्ध होगी. गांधी अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे, बल्कि उस व्यवस्था के विरोधी थे, जो ज्ञान और अवसरों को केवल अंग्रेजी जानने वाले खास वर्ग तक सीमित कर देती है. उन्होंने भारतीय भाषाओं को सांस्कृतिक आत्मविश्वास का आधार माना. आज भारतीय भाषाओं में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के बढ़ते प्रयास महात्मा गांधी की इसी दूरदर्शी सोच की याद दिलाते हैं. भागलपुर की अपनी यात्राओं में उन्होंने केवल भाषा का प्रश्न ही नहीं उठाया, बल्कि सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव को भी राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त बताया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाति और अस्पृश्यता के रहते वास्तविक स्वराज संभव नहीं है. उनका संदेश था कि 'राम और रहीम एक ही सत्य के दो नाम हैं.' धर्म उनके लिए मनुष्य को जोड़ने का माध्यम था, विभाजन का नहीं. सच तो यही है कि विविधताओं का सम्मान ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है. आज जब समाज वैचारिक ध्रुवीकरण, डिजिटल अफवाहों और अविश्वास जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब महात्मा गांधी का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है.

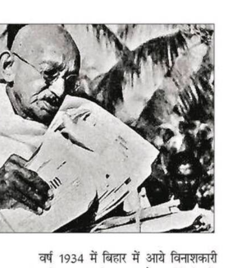

वर्ष 1934 में बिहार में आये विनाशकारी भूकंप के बाद गांधी राहत और पुनर्निर्माण के उद्देश्य से भागलपुर पहुंचे. उन्होंने पीड़ितों के लिए सहायता जुटायी, स्वयं हस्ताक्षर के बदले प्राप्त धनराशि राहत कोष में समर्पित की और हरिजन सेवा को अपने अभियान का केंद्र बनाया. गांधी का मानना था कि पुनर्निर्माण केवल ढही हुई इमारतों का ही नहीं, बल्कि समाज की संवेदना, समानता और विश्वास का भी होना चाहिए. करुणा को उन्होंने राष्ट्र निर्माण का सर्वोच्च मूल्य माना. भागलपुर की यात्रा के कुछ समय बाद गांधी ने 'यंग इंडिया' में अपने प्रसिद्ध 'सात सामाजिक पाप' प्रकाशित किये- सिद्धांतों के बिना राजनीति, मेहनत के बिना धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान तथा बलिदान के बिना उपासना. यदि भागलपुर में उनके संदेशों को एक साथ देखा जाये, तो स्पष्ट होता है कि मातृभाषा का सम्मान, सत्याग्रह, सामाजिक समानता, सांप्रदायिक सद्भाव और करुणा इन्हीं सामाजिक पापों के विरुद्ध उनके व्यावहारिक कार्यक्रम थे.

इस वर्ष भागलपुर महात्मा गांधी की 1925 की ऐतिहासिक यात्रा का शताब्दी वर्ष मना रहा है. यह केवल इतिहास को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि गांधी के विचारों को वर्तमान जीवन में पुनः स्थापित करने का आह्वान भी है. भागलपुर हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सरकारों और संस्थाओं से नहीं बनते, वे विद्यालयों, भाषाओं, समाज की संवेदनाओं और नागरिकों के चरित्र से निर्मित होते हैं. गांधी की भागलपुर यात्राएं आज भी यह संदेश देती हैं कि स्वराज केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता, नैतिक जागरण और मानवीय मूल्यों की निरंतर साधना का नाम है. यही भागलपुर की ऐतिहासिक विरासत है और यही उसकी सबसे बड़ी राष्ट्रीय देन है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

आपके पत्र

कार्यपालक अधिकारियों को भी मिले सुरक्षा

हाल के दिनों में कार्यपालक पदाधिकारियों पर बढ़ते हमले और हत्याओं से प्रशासनिक महकमे में भय का माहौल है. सरकारी योजनाओं को लागू करने और भ्रष्टाचार रोकने वाले ये अधिकारी भू-माफिया व अपराधियों के निशाने पर हैं. यदि सरकारी सेवक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो विकास कार्य ठप हो जायेंगे. सरकार इन अधिकारियों को विशेष सुरक्षा कवर दे. संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को अंगरक्षक तथा कार्यालयों व आवासों पर सुरक्षा बल मुहैया कराये जाएं. साथ ही, प्रताड़ना या धमकी की सूरत में त्वरित कार्रवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बने ताकि अपराधियों में खौफ रहे.

लव राज, (रामनगर)पश्चिम चंपारण

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. एक ही दिन में 8 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य समेत 16 पदक जीतकर भारत ने विश्व खेल मंच पर अपनी मजबूती साबित की है. इस सफलता में महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा. मुक्केबाजी में बेटियों ने इतिहास रचते हुए 5 स्वर्ण जीते, जबकि मुक्केबाजी में कुल 7 स्वर्ण पदक मिले. यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास का परिणाम है. यह स्वर्णिम यात्रा नए और आत्मविश्वासी भारत की कहानी बयां करती है.

युगल किशोर राही, छपरा

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013 ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

हर व्यक्ति को अपने निर्वासन से बाहर निकलने का रास्ता खुद तय करना पड़ता है। -मार्टिन बुबर

माफी और जवाबदेही

मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए हटाए जाने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगना और कंटेंट प्रमोशन में वित्तीय हितों की बात स्वीकारना महज कॉर्पोरेट या तकनीकी गलती नहीं, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल संप्रभुता से जुड़े एक गंभीर प्रश्न की ओर इशारा करता है। उल्लेखनीय है कि ये सोशल मीडिया कंपनियां दुनियाभर में खुद को एक निष्क्रिय मंच बताकर सेफ हार्बर (कानूनी संरक्षण) की मांग करती रही हैं। उनका तर्क होता है कि वे किसी संपादक की तरह कंटेंट का चयन नहीं करतीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं द्वारा डाले गए कंटेंट को स्वचालित एल्गोरिदम के आधार पर दिखाती हैं। जबकि, वास्तविकता यह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म कंटेंट की मेजबानी करने के साथ यह भी तय करते हैं कि कौन-सा कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचेगा, किसे दृश्यता मिलेगी और किसे लगभग अदृश्य ही बना दिया जाएगा। उनके एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं की रुचियों, व्यवहार, क्लिक, देखने के समय, सामाजिक संबंधों व मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके तय करते हैं कि कैसा कंटेंट किस व्यक्ति के सामने रखा जाए। इसी कारण ये प्लेटफॉर्म लोगों की सोच, प्राथमिकताओं और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी देश के प्रधानमंत्री की पोस्ट को हटाने की ताकत रखती है, तो यह चिंताजनक है, पर वास्तविक चिंता इससे कहीं व्यापक है। अगर ये कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि अपने एल्गोरिदम के जरिये अपवादों को मुख्यधारा का विमर्श बना रही हैं, किसी विषय को कृत्रिम रूप से ट्रेंड करा रही हैं या किसी मुद्दे की पहुंच सीमित कर रही हैं, तो वे किसी निर्वाचित सरकार को भी बंधक बना सकती हैं। यह स्थिति सेंसरशिप से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसमें सूचना पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, बल्कि उसकी दृश्यता और प्राथमिकता को अपारदर्शी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और स्वतंत्र पत्रकारिता उतनी ही जरूरी है, जितना फर्जी खबरों

और दुर्भावनापूर्ण प्रचार पर रोक। लोकतंत्र में अपारदर्शी एल्गोरिदम विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। लिहाजा, मेटा की माफी पर्याप्त नहीं है। इससे अधिक आवश्यक यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों। अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार करें, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संचालित हों और अपने प्रभाव को देखते हुए जवाबदेही भी स्वीकार करें।

एक वापसी, कई सवाल

दिल्ली से ऑडियो संदेश जारी कर दिसंबर में अपनी स्वदेश वापसी की घोषणा के साथ शेख हसीना ने साफ कर दिया कि वह कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ढाका के विरोधी सुरों के बीच, भारत के लिए चुनौती यह है कि वह हसीना के प्रति अपने ऐतिहासिक जुड़ाव को बनाए रखते हुए बांग्लादेश के साथ कैसे तालमेल बिठाता है।

1971 में बांग्लादेश के गठन में मदद करने के बाद, ऐसा लगता है कि भारत को इसके उतार-चढ़ाव का हिस्सा बने रहना है। बांग्लादेश की बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो भारत के प्रति खुलकर आभार जताने और उसकी दोस्ती को सबसे अधिक महत्व देने वाली नेता मानी जाती हैं, ने फिर कहा है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह इस साल दिसंबर में अपना दूसरा निर्वासन खत्म कर स्वदेश लौटेंगी। वह वापस लौटने पर हिरासत में लिए जाने (उन्हें सजा और मौत का सामना करना पड़ सकता है) और 'यहां तक कि मारे जाने' के लिए भी तैयार हैं। सुरक्षा कारणों से गुप्त स्थान से मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'अपने लोगों के बीच लौटना मेरा फर्ज है।'

महेंद्र वेद

वरिष्ठ पत्रकार

शायद इसी वजह से या किसी रणनीति के तहत, उन्होंने अपनी सार्वजनिक बातचीत केवल ऑडियो के माध्यम से की, वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लगभग 30 मिनट तक अंग्रेजी में लिखित बयान पढ़ा, ताकि नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरिस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में मौजूद विदेशी मीडिया तक अपनी बात पहुंचा सकें। उनकी जल्द होने वाली 'घर वापसी' से जुड़े इस राजनीतिक और भावुक कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय का वीडियो संदेश भी था। उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए, जिनका जवाब शायद शेख हसीना खुद नहीं देना चाहती थीं। दोनों ने भारत का शुक्रिया अदा किया। जैसी कि अपेक्षा थी, ढाका ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है, जबकि नई दिल्ली ने साफ कहा कि वह ऐसे किसी 'निजी' कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पड़ोसी देश प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों (जो पहले से ही तनावपूर्ण है और जिसे सुधारने की जरूरत है) को किस तरह संभालते हैं।

हसीना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पुराने निर्वासन और वतन वापसी को याद किया। उनका पहला छह साल का निर्वासन दिल्ली में 1975 में शुरू हुआ था, जब उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। मौजूदा निर्वासन के भी इस हफ्ते पांच अगस्त को दो साल पूरे हो गए। इस दौरान उन्होंने विरासत में मिले उस धर्मनिरपेक्ष सपने और राजनीतिक ढांचे के नष्ट किए जाने का विरोध किया, जिसे उन्होंने मजबूत किया था। अब यह तो समय ही बताएगा कि वह इनमें से कुछ भी फिर से बहाल करेंगी या नहीं। हसीना ने बांग्लादेश में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की 'वापसी' को लेकर चेतावनी दी। साथ ही, उन्होंने इस्लामी चरमपंथियों और अल-कायदा के बढ़ते प्रभाव की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि दुनिया को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन, दुनिया को इस्लामी चरमपंथ के बढ़ते असर और उससे भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले खतरे को लेकर कोई खास चिंता नहीं है।

मजबूती से अपना बचाव करने के बावजूद, हसीना को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बांग्लादेश की 'विजेता ही हकदार' वाली हिंसक राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को लेकर कुछ सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। वह अपनी प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा जिया का ही तरीका अपना रही थीं, जिन्होंने भी यही खेल खेला था। हालांकि, हसीना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सत्ता से हटने के बाद हो रही उनकी आलोचना 'चुनिंदा' और एक सुनियोजित 'साजिश' का हिस्सा है। उनका कहना है कि इसमें इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि कैसे उन्होंने अपने देश को आर्थिक तरक्की और बेहतर मानव विकास संकेतकों की अभूतपूर्व राह पर आगे बढ़ाया।

उन्होंने अपने आलोचकों, खासकर अपने 'गैर-कानूनी' उत्तराधिकारी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम लेकर तीखा हमला किया। ढाका में अटकलें हैं कि यूनुस को अगला राष्ट्रपति चुना जा सकता है, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति, जो हसीना के सहयोगी थे, को उनका कार्यकाल खत्म होने में दो साल बाकी रहते हुए ही हटा दिया गया था। यदि ऐसा होता है और तारिक रहमान भी इसके लिए सहमत होते हैं, तो यह फैसला हसीना की संभावित वापसी से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक हालात और अधिक न उलझे।

हसीना ने 2009 से 2024 तक के अपने 15 वर्ष के शासनकाल के दौरान हुई 'गलतियों' को भी माना। उन्होंने बताया कि कैसे नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के विवादित मुद्दे पर प्रदर्शनकारी छात्रों तक उनकी पहुंच की कोशिशें तब नाकाम हो गईं, जब 'अदृश्य ताकतों' के इशारे पर छात्रों ने मांगें बदल दीं। उन्होंने कहा, 'कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों पर सुनियोजित हमले किए गए। अधिकारियों की हत्या कर दी गई। पुलिस स्टेशनों और चौकियों में आग लगा दी गई। हथियार लूट लिए गए। करीब 3,000 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई और उन्हें गंभीर हिंसा का शिकार बनाया गया।' हसीना ने कहा, 'मैं एक सीधा सवाल पूछती हूं। ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों का क्या फर्ज है? क्या राज्य की जनता की जान और संपत्ति की रक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हर देश में, कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि वे नागरिकों, सरकारी संस्थानों और अपनी जान की रक्षा करें। यह कोई अपराध नहीं है। यह वह कर्तव्य है, जो उन्हें कानून द्वारा सौंपा गया है।'

शेख हसीना की संभावित वापसी तारिक रहमान के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यदि वह लौटती हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तारिक रहमान की जिम्मेदारी होगी, चाहे हसीना हिरासत में हों या बाहर। मुख्यधारा की राजनीति में शामिल इस्लामी गुट, चरमपंथी तथा पुराने छात्र नेता, सभी उनके विरोधी हैं। अजीब है कि उनका विरोध करने और खुद भी जबर्दस्त विरोध का सामना करने के बावजूद, तारिक रहमान अपनी मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अवामी लीग के साथ हाथ नहीं मिला सकते। ऐसे में, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वह दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी खेमे के अपने विरोधियों और इस क्षेत्र में वैश्विक ताकतों की चालों का सामना कैसे करते हैं।

कुल मिलाकर, हसीना की 'घर वापसी' की योजना का मकसद तुरंत सत्ता हासिल करना नहीं है। उनकी पार्टी, अवामी लीग, भले ही एक अहम राजनीतिक ताकत रही हो, पर अभी उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और निकट भविष्य में उसके सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि वह बांग्लादेश की राजनीति से अपनी पार्टी के पूरी तरह खत्म होने से पहले उसकी अहमियत बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। अब यह देखना बाकी है कि उनकी वापसी उन्हें एक आरोपी के तौर पर पेश करती है या फिर एक ऐसे प्रतीक के तौर पर, जिसके इर्द-गिर्द बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर ध्रुवीकृत हो सकती है। उनके सामने दो राजनीतिक विरासतों को बचाने की चुनौती है-अपनी खुद की और अपने पिता की। ऐसा करने के लिए, उनके पास अपने लोगों के अलावा और कोई सहारा नहीं है।

विमर्श

छोटा बड़ा सब सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न

संत रैदास की 650वीं जयंती के मौके पर भदोही का नाम 'संत रविदास नगर' करना उनके समता, मानवता और मन की पवित्रता के विचारों को सम्मान देने का ही एक प्रयास है।

गुरु रैदास की जयंती इस बार विशेष उत्सव हो गई। इसलिए कि उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके 650वें जन्मदिन पर 'भदोही' का नाम बदल कर 'संत रविदास नगर' करने की घोषणा की। उत्तर-प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली, बिहार और खासकर पंजाब में गुरु रैदास की चर्चा तेज हो गई है।

संत रैदास ने दोहरे मोर्चों पर दबाव झेले। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक सत्ता के प्रलोभनों और धर्म परिवर्तन के दबावों के बावजूद अपने 'निर्वर्ण संप्रदाय' को मुस्लिम नहीं बनाया। जबकि, अस्पृश्यता की सबसे बड़ी समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन इस्लाम की ओर से उपलब्ध था। रैदास युग में न तो वर्ण बदल पाना संभव था और न पेशा, उन्होंने चर्म कार्य के पेशे को सम्मान की दृष्टि दी। अपनी जाति को हीन भावना से निकाला। *कहे रैदास खलास चमारा* कहते हुए कहीं से भी ऊंच-नीच की भावना से प्रभावित नहीं हुए। निर्गुण भक्ति के मार्ग पर चलकर उन्होंने उपेक्षित मानव गरिमा की रक्षा की। *मन चंगा, तो कठौती में गंगा* कहते हुए उन्होंने मन की पवित्रता को महत्व दिया। उन्होंने जाति, पेशे की पहचान और सम्मान को बचाया, और यह कहने में संकोच का अनुभव नहीं किया कि *मेरी जाति कुटवां ढला ढोर ढोवन्ता, नितहि बनारस आस पासा।।*

श्यौराज सिंह बेचैन

समता-मूलक समृद्ध समाज निर्माण की उनकी संकल्पना में 'बेगमपुरा' की महान अवधारणा है। ऐसे शहर का निर्माण करना, जिसमें कोई गम, दुख-दर्द का नामो-निशान न हो। मनुष्य का स्वभाव ही सेवा और सहयोग की तत्परता से भरा हो। बनारस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, वहीं पर उनके परंपरागत पंडितों से शास्त्रार्थ हुए। उनसे आग्रह किया गया कि यदि तुम ज्ञानी पंडित हो, तो हमें जनेऊ दिखाओ। साहित्य में भी रैदास की महत्ता गैर-दलित कवियों में भी ससम्मान स्वीकार्य हुई। राजघरानों की बहू मीरा, उनकी शिष्या बनीं। राजस्थान की रानी झाली ने तो गुरु को सोने की पालकी-रथ में बिठाकर नगर में उनकी झांकी निकाली। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने 1942 में कविता लिखी-*दृग, तुम्हें श्रद्धा-सलिल से सींच कर। ज्ञान-गंगा में, समुज्ज्वल चर्मकार, चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार।।* रैदास मनुष्यता के सुखों की काल्पनिक दुनिया में ही विचरण नहीं करते थे, बल्कि भौतिक संसार की नई रूपरेखा भी रच रहे थे-फ्रांस की समता, स्वतंत्रता और बंधुता के मूल्यों आधारित क्रांति व साम्यवाद की अवधारणा घोषित होने के करीब चार सौ साल पूर्व वह कह रहे थे-*ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न।।*

रैदास के विचारों ने उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी लोगों को प्रेरणा दी। पंजाब में उनको सिख धर्म में जगह मिली, गुरु ग्रंथ साहिब में चालीस शब्द शामिल किए गए। पंजाबी में बौद्ध धर्म की कम, गुरु रविदास की मान्यता ज्यादा है। डॉ. आंबेडकर के प्रति नाराजगी के चलते रविदासिया समाज बौद्ध नहीं बना। कालांतर में जातिभेद से ही व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। सिखों में अस्पृश्यता का वर्ताव न के बराबर है, किंतु पंजाब में दलित सरदारों को 'गुरु रविदास गुरुद्वारे' अलग बनाने पड़े हैं। गैर-दलित सरदारों के गुरुद्वारों में रविदासिया समाज के सिख नहीं जा सकते। मैंने पंजाबी के प्रसिद्ध दलित लेखक और संपादक बलबीर माधोपुरी के साथ पंजाब के कई गांवों में यह प्रत्यक्ष देखा है।

-लेखक डीयू के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रोफेसर हैं।

प्रकृति हमें शांत भाव से जीवन का आनंद लेने की गहरी क्षमता देकर वृद्धावस्था के लिए तैयार करती है।
-राल्फ वाल्डो इमर्सन

खुद को जानने का वक्त

वृद्धावस्था जीवन का वह पड़ाव है, जहां सभी अशांत भावनाएं शांत हो जाती हैं। जैसे सांझ के सूरज की किरणें अधिक कोमल व सुखद हो जाती हैं, वैसे ही ढलती उम्र की चेतना में एक गहरी शांति और करुणा घुल जाती है।

जीवन के इस संध्याकाल में, जब मेरी अवस्था साठ वर्ष को पार कर चुकी है और दुनिया के कोलाहल से मैं दूर हो चुका हूं, मुझे एहसास होता है कि उम्र का बढ़ना कोई क्षति नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। जब मैंने अपनी पुस्तक *रेवेरीज ऑफ द सोलिटरी वॉकर* की रचना शुरू की, तब मेरा उद्देश्य किसी जगत-कल्याण या दार्शनिक बहस का हिस्सा बनना नहीं था; मैं तो केवल अपने भीतर के उस शांत समंदर को खंगालना चाहता था, जो जवानी के उफनते ज्वार के शांत होने के बाद मुझे प्राप्त हुआ है।

जीन-जैक्स रूसो

जवानी के दिनों में हम महत्वाकांक्षाओं, सामाजिक प्रतिष्ठा और दूसरों के निर्णय के गुलाम बने रहते हैं। पर, ढलती उम्र इन्सान को उसकी मूल प्रकृति की ओर वापस मोड़ देती है। जैसे-जैसे शरीर शिथिल होता है, मन सांसारिक लालसाओं के बोझ से मुक्त होने लगता है। अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है। अब मैं केवल इस बात का साक्षी हूं कि मैं भीतर से क्या महसूस करता हूं। उम्र बढ़ने के साथ जो सबसे सुंदर बदलाव आता है, वह है समय के साथ हमारी एकात्मता। जब मैं प्रकृति की गोद में, किसी झील के किनारे या नीरव जंगलों में टहलता हूं, तो मुझे लगता है कि समय ठहर गया है। मेरे लिए अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं, दोनों बेमानी हो जाती हैं। मैं केवल 'वर्तमान क्षण' की अनुभूति में जीता हूं।

मुड़-मुड़ के देख

मेरे दृष्टिकोण में, यदि आपने प्रकृति के नियमों का सम्मान किया है, तो वृद्धावस्था जीवन का वह पड़ाव है, जहां सभी अशांत भावनाएं शांत हो जाती हैं। जैसे शाम के समय सूरज की किरणें अधिक कोमल और सुखद हो जाती हैं, वैसे ही ढलती उम्र की चेतना में एक गहरी शांति और करुणा घुल जाती है।

मैं मानता हूं कि इन्सान की उम्र केवल उसके शरीर के वर्षों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की स्वतंत्रता से मापी जानी चाहिए। यदि हम उम्र के साथ अपनी लालसाओं पर विजय पा लें और प्रकृति के शाश्वत प्रवाह को स्वीकार कर लें, तो जीवन का अंतिम अध्याय ही सबसे अधिक संतुष्टिदायक और सत्य के सबसे करीब होता है।

ताकि हर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लौटे

वृद्धाश्रम में अगर युवा कुछ घंटे बुजुर्गों के साथ बिताएं, तो यह दोनों पीढ़ियों के लिए सीख और खुशियों का कारण बन सकता है।

वृद्धाश्रम में 'सामाजिक इंटर्नशिप' जैसी पहलों के जरिये युवा न केवल बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के साथ होने जैसा भी महसूस कराते हैं।

वृद्धाश्रम केवल एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि उन असंख्य बुजुर्गों की विवशता का प्रतीक है, जिन्हें जीवन की सांध्य बेला में अपने ही परिवार से दूरी का दर्द सहना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि जब बच्चे अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात करते होंगे, तो शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त हो रहे माता-पिता के ऊपर क्या बीतती होगी? वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को भोजन, दवा और रहने की सुविधा तो मिल जाती है, पर क्या उन्हें अपने बच्चों जैसा अपनापन और प्यार मिल पाता है? शायद नहीं!

परिवार से बिछड़ चुके और उपेक्षित बुजुर्गों को खुशहाल, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से सक्रिय जीवन देने के उद्देश्य से जम्मू के अम्फल्ला स्थित वृद्धाश्रम में एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। इसका मकसद सार्थक संवाद, सहभागिता और अपनत्व के माहौल के जरिये उनके अकेलेपन को कम करना तथा परिवार और समाज से जुड़ाव की भावना को फिर से मजबूत करना है। यहां विभिन्न सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से एक कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसे बाकायदा 'सामाजिक इंटर्नशिप' का नाम दिया है। इस आश्रम का नाम है 'होम फॉर द एजेड एंड इनफर्म', यानी वृद्ध और मानसिक एवं शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए आश्रय स्थल। इसका ध्येय वाक्य है, 'स्क्रीन टाइम-सेवा टाइम', यानी अपने मोबाइल के रील समय को सेवा समय में तब्दील करें।

दस दिन की लघुकालिक इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थी न केवल इन बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के साथ होने जैसा भी महसूस कराते हैं। इस पहल के अंतर्गत विद्यार्थी नियमित रूप से आश्रम जाकर वृद्धजनों के साथ समय व्यतीत करते हैं। उन्हें देश-दुनिया की ताजा खबरों से अवगत कराने के साथ मनोरंजक गतिविधियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के जरिये उन्हें जीने का उद्देश्य प्रदान करते हैं। इसके अलावा, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग व ध्यान भी करवाते हैं।

इन कोशिशों से बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौटती है और उन्हें महसूस होता है कि वे अपने बच्चे के साथ हैं। वहीं, विद्यार्थियों को बुजुर्गों के अनुभवों, संघर्षों व संस्कारों से सीखने, जमीनी स्तर की सेवा तथा राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने का अमूल्य अवसर प्राप्त होता है। इससे बुजुर्गों का आत्मबल तो बढ़ता ही है, साथ ही बच्चों में करुणा, धैर्य, कृतज्ञता, संवेदनशीलता और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। उनकी सहभागिता से आश्रम का वातावरण अधिक आत्मीय, आनंदमय और परिवार जैसा बनता है। बुजुर्ग भी सुबह से ही बच्चों की बाट जोहने लगते हैं।

यह पहल स्पष्ट करती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री या प्रमाण-पत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक तैयार करना भी है। करुणा, धैर्य, कृतज्ञता और बड़ों के प्रति सम्मान जैसे गुण पुस्तकों से नहीं, बल्कि ऐसे अनुभवों से विकसित होते हैं। आज अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएं भी ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देती हैं, जिनमें नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना हो।

-रवि शंकर शर्मा

किलिमंजारो पर काटा 90वें जन्मदिन का केक

डॉ. आर्ट उलेन अपने 90वें जन्मदिन की सुबह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे और उनके गाइड उनके लिए केक काट रहे थे। दरअसल, डॉ. आर्ट उलेन ने माउंट किलिमंजारो की 19,341 फीट ऊंची चोटी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। वह इस पहाड़ को फतह करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। पिछले 15 वर्षों में यह किलिमंजारो की उनकी तीसरी सफल चढ़ाई थी और कुल मिलाकर यह उनका चौथा प्रयास था। उन्होंने अपने 70 के दशक में पत्नी के साथ दो बार यह चढ़ाई पूरी की थी। 85 वर्ष की उम्र में एक बार खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें 17,000 फीट की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा था। चढ़ाई आसान नहीं थी। दवाइयां लेने की वजह से उनका संतुलन प्रभावित होता था, इसलिए उन्हें बहुत संभालकर चलना पड़ता था। रातें इतनी ठंडी होती थीं कि तंबू में रखी पानी की बोतल भी जम जाती थी। अपनी उम्र के लोगों के लिए उनका संदेश है कि जरूरी नहीं कि किलिमंजारो की ही चढ़ाई की जाए। मोहल्ले का एक चक्कर लगाना या किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ना भी इस उम्र में सुकूनदेह और लाभदायक हो सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- *वृद्धकेयर* एक गैर-लाभकारी संस्था (एनजीओ) है, जिसका काम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्ण और बेहतर जीवन प्रदान करना है। यह संस्था पूरे भारत में वृद्धाश्रमों और वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थाओं को स्वयंसेवकों और अन्य संसाधनों से जोड़ने का कार्य करती है। संस्था का उद्देश्य बुजुर्गों की बुनियादी जरूरतों के साथ-साथ उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देना है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट vridhcare.com या 8700851044 पर संपर्क कर सकते हैं।
- *हार्मनी फॉर सिल्वर्स फाउंडेशन* बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यह संस्था बुजुर्गों को 'एक्टिव एजिंग' (सक्रिय बुढ़ापा) के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें आर्थिक सुरक्षा और रिवर्स मॉर्गेज के बारे में जागरूक करती है, और 'हार्मनी सीनियर सिटिजन रन' जैसे कम्युनिटी इवेंट्स आयोजित करके उन्हें सशक्त बनाती है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट harmonyindia.org के जरिये संस्था से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है।

जिंदगी की दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं edit@amarujala.com पर भेज सकते हैं।

ट्राई सख्त : कंपनियों को अब 5जी इंटरनेट स्पीड का देना होगा हिसाब

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पहली बार 5जी नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। अब कंपनियों को 5जी इंटरनेट स्पीड का हिसाब देना होगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि 5जी संसाधनों के बंटवारे के कारण आम यूजर्स को खराब सेवा न मिले।

दूरसंचार कंपनियों को 4जी, 5जी और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग टैरिफ तय करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा, 5जी नेटवर्क स्लाइसिंग आधारित प्लान में नेटवर्क के हर हिस्से को अलग टैरिफ श्रेणी माना जाएगा। कंपनियों को प्रत्येक हिस्से के लिए डाउनलोड और अपलोड स्पीड की अनिवार्य जानकारी देनी होगी। दावे गलत होने पर कार्रवाई होगी। स्लाइसिंग में एक 5जी नेटवर्क को कई वर्चुअल नेटवर्क में बांटा जाता है। हर हिस्से को जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। ब्यूरो

प्रीमियम सेवाओं के लिए भी अलग टैरिफ का रास्ता साफ

सोना 3,800 रुपये उछलकर सात हफ्ते के शीर्ष पर, चांदी 2,100 रुपये महंगी

नई दिल्ली। दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में तेजी रही और 3,800 रुपये महंगा होकर सात हफ्ते के उच्च स्तर 1,53,800 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पहुंच गया।

चांदी की कीमत भी 2,100 रुपये बढ़कर 2,34,800 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। कारोबारियों ने कहा कि रुपये में कमजोरी के कारण घरेलू बाजार में आयातित सराफा महंगा हो गया। कमजोर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड रिटर्न में नरमी के बीच विदेशी बाजार में सोने

में बढ़त ने कीमतों को और सहारा दिया। ईरान के यह कहने के बाद कि होर्मुज से समुद्री यातायात के प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ समझौते पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, इससे हाजिर सोने की कीमत बढ़कर 4,260 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गई। एजेंसी

लोन न चुका पाने पर मोबाइल व लैपटॉप बंद नहीं कर सकेंगे बैंक

मुंबई। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पर्सनल, होम या कार लोन डिफॉल्ट होने पर लेनदारों के मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप लॉक या बंद नहीं कर सकेंगे। नया नियम एक जनवरी, 2027 से लागू होगा।

आरबीआई ने कहा, बैंक केवल उसी उपकरण को बंद कर सकते हैं, जिसे खरीदने के लिए लोन लिया गया है। ऐसे मामलों में भी बैंक शुरुआत में उपकरण को पूरी तरह बंद नहीं कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा, यदि किसी उपकरण पर प्रतिबंध लगाया भी जाता है, तो उसकी जरूरी सुविधाएं जैसे इनकमिंग कॉल, एसएमएस और इमरजेंसी एसओएस फीचर किसी भी हालत में बंद नहीं किए जा सकते। केंद्रीय बैंक को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें कर्ज वसूली के दौरान लेनदारों को धमकाने और उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम करने की बात सामने आई थी। इसके बाद ही केंद्रीय बैंक ने नए निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी

आरबीआई का फैसला : नियम एक जनवरी, 2027 से लागू होंगे

एक्सप्लेनर

क्या डिजिटल कंपनियां कर रहीं ठगी?

क्या आप भी हैं डार्क पैटर्न का शिकार?

आइए समझते हैं क्या होता है डार्क पैटर्न और कैसे गुमराह कर खाली कर रहा आपकी जेब?

अगर आप भी ऑनलाइन फ्लाइट टिकट, राशन खरीदने या मूवी शो बुक करते समय अचानक बिल बढ़कर आने से परेशान हैं, तो डार्क पैटर्न के शिकार बन रहे हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस चालाकी पर कड़ा शिकंजा कसते हुए फिजिक्सवाला, फर्स्टक्राई, जेप्टो, फार्मईजी समेत 7 बड़ी डिजिटल कंपनियों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्या होता है डार्क पैटर्न?

- डार्क पैटर्न किसी ऐप या वेबसाइट का ऐसा भ्रामक और चालाक डिजाइन होता है, जो उपभोक्ता को धोखे में रखकर ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है, जो वह सामान्य स्थिति में कभी न करता।

- इन प्रथाओं को यूजर्स को गुमराह या उन पर अनपेक्षित खरीदारी करने, सेवाओं की सदस्यता लेने या व्यक्तिगत सूचना साझा करने जैसे दबाव बनाने को डिजाइन किया गया है।
- डार्क पैटर्न किसी उपभोक्ता की स्वतंत्र पसंद को धोखा देती है, उसमें हेरफेर करती है या उसे बाधित करती है, जो अनुचित व्यापार प्रथा या भ्रामक विज्ञापन के बराबर है।

डार्क पैटर्न के कुछ प्रकार इस तरह हैं...

- पेमेंट पेज पर अचानक हैंडलिंग चार्ज और मेंबरशिप फीस जोड़ना (ड्रिप प्राइसिंग व बास्केट स्नीकिंग)।
- 24 घंटे का फर्जी टाइमर चला झूठी जल्दबाजी पैदा करना।
- चेकआउट पर स्वतः 10 रुपये का दान जोड़ना और मुफ्त कोर्स के नाम पर जबरन डाटा लेना।
- एड-ऑन न लेने पर अपराधबोध पैदा करने वाले शब्द से यूजर को डराना।
- ऑटो-सब्सक्रिप्शन के साथ प्री-टिकड बॉक्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करना।
- टैक्स समेत दाम दिखाकर अलग से जीएसटी जोड़ना।

ये तरीके अपनाकर बच सकते हैं उपभोक्ता

- **शुरुआती और आखिरी कीमत मिलाएं :** प्रोडक्ट चुनते वक्त दिखा रहे रेट और पेमेंट गेटवे पर दिख रहे अंतिम बिल की तुलना जरूर करें।
- **प्री-टिक्ड बॉक्स हटाएं :** चेकआउट करते समय ध्यान दें कि कोई इंश्योरेंस, डोनेशन या मेंबरशिप का डिब्बा पहले से टिक तो नहीं है।
- **स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें :** अगर किसी साइट पर धोखे से अतिरिक्त चार्ज जुड़ गया है, तो उस पेज का स्क्रीनशॉट और ऑर्डर आईडी संभाल कर रखें।

ठगी पर करें शिकायत

- ठगी होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करें या एनसीएच एप/consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
- जागृति पोर्टल पर किसी वेबसाइट या एप का यूआरएल देकर सीधे सीसीपीए को रिपोर्ट भेजें।
- ठगी की वजह से आपको अगर आर्थिक नुकसान हुआ है, तो दो साल की अवधि के भीतर ई-दाखिल के जरिये जिला उपभोक्ता आयोग में दावा पेश करें। ▪ बोनस डेस्क

न्यूज डायरी

एलआईसी : लाभ 23% बढ़कर 13,492 करोड़

नई दिल्ली। जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का लाभ 2026-27 की जून तिमाही में सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़कर 13,492 करोड़ हो गया। नेट प्रीमियम आय 1.27 लाख करोड़ के पार निकल गई। सॉल्वेंसी अनुपात 2.42 गुना रहा, जो एक साल पहले 2.17 गुना था। ऊंचा सॉल्वेंसी अनुपात दर्शाता है कि कंपनी दावों का भुगतान करने की बेहतर स्थिति में है। एजेंसी

जेप्टो व फर्स्टक्राई समेत 7 कंपनियों पर जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्र ने डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर ग्राहकों को गुमराह करने के मामले में जेप्टो, फर्स्टक्राई और फिजिक्सवाला समेत 7 कंपनियों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार ने राज्यसभा में बताया, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक ऑनलाइन प्रथाओं में शामिल कंपनियों को इसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो

ट्रेंट का मुनाफा 22% बढ़ा, 23 नए स्टोर खुले

नई दिल्ली। टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट ने 2026-27 की जून तिमाही में 22% वृद्धि के साथ 518.07 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। सौंदर्य और फुटवियर उद्योग में तेज बढ़त हुई। कंपनी ने वेस्टसाइड का एक और जूडियो के 22 नए स्टोर खोले। कुल स्टोर्स की संख्या 1,300 से अधिक हो गई है। एजेंसी

एसी, वाशिंग मशीन, स्मार्टफोन से लेकर बर्तनों तक के बढ़ सकते हैं दाम

त्योहारों से पहले धातुओं में तेजी लौटी, महंगे होंगे घरेलू उपकरण

बोनस डेस्क

नई दिल्ली। आगामी त्योहारी सीजन में अगर आप नया टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन या नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। वैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल और आपूर्ति संकट के चलते तांबा, एल्युमीनियम, जिंक और निकल जैसी औद्योगिक धातुओं की कीमतें तेज रफ्तार से बढ़ी हैं।

लंदन मेटल एक्सचेंज पर तांबे का तीन महीने का औसत भाव 1.8 फीसदी तक बढ़कर 14,369.50 डॉलर प्रति टन पहुंच गया, जो 29 जनवरी के बाद का उच्चतम स्तर है। इस खबर के बाद भारत में भी तांबे के भाव 2.56 फीसदी उछलकर 1304.90 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। एक महीने पहले यह 1187.85 रुपये प्रति किलोग्राम था। एल्युमीनियम में भी पांच फीसदी की तेजी आई है।

दरअसल, कांगो ने कॉपर और कोबाल्ट कंसंट्रेट के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और अपने खनिज संसाधनों से अधिक मूल्य बनाए रखने के प्रयासों को तेज करने के तहत उठाया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

प्रमुख धातुओं की कीमतों में लगी आग

धातु	6 अगस्त	6 जुलाई	वृद्धि
तांबा	1304.90	1187.85	9.85%
एल्युमीनियम	282.57	268.92	5.08%
जिंक	329.38	308.34	6.82%
टिन	4879.24	4429.14	10.16%
लेड	164.75	163.41	0.82%

(भाव : रुपये प्रति किलोग्राम में)

कीमतों में तेजी की वजह चीन और अमेरिका भी

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही बाधित हो रही है। इस रास्ते से तांबा, एल्युमीनियम और सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा हिस्सा पास होता है। जिंक के वेयरहाउस स्टॉक्स में साल की शुरुआत से अब तक 75 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

- प्रमुख औद्योगिक धातुओं की कीमतों में तेजी का बड़ा कारण है एआई डाटा सेंटरों और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग। इस वजह से अमेरिका एवं चीन तांबे की अंधाधुंध खरीदारी और जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

आपकी जेब पर असर...8% तक बढ़ेंगे दाम

घरेलू उपकरण और वाहनों के निर्माण में तांबा, स्टील और एल्युमीनियम मुख्य कच्चे माल हैं। जब इन धातुओं के दाम बढ़ते हैं, तो विनिर्माण कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों की जेब पर डालती हैं।

- एयर कंडीशनर के कंडेंसर, कंप्रेसर और वाशिंग मशीन की मोटर में बड़े पैमाने पर तांबे का इस्तेमाल होता है। इसके महंगे होने से कंपनियों की इनपुट लागत 8-10 फीसदी बढ़ गई है, जिससे त्योहारी खरीदारी से ठीक पहले घरेलू उपकरणों के दाम 5 से 8 फीसदी तक बढ़ सकते हैं। ईवी बैटरियों और वायरिंग हार्नेस में तांबे का सस्ता विकल्प नहीं है। बर्तन से लेकर स्मार्टफोन के दाम भी बढ़ेंगे।

डॉलर इंडेक्स में उछाल से रुपया 14 पैसे कमजोर

मुंबई। डॉलर इंडेक्स में मामूली तेजी और अमेरिकी बॉन्ड रिटर्न में बढ़ोतरी के बीच बृहस्पतिवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 95.22 पर बंद हुआ। हालांकि, कच्चे तेल की नरम कीमतों ने रुपये को कुछ हद तक समर्थन दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.13 पर खुला। मिरै एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, डॉलर के मुकाबले रुपये का हाजिर भाव 94.80 से 95.50 के दायरे में रहने के आसार हैं। छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 99.78 के स्तर पर रहा। एजेंसी

बिजली उत्पादन में 65 फीसदी पहुंचेगा एआई का इस्तेमाल

नई दिल्ली। देश के बिजली उत्पादन क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग 2030 तक 35 फीसदी से बढ़कर 65 फीसदी पहुंचने का अनुमान है। द एनर्जी एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव सोसायटी के अध्ययन के मुताबिक, फिलहाल करीब 35 फीसदी बिजली उत्पादक कंपनियों ने अपने मुख्य परिचालन में एआई को अपनाया है और यह संख्या तेजी से बढ़ने का अनुमान है।

अध्ययन के मुताबिक, 2031-32 तक सिर्फ डाटा सेंटर से बिजली की मांग 13.56 गीगावाट तक पहुंच सकती है। यह अध्ययन दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बंगलूरू और चेन्नई की कंपनियों के 250 पेशेवरों के बीच किया गया। एजेंसी

टाटा संस समेत 17 कंपनियों को मिला बड़ी एनबीएफसी का दर्जा

मुंबई। आरबीआई ने टाटा संस समेत 17 कंपनियों को उच्च श्रेणी की एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) सूची में शामिल किया है। टाटा संस को दूसरी बार इस सूची में रखा गया है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पंजीकरण लौटने के आवेदन पर विचार जारी है और सूची में शामिल किए जाने का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने हाल ही में लागू किए गए संशोधित नियमों के तहत एक लाख करोड़ से अधिक संपत्तियों वाली एनबीएफसी को उच्च श्रेणी में रखने का प्रावधान किया है। मार्च, 2026 तक टाटा संस की एकीकृत परिसंपत्तियां दो लाख करोड़ से अधिक थीं। 2022 में पहली बार इस श्रेणी में आने के बाद टाटा संस पर कड़े पूंजी पर्याप्तता, जोखिम और खुलासों के नियम लागू हुए थे। साथ ही, तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने जैसी शर्त भी लगाई गई थी। इसके बाद टाटा संस ने अपने कारोबार में बदलाव किया और एनबीएफसी पंजीकरण को लौटने की अर्जी दी। ब्यूरो

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts amarujala.com/jobs

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में निकली भर्ती

अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन

6777 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 19 अगस्त, 2026
पात्रताएं : मैट्रिक, बारहवीं व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : nfr.indianrailways.gov.in

यूपीएसएसएससी में रिक्तियां ▪ 208 पद

वैज्ञानिक सहायक व अन्य पदों पर करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 17 अगस्त, 2026
योग्यताएं : बीएससी व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : upsssc.gov.in

बैंक ऑफ बड़ौदा ▪ 206 पद

मैनेजर व अन्य पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 26 अगस्त, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : bankofbaroda.bank.in

एनटीपीसी लिमिटेड ▪ 135 पद

डिप्टी मैनेजर के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 20 अगस्त, 2026
वेतनमान : रुपये 70,000 से रुपये 2,00,000 तक
यहां आवेदन करें : ntpc.co.in

एसकेएयू, कुरुक्षेत्र ▪ 60 पद

स्टाफ नर्स व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 21 अगस्त, 2026
योग्यताएं : दसवीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : skau.ac.in

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ▪ 20 पद

एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 12 अगस्त, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : icsi.edu

यहां भी रोजगार की संभावनाएं...

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली : प्रोजेक्ट साइंटिस्ट व प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद खाली।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 17 अगस्त, 2026
- ird.iitd.ac.in

ब्रिक-ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान : सहायक डाटा प्रबंधक व अन्य पदों पर मौके।
- वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 10-17 अगस्त, 2026
- thsti.res.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

शिक्षा तथ्यों का अध्ययन नहीं है, बल्कि सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण है।

एनआईओएस इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026-27

सांख्यिकी, गणित जैसे क्षेत्रों में कॅरिअर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए लाभकारी, 31 अगस्त तक करें आवेदन

राज वर्धन जायसवाल
कॅरिअर एक्सपर्ट

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने नेशनल इंटर्नशिप इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स (एनआईओएस) 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, डाटा साइंस, शोध तथा सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में कॅरिअर बनाना चाहते हैं। इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में वास्तविक सरकारी परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी व्यावहारिक समझ के साथ-साथ पेशेवर कौशल का भी विकास होगा।

▪ आवश्यक योग्यताएं

इस इंटर्नशिप के लिए भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के छात्र आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के दूसरे वर्ष या चौथे सेमेस्टर के वे विद्यार्थी, जिनके पाठ्यक्रम में सांख्यिकी या गणित का कम-से-कम एक विषय शामिल हो तथा जिन्होंने 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, आवेदन के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी, शोधार्थी तथा पिछले दो वर्षों के भीतर स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी कर चुके अभ्यर्थी भी निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

▪ आधुनिक तकनीकों से होंगे परिचित

यह इंटर्नशिप केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों को सरकारी कार्यप्रणाली, आधिकारिक आंकड़ों के उपयोग और आधुनिक डाटा तकनीकों को समझने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को पाइथन प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, वेब स्क्रैपिंग, यूआई/यूएक्स, जीडीपी अनुमान, एसडीजी, सीपीआई, पीएलएफएस, एएसयूएसई, पर्यावरण सांख्यिकी तथा अन्य प्रमुख सांख्यिकीय और डाटा-आधारित परियोजनाओं से जुड़कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

▪ स्टाइपेंड व प्रमाणपत्र

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि

- *भारत और विदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं।*
- *वास्तविक सरकारी परियोजनाओं पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कार्य करने का मौका मिलेगा।*
- *पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स समेत कई क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा।*

चयनित इंटर्न को प्रतिमाह दस हजार रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि दो से छह माह तक होगी। अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार दिल्ली स्थित मुख्यालय या विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

▪ ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार एमओएसपीआई की आधिकारिक वेबसाइट internship.mospi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।

फेलोशिप प्रोग्राम

आईसीएएनएन फेलोशिप-2027

- **पात्रताएं :** सभी देशों और क्षेत्रों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इंटरनेट गवर्नेंस, डीएनएस, साइबर सुरक्षा या आईसीएएनएन की पॉलिसी से जुड़े काम में रुचि हो।
- **आयु-सीमा :** कम से कम 21 वर्ष
- **कार्यक्रम की तिथि :** 13 से 18 मार्च, 2027
- **अंतिम तिथि :** 21 अगस्त, 2026
- **वेबसाइट :** icann.org/fellowshipprogram

आवेदन आमंत्रित

एनआईएसएम रील मेकिंग कॉन्टेस्ट

- **कौन हैं आवेदन के पात्र :** कॉलेज के छात्र, युवा प्रोफेशनल, क्रिएटर्स और फाइनेंसियल एजुकेशन में दिलचस्पी रखने वाले भाग ले सकते हैं।
- **रील की अवधि :** न्यूनतम 50 सेकंड व अधिकतम 160 सेकंड
- **रील का साइज :** 100 एमबी तक
- **आवेदन की अंतिम तिथि :** 30 सितंबर, 2026
- **वेबसाइट :** nism.ac.in/reel-competition-2026

एग्जाम अलर्ट

एमपीपीएससी एसएसई मुख्य परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 08-13 अगस्त, 2026
- परीक्षा में चार सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे और एक-एक सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध लेखन के पेपर होंगे। हिंदी निबंध लेखन के पेपर की अवधि दो घंटे व बाकी सभी पेपर की तीन-तीन घंटे निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/33dee7vy

अंतरराष्ट्रीय पहल

एएसईएफ लिंकअप प्रोग्राम

- **पात्रताएं :** कला एवं संस्कृति क्षेत्र के पेशेवर हों, जिनके पास कम से कम पांच वर्षों का अंतरराष्ट्रीय अनुभव हो और जो क्यूरेशन, शोध, कला प्रबंधन, अकादमिक या सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हों।
- **आयु-सीमा :** न्यूनतम 21 वर्ष
- **अंतिम तिथि :** 27 अगस्त, 2026
- **आवेदन लिंक :** tinyurl.com/v7zp9zvd

वीकली जीके

1. पीएम-प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना
(b) किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना
(c) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल-2026 से सम्मानित किया गया?
(a) गगनदीप कांग (b) अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम
(c) टेसी थॉमस (d) माइलस्वामी अन्नादुरई

3. एस8000 बैंडरॉल क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है?
(a) इस्राइल (b) यूक्रेन
(c) रूस (d) फ्रांस

4. दिखो नदी किस नदी की सहायक नदी है?
(a) गोदावरी (b) ब्रह्मपुत्र
(c) कृष्णा (d) कावेरी

उत्तर : 1.a, 2.b, 3.c, 4.b

आज का दिन

7 अगस्त, 1959

फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अमेरिकी मानवरहित उपग्रह एक्सप्लोरर-6 प्रक्षेपित किया गया था। पृथ्वी की तस्वीर लेने वाला यह पहला उपग्रह था।

- **1941 :** नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था।
- **1947 :** नॉर्वे के थोर हेअरडाहल ने लकड़ी की नाव से 4,300 मील की समुद्री यात्रा पूरी की।
- **1955 :** हिंदी सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर का जन्म हुआ था।
- **1960 :** कोटे डी आइवर को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी।

व्रत त्योहार

आज : श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी।
कल : वर्षा ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, उत्तर गोले।
राहुकाल : प्रातः 09.00 से 10.30 तक।

सूर्योदय : 05.50
सूर्यास्त : 19.03
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 17 श्रावण मास शक 1948, श्रावण मास 24 प्रविष्टे, 24 सफर हिजरी 1448, श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी 13.59 तक उपरांत एकादशी, रोहिणी नक्षत्र 16.50 तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र, ध्रुव योग 09.01 तक उपरांत व्याघात योग 29.37 तक तदोपरांत हर्षण योग, विष्टि (भद्रा) करण 13.59 तक उपरांत बव करण, चंद्रमा मिथुन राशि में 27.46 बजे।

राशिफल

amarujala.com/astrology ▪ पं. विनोद त्यागी

मेष : मानसिक तनाव बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहनशीलता बनाए रखें। किसी घनिष्ठ से मनमुटाव हो सकता है।

वृष : प्रभावी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा। स्वविवेक से अटका कार्य बनेगा।

मिथुन : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णय लेने में सावधानी बरतें। जमीनी कार्यों में उत्तम लाभ हो सकता है।

कर्क : भाग्य सहायक रहेगा। योजना में सफलता मिलेगी। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। घर में आनंद रहेगा।

सिंह : राजकाज में परेशानी होगी। विरोधी पक्ष से सचेत रहें। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा।

कन्या : सकारात्मक सोच बनाए रखें। परेशानी का हल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें।

तुला : वाणी पर नियंत्रण रखें। अनुकूल सूचना मिल सकती है। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे।

वृश्चिक : पूर्वनियोजित कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति हो सकती है। सुख साधनों पर व्यय होगा।

धनु : राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। कानूनी मामला सुलझ सकता है। नौकरी में दबदबा बना रहेगा।

मकर : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में आपकी प्रशंसा होगी। अटका धन मिल सकता है। स्वजन सहयोग मिलेगा।

कुंभ : मानसिक तनाव से बचें। योजना में स्वविवेक से सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है।

मीन : लोकप्रियता में वृद्धि होगी। नई योजना में व्यस्त रहेंगे। भू-संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। मित्र सहायक रहेंगे।

सुडोकू

					4		7	
	2	4				8		9
6	8			7				
3		8		1	6	5		4
4			5		9			8
5		2	7	4		6		1
				6			1	7
1		5				9	4	
	6		4					

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

9	5	3	6	8	4	1	7	2
7	2	4	1	5	3	8	6	9
6	8	1	9	7	2	4	5	3
3	7	8	2	1	6	5	9	4
4	1	6	5	3	9	7	2	8
5	9	2	7	4	8	6	3	1
8	4	9	3	6	5	2	1	7
1	3	5	8	2	7	9	4	6
2	6	7	4	9	1	3	8	5

दैनिक जागरण
आचरण व्यक्तित्व का दर्पण होता है

एनटीए में सुधार

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट के पेपर लीक होने के बाद इसे आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज में सुधार किया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। यह ठीक है कि बीते दिनों एनटीए के लिए अस्थायी रूप से काम करने वाले कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हटाया गया और उसके प्रशासनिक ढांचे को मजूबत बनाने के लिए महाप्रबंधक तथा उसके समकक्ष स्तर के पदों की भर्ती के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उचित यह होगा कि इन कदमों के संदर्भ में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स से भी विचार-विमर्श किया जाए। और भी उचित यह होगा कि इस टास्क फोर्स को अपना काम शीघ्र शुरू करने को कहा जाए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि यह टास्क फोर्स अपनी सिफारिशें कब तक देगा। इसके लिए कोई समयसीमा तय की जानी चाहिए। आवश्यक यह भी है कि उसकी ओर से जो सुझाव दिए जाएं, उन पर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित किया जाए। यह एक तथ्य है कि एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए राधाकृष्णन समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन सभी पर अमल नहीं किया गया। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिशों पर भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। शायद इस सबका ही परिणाम यह रहा कि एनटीए नीट के साथ अन्य केंद्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने में नाकाम रही। इसी नाकामी का नतीजा छात्रों के उस आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसके चलते शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। इस त्यागपत्र के बाद पेपर लीक रोधी कानून में संशोधन कर उसे और कठोर भी बनाया गया।

निःसंदेह परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले तत्वों को हतोत्साहित करने के लिए संबंधित कानून को कठोर करना ही चाहिए, क्योंकि देश में एक पेपर लीक माफिया पैदा हो गया है, लेकिन इसी के साथ इसके उपाय भी करने चाहिए, जिससे पेपर लीक ही न हो सके। ऐसा तब होगा, जब एनटीए और इस जैसी अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली में अपेक्षित बदलाव होंगे। यह साधारण बात नहीं कि पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूली परीक्षाओं में भी सेंध लग रही है। इसे देखते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को न केवल उन्नत तकनीक को अपनाना चाहिए, बल्कि प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार करने जैसे कदम भी उठाने चाहिए। नीट जैसी जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों छात्र बैठते हैं, उन्हें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। आवश्यक केवल यह नहीं है कि एनटीए की कार्यप्रणाली सुधरे, बल्कि यह भी है कि किसी भी स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराने वाली संस्थाओं का कामकाज ऐसा हो कि परीक्षार्थियों के मन में परीक्षाओं की शुचिता को लेकर कोई संदेह न रहे।

आस्था संग अनुशासन भी

देवभूमि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और जनसहभागिता की परीक्षा भी है। इस वर्ष सरकार और प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने को व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वयं हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के बीच जाकर उनका स्वागत करना और व्यवस्था का निरीक्षण करना, यह संदेश देता है कि सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इससे श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत हुआ है। प्रशासन की सख्ती और सतर्कता का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो अब तक पूरी कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित हो रही है। यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और निगरानी तंत्र ने यात्रा को व्यवस्थित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रभावी योजना और समय पर कार्रवाई से बड़ी धार्मिक यात्राओं का सफल संचालन संभव है। यद्यपि, केवल प्रशासनिक व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है। प्रशासन को जहां नियमों का पालन कराते समय संयम, संवेदनशीलता और संवाद का परिचय देना होगा, वहीं श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि कांवड़ यात्रा धर्म, श्रद्धा और आत्मसंयम की यात्रा है, न कि शक्ति प्रदर्शन अथवा हुड़दंग का अवसर। यातायात नियमों का पालन और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना भी धार्मिक आचरण का ही हिस्सा है।

> कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित बनाने को प्रशासन और श्रद्धालु, दोनों के स्तर पर प्रयास जरूरी हैं

मंदिर प्रबंधक तैयार करने का समय

विकास सारस्वत

राम मंदिर में दान की चोरी धर्म की विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्थापन की असफलता हैं। इसलिए समाधान मंदिर को कारपोरेट तरीके से चलाना नहीं हैं

अवधेश राजपूत

रामजन्मभूमि मंदिर अपनी प्राण-प्रतिष्ठा के मात्र दो वर्षों के भीतर ही संस्थागत विफलता के एक अप्रत्याशित उदाहरण के रूप में सामने आया है। यहां चढ़ावा चोरी के मामले से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें यह बात विशेष रूप से चिंताजनक है कि यह घटना एक ऐसे मंदिर में घटी, जो सैकड़ों वर्षों के कड़े संघर्ष, अनेक लोगों के बलिदान और करोड़ों व्यक्तियों के दान के फलस्वरूप बना है। अयोध्या के अलावा बदरीनाथ धाम-उत्तराखंड और अंबाजी मंदिर-गुजरात के दान-पात्र से भी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। इतने प्रसिद्ध और संसाधन-संपन्न मंदिरों में गहन निगरानी के बावजूद प्रबंधन की विफलता अन्य मंदिरों में भी चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंकाओं को जन्म देती है। अयोध्या में हुए दुखद घटनाक्रम के बाद एक मुखर प्रतिक्रिया यह आई है कि मंदिरों को कारपोरेट सरीखे पेशेवर तरीके से चलाया जाए। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आइएएस नृपेंद्र मिश्रा ने सीईओ नियुक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने इस पदाधिकारी के सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की अपेक्षा की।

हालांकि दोनों ही मत इसकी अनदेखी करते हैं कि मंदिर न तो विशुद्ध रूप से व्यवसाय है और न ही सरकारी उपक्रम। यह अवश्य है कि जवाबदेही में सुधार के लिए दान की गणना में पारदर्शिता, नियमित कार्य आडिट, विस्तृत नियमावली और खातों की संपूर्ण जांच जैसी कार्यप्रणाली बने। गणना कक्षों में छेड़छाड़-रोधी प्रणाली, सीसीटीवी, आरएफआइडी टैग युक्त दान-पेटियां और बड़े चढ़ावों के लिए ब्लाकचेन जैसी अपरिवर्तनीय लेखा-प्रणाली ऐसा अंकेक्षण मार्ग बना सकती है, जिसे कोई दुर्जन आसानी से धोखा नहीं दे सकता। एक अलग संग्रहालय में ऐसे बहुमूल्य चढ़ावे को सीमित अथवा दीर्घकाल के लिए प्रदर्शित भी किया जा सकता है। तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण और सरल भाषा में सारांश सहित विस्तृत लेखा रिपोर्टों को हर तिमाही वेबसाइट पर डालने जैसे बहुत से कदम उठाए जा सकते हैं, जो दानदाताओं एवं श्रद्धालुओं में विश्वास का भाव बनाएं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और गुरुवायुर जैसे कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बनी भी हुई है। यह भी स्मरण रहे कि मंदिर न तो कोई ऐसी कंपनी है जो शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करे और न ही वह शासकीय दायित्व का भाग है, जो सरकार के जनकल्याण उद्देश्यों की पूर्ति करे।

मंदिर एक जीवंत धार्मिक संस्था है, जिसकी वैधता उतनी ही मात्रा में अनुष्ठानिक शुद्धता, परंपरा और पवित्रता पर टिकी है, जितनी आर्थिक शुचिता पर। अतः कारपोरेट प्रबंधन को ज्यों का त्यों मंदिरों पर थोपने के बजाय एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो आडिट, प्रौद्योगिकी, आंतरिक नियंत्रण, पेशेवर वित्त प्रबंधन जैसे आधुनिक प्रशासकीय उपकरणों को आगम शास्त्र और धार्मिक व्यवस्था के अधीन रखे। मंदिर के अपने अनुष्ठानों पर अधिकार का स्रोत आगम शास्त्र यानी परंपराएं हैं। वे ऐसे संहिताबद्ध शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो विभिन्न संप्रदायों के मंदिरों के लिए भिन्न प्रकार के प्रविधान निश्चित करते हैं। जैसे वैष्णव मंदिरों के लिए पाञ्चरात्र और वैखानस आगम, शैव मंदिरों के लिए कामिक, करण और भैरव आगम और शाक्त संप्रदायों के लिए शक्ति आगम। ये कोई आंतरिक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाएं' यानी एसओपी नहीं हैं, जो प्रबंधन की दक्षता को निरूपित करें, बल्कि ये मंदिर का अपना संवैधानिक कानून हैं। यदि किसी सीईओ को धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण के बिना मंदिर संचालन का अधिकार दिया जाए, तो वह भली मंशा के बावजूद प्रतिष्ठित इष्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। वह ऐसे परिवर्तन कर सकता है, जो स्वयं देवता की प्राण-प्रतिष्ठा की पवित्रता को निरस्त कर दे। कुछ इसी प्रकार का दोष सरकारी बोर्डों के मत्थे लगता है, जो परंपराओं की विशिष्टताओं के विपरीत विभिन्न मंदिरों पर एक समान मंदिर-प्रबंधन नियम थोप इस विविधता को रौंद देते हैं। आगमिक मंदिरों में ऐतिहासिक रूप से सत्ता का एक अंतर्निहित पृथक्करण रहा है। केवल अर्चक या पुजारी ही पूजा-अनुष्ठान कर सकता है। मंदिर वास्तु-संरक्षक, मंदिर की संरचना एवं उसकी शिल्प शास्त्रीय अनुरूपता सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार लौकिक ट्रस्टी जो कभी राजा होते थे, मंदिर के भौतिक रखरखाव, भूमि, कोष, सुरक्षा एवं विवाद निस्तारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह विखंडन आध्यात्मिक और भौतिक सत्ताओं को एक ही शक्ति में केंद्रित होने से रोकता था, पर एक सर्वशक्तिमान सीईओ पुनः ऐसे त्रुटिपूर्ण केंद्रीकरण को जन्म दे सकता है। अल्पकालिक अवधि में ऐसे ट्रस्टियों का चयन जो आधुनिक प्रबंधन के साथ आगम शास्त्रों के भी ज्ञाता हों, थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा।

वर्तमान परिस्थितियों का उपयोग एक ऐसे अवसर के रूप में किया जा सकता है, जो बिजनेस मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट की शैली पर टैंपल मैनेजमेंट यानी मंदिर-प्रबंधन के लिए कार्यकारी तैयार करे। तिरुपति या अयोध्या जैसे बड़े मंदिर ऐसे संस्थान खड़े करने का बीड़ा उठा सकते हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य ऐसे मंदिर प्रबंधकों का विकास होना चाहिए, जिनमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता के साथ आधुनिक प्रबंधन की कुशलताएं हों। अर्चकों के लिए चर्या पाद, परिचारकों और स्थानिकों के क्रिया पाद, अध्येताओं एवं कलाकारों के लिए ज्ञान पाद व सभी के लिए योग पाद की अनिवार्यता वैसी आचरण संहिता हैं, जो प्रबंधन और मानव संसाधन को व्यावहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित कर सकती हैं। अयोध्या में हुई चोरी धर्म की विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्थापन की विफलता है। इसलिए समाधान यह नहीं होना चाहिए कि मंदिर का कारपोरेट अधिग्रहण हो। न ही यह कि परंपरा के नाम पर मंदिरों की विशाल भौतिक संपत्ति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। समाधान वह है, जिसका आदर्श स्वयं आगमों ने सदियों पहले प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक सत्ता को भौतिक प्रशासन से पृथक रखा जाए और प्रशासन को इस प्रकार उत्तरदायी बनाया जाए, ताकि मंदिर की गरिमा पर आंच न आए।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

जजों की संख्या बढ़ाना कितना कारगर

जगदीप सिंह

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित न रहे। उच्च न्यायालयों में भी जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट तक संभव नहीं हर किसी की पहुंच। फाइल

बीते दिनों संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यह बदलाव केवल पदों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव लंबित मामलों के निस्तारण पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग 92,000 मामले लंबित हैं। वर्तमान में सीमित संख्या में जज होने के कारण प्रतिदिन सीमित मामलों की ही सुनवाई हो पाती है। अनेक महत्वपूर्ण अपीलें और याचिकाएं महीनों तक सूचीबद्ध होने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। अतिरिक्त चार न्यायाधीशों की नियुक्ति से एक साथ अधिक खंडपीठों का गठन संभव होगा। संविधान पीठों पर भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने का गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनेक संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मामले पांच, सात या नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। न्यायाधीशों की सीमित संख्या के कारण ऐसी पीठें अपेक्षाकृत कम ही गठित हो पाती हैं। अतिरिक्त जज उपलब्ध होने से मुख्य न्यायाधीश नियमित रूप से संविधान पीठों का गठन कर सकेंगे। इससे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय आएंगे। परिणामस्वरूप कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी और अन्य अदालतों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे। उनसे आने वाले मामलों पर भी इसका प्रभाव होगा।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं। इन न्यायालयों से बड़ी संख्या में अपीलें और विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी होती है तो राज्य स्तर पर भी अनिश्चितता बनी रहती है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से इन अपीलों का निस्तारण अधिक तेजी से हो सकेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर मामलों में शीघ्र अंतिम फैसला आने से राज्यों में न्यायिक प्रक्रिया भी गति पकड़ेगी। इससे नागरिकों को राज्य स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय प्राप्त करने में लगने वाला कुल समय कम होगा। आम नागरिकों के जीवन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक सार्थक होगा। संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामले, आपराधिक अपीलें तथा मौलिक अधिकारों से जुड़े मुकदमे अब लंबे इंतजार के बजाय अधिक समयबद्ध तरीके से निपट सकेंगे।

जो लोग वर्षों से मुकदमेबाजी का खर्च उठाते-उठाते थक चुके हैं, उन्हें राहत मिलेगी। बार-बार अदालत में तारीख पर उपस्थित होने की मजबूरी कम होगी। न्याय अधिक सुलभ, त्वरित और व्यावहारिक प्रतीत होगा। आर्थिक क्षेत्र पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक विवाद, अनुबंध संबंधी मामले और निवेश से जुड़े मुकदमे लंबे समय तक लंबित रहने से अनिश्चितता बनी रहती है। इसके कारण कंपनियां और उद्यमी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामलों का शीघ्र निस्तारण होने से व्यापारिक वातावरण में सुधार होगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

जब लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अधिक गति और दक्षता के साथ कार्य कर रहा है तो न्यायिक व्यवस्था पर उनका विश्वास और मजबूत होगा। साथ ही न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार कम होने से निर्णयों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। हालांकि न्यायाधीशों की संख्या में यह वृद्धि केवल सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उच्च न्यायालयों और जिला स्तर की अदालतों में भी जजों की संख्या बढ़ाने तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता है। यदि उच्च न्यायालय मजबूत होंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक अनावश्यक अपीलें कम पहुंचेंगी। इससे सुप्रीम कोर्ट अपना अधिक समय संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर केंद्रित कर सकेगा।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ डिजिटल सुविधाओं का बेहतर उपयोग भी संभव होगा। ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और केस मैनेजमेंट सिस्टम अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। इससे दूरदराज के राज्यों से आने वाले पक्षकारों और अधिवक्ताओं को भी सुविधा मिलेगी। वैसे केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। योग्य, अनुभवी और समर्पित न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। इसके साथ ही न्यायालयों के बुनियादी ढांचे और सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना होगा तभी इस वृद्धि का पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त तारीख पर तारीख के सिलसिले को भी रोकना होगा। यह समझा जाए कि जितना आवश्यक सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना है, उतना ही अन्य न्यायलयों से भी, क्योंकि न तो हर मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचता है और न ही हर कोई वहां तक जा सकता है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अहंकार से मुक्ति

मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि उसकी वृत्ति से प्रकट होता है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि आसुरी वृत्ति का मूल कारण अहंकार, असीम कामनाएं, क्रोध और स्वार्थ है। ऐसा व्यक्ति कर्मफल के शाश्वत सिद्धांत और ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है और यही भ्रम उसके पतन का कारण बनता है।

आसुरी वृत्ति का सबसे बड़ा लक्षण है निरंतर तुलना और प्रतिस्पर्धा। ऐसा व्यक्ति अपनी सफलता का मूल्य अपने गुणों से नहीं, बल्कि दूसरों से अधिक धन, पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करने से निर्धारित करता है। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। आज जो उसके पास है, उसमें उसे आनंद नहीं मिलता, उसका सुख सदैव उस वस्तु में छिपा रहता है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई। परिणामस्वरूप वह जीवन भर उपलब्धियों के पीछे दौड़ता है, परंतु संतोष और शांति से वंचित रहता है।

दूसरा प्रमुख लक्षण है दूसरों को प्रतिद्वंद्वी मानना। आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति हर सफल व्यक्ति में अपना शत्रु देखता है। उसकी प्रसन्नता दूसरों के दुख से जुड़ जाती है। यही कारण है कि आसुरी प्रवृत्ति आत्मविनाश का मार्ग बन जाती है। इसके विपरीत दैवी वृत्ति वाला व्यक्ति करुणा, विनम्रता, संतोष और परोपकार को जीवन का आधार बनाता है। वह दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता, उनके सुख में अपना सुख खोजता है। वास्तविक विजय दूसरों को पराजित करने में नहीं, अपने भीतर के लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय प्राप्त करने में है। जब मनुष्य तुलना के स्थान पर संतोष, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और स्वार्थ के स्थान पर सेवा को अपनाता है, तभी उसके भीतर दैवी चेतना का उदय होता है। यही मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मुकेश ऋषि

जीवन बचाने में सक्षम सही जानकारी

डा. मोनिका शर्मा

दिल्ली पुलिस द्वारा बनाया गया 'से हेल्प' एप आपातकालीन स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया हैं

बीते दिनों दिल्ली पुलिस की 'से हेल्प' एप ने एक महिला अधिवक्ता का जीवन सहेजने में मदद की। दिल की बीमारी के कारण अचानक जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तब वह घर पर अकेली थीं। असहनीय दर्द के बीच रसोई में फर्श पर गिर गईं तो उन्होंने दिल्ली पुलिस की 'से हेल्प' एप पर मदद मांगी। यह एप दिल्ली पुलिस के सहयोग से महिलाओं, बुजुर्गों और आमजन की इमरजेंसी सुरक्षा के लिए काम करता है। विशेष तरह के वायस-एक्टिवेटेड यानी आवाज से चलने वाले इस सुरक्षा एप से आपातकालीन स्थितियों में सहायता ली जा सकती है।

चिंतनीय है कि स्मार्टफोन में तरह-तरह के एप भरे होने के बावजूद सही उपयोग से जुड़ी सजगता के प्रति यूजर्स उदासीन ही रहते हैं। जबकि किसी भी एप के उपयोग को ठीक से समझने से ही समय पर उसका उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस द्वारा बनाया गया 'से हेल्प' एप भी आपातकालीन स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। इस एप से जुड़कर कोई भी सहायता मांग सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की महिला वकील के मामले में भी जीवन सहेजने से जुड़ी सबसे अहम बात 'से हेल्प' एप के बारे में सही जानकारी होना भी रही।

तकनीकी तरक्की के इस दौर में देश में भी इमरजेंसी में मदद लेने के लिए कई एप हैं। कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी अहम आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत कर 112 इंडिया एप लांच किया गया है। किसी भी संकट में यह एप त्वरित मदद के लिए यूजर की मौजूदगी की सटीक जगह की जानकारी के साथ ही नजदीकी आपातकालीन केंद्र और मदद के लिए पंजीकृत संपर्कों को एक साथ अलर्ट भेजता है। इसमें खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की तत्काल सहायता के लिए 'शाउट' सुविधा भी शामिल है। 'शाउट' फीचर को सक्रिय करते ही आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के पास अलर्ट पहुंच जाता है, जिससे आस-पास मौजूद रजिस्टर्ड वालंटियर्स से मदद मिल पाती है।

हमारे यहां आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए कई सरकारी और निजी एप हैं। परंतु जीवन रक्षक एप्स की सही जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है। आम यूजर्स को इंटरनेट मीडिया के अजब-गजब सामग्री देखने में समय लगाने के बजाय इन एप्स की कार्य प्रणाली समझनी चाहिए। यह समझ और सजगता अपनी ही नहीं, दूसरों की मदद करने में भी काम आती है। भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा ही नहीं, सामुदायिक सुरक्षा को लेकर अलर्ट करने वाले एप्स भी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आधिकारिक एप 'सचेत' प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से जुड़ी चेतावनियां देता है। यह सुविधा आमजन को प्राकृतिक आपदाओं के संभावित खतरों के बारे में पहले से सतर्क करता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

संवाद से दूर हों विवाद

'गतिरोध से ग्रस्त संसद' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में देश की सबसे बड़ी जनप्रतिनिधि संस्था के रवैये को उचित ही रेखांकित किया गया है। संसद लोकतंत्र का वह सर्वोच्च मंच है, जहां महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, संवाद और निर्णय होता है, किंतु राजनीतिक टकराव के कारण संसदीय कार्यवाही का बार-बार बाधित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों की समीक्षा करना है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी विपक्ष की बात सुनना और आवश्यक मुद्दों पर जवाब देना है। विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, किंतु हर मुद्दे पर सदन को बाधित करना अलोकतांत्रिक है। दुर्भाग्य यह है कि आज कई बार वास्तविक मुद्दों पर सार्थक बहस की जगह राजनीतिक नारेबाजी और गतिरोध हावी हो रहा है। संसद की गरिमा को बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक मतभेद के स्थान पर संवाद और सहयोग का मार्ग अपनाना चाहिए।

himanshushekhar.mca@gmail.com

संसदीय व्यवस्था में असहमति

गुरुवार को प्रकाशित ए. सूर्यप्रकाश का विचारोत्तेजक लेख "अराजकता का पर्याय न बने असहमति" वर्तमान भारतीय संसदीय लोकतंत्र के मर्म को छूता हुआ एक अत्यंत सामयिक, दिशा-निर्देशक और विचारणीय आलेख है। लेखक ने अत्यंत निष्पक्षता और सूक्ष्मता से असहमति और अराजकता के मध्य की उस महीन रेखा को रेखांकित किया है, जिसे आज की राजनीति में प्रायः धुंधला कर दिया जाता है। संसदीय व्यवस्था में असहमति लोकतंत्र की आत्मा और प्राणवायु है। सरकार की नीतियों की आलोचना, प्रश्न पूछना और रचनात्मक विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र को जीवंत एवं जवाबदेह बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। किंतु जब यही विरोध संसदीय सीमाओं को लांघकर कार्य स्थगन, शोर-शराबे और वेल में नारेबाजी का रूप ले लेता है, तो असहमति अपना मूल चरित्र खोकर अराजकता में बदलने लगती है। डा. बीआर अंबेडकर ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जब संवैधानिक रास्ते खुले हों, तब असंवैधानिक या अमर्यादित तरीकों का सहारा लेना लोकतंत्र के लिए घातक है। संसद केवल राजनीतिक टकराव का अखाड़ा नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं, समस्याओं और राष्ट्र-निर्माण के कानूनों को स्वरूप देने वाला पवित्र मंच है। गतिरोध और हंगामे से न केवल समय और टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद होता है, बल्कि जनहित के गंभीर विषय भी बिना किसी ठोस चर्चा के लटक जाते हैं। सशक्त लोकतंत्र की नींव सत्ता पक्ष की उदारता और विपक्ष के विवेकपूर्ण आचरण पर टिकी होती है। सत्ता पक्ष को जहां असहमति के प्रति सहिष्णु और स्वस्थ बहस के लिए तत्पर रहना चाहिए, वहीं विपक्ष का यह दायित्व है कि विरोध का माध्यम 'संवाद और तथ्य' बने। विरोध में भी गरिमा, संवाद में भी समाधान और असहमति में भी राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए।

मनोज वशिष्ठ, रेवाड़ी, हरियाणा

मेलबाक्स

मुद्रा प्रणाली का आधुनिकीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में पालिमर नोटों को लागू करने की तैयारी भारतीय मुद्रा प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रारंभिक चरण में 10 और 20 के पालिमर नोट जारी किए जाएंगे। इनका विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। यह कदम नकली नोटों पर नियंत्रण, मुद्रा की गुणवत्ता में सुधार और छपाई पर होने वाले सरकारी खर्च को कम करने में सहायक हो सकता है। पालिमर नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। ये पानी, नमी, गंदगी और बार-बार उपयोग से जल्दी खराब नहीं होते। इनमें पारदर्शी विंडो, होलोग्राम और उन्नत सुरक्षा फीचर्स जोड़ना भी आसान होता है। विश्व के 60 से अधिक देशों में इनका उपयोग हो रहा है। भारत में पहले व्यापक फील्ड ट्रायल आवश्यक है।

हेमंत कुमार, हवाई नगर, रांची

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाषः नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

11 सेटेलाइट हैं भारत के अपने 'नाविक' के पास जिनमें से आठ ही सक्रिय हैं, जबकि चीन के 'बैदाऊ' के पास 56 सेटेलाइट हैं, और अमेरिका के सबसे जाने माने 'जीपीएस' के पास केवल 33 सेटेलाइट हैं। ये सभी नेविगेशन से जुड़े सेटेलाइट हैं।

राहुल पाण्डेय
शोधार्थी, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली

आजकल

अंतरिक्ष में वर्चस्व कायम करने की होड़

आधुनिक विश्व एक ऐसी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है जिसमें चीन और अमेरिका के बीच बहुआयामी होड़ सबसे प्रमुख है। इस बीच भारत के पास अपनी राजनीतिक स्थिति और व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वयं को ताकतवर बनाने का एक बड़ा अवसर भी दिख रहा है। वस्तुत: हाल के कुछ सफल सैटेलाइट प्रक्षेपण दर्शाते हैं कि भारत के पास एक अच्छा मौका है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र को विकसित करे, जिससे वर्तमान और भविष्य के हित सुरक्षित किए जा सकें

अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए कई विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फाइल

बीता माह यानी जुलाई 2026 तीन बड़े अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े मामलों का गवाह बना। सबसे पहले जुलाई 10 को चीन के चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलाजी कारपोरेशन ने अमेरिका के स्पेस एक्स के फाल्कन नाइन और ब्लू ओरिजिन की बराबरी कर ली। चीन के लांग मार्च 10बी राकेट जो कि दोबारा प्रयोग में लेने वाली राकेट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद उसकी अंतरिक्ष तकनीक में कहीं अधिक मजबूती दुनिया ने देखी जो कि चीन को आने वाले समय में काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ी कर देगी।

चीन और जापान ने दोबारा प्रयोग में लाने वाले राकेट का सफल प्रक्षेपण करके स्वयं को अमेरिका और चीन के बाद दूसरे और तीसरे नंबर का देश बना लिया है। इसके अतिरिक्त, जुलाई 18 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने विक्रम-1 राकेट का पदार्पण 'मिशन आगमन' के तहत सफलतापूर्वक किया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका और चीन के बाद निजी तौर पर कक्षा तक पहुंचने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अनुसार, 2025 के अंतिम सप्ताह में कई चीनी उपग्रह आपरेटरों ने दो लाख से अधिक सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के लिए आवेदन किए जो कि चीन 2035 तक अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। मस्क चाहते हैं कि स्पेसएक्स अंतरिक्ष में लगभग 10 लाख एआइ संबंधित सैटेलाइट्स भेजने की योजना बना रहे हैं।

शीत युद्ध के समय : शीत युद्ध के शुरुआती दौर में शुरू हुई यह प्रतिस्पर्धा अब अपने सबसे तीव्र रूप में सामने आ रही है और उसका कारण है कि चीन का प्रतिस्पर्धा में भाग लेना। शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष की होड़ में केवल अमेरिका और सोवियत संघ ही शामिल थे और उस दौर में स्पेस रेस जैसे शब्दों का उदय हुआ। हालांकि अंतरिक्ष की होड़ में सबसे पहले सोवियत संघ ने अग्रणी भूमिका निभाई जब उसने अक्टूबर 1957 में पहली बार पृथ्वी के बाहर कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक-1 अंतरिक्ष में भेजा। इसके चार साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर मानव को कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना और पहली महिला (वैलेंटीना तेरेशकोवा) को भी अंतरिक्ष में भेजा।

सोवियत संघ की इन शुरुआती सफलता ने अमेरिका को चौंका दिया। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जान एफ. कैनेडी ने 1961 में घोषणा की कि अमेरिका इस दशक के अंत से पहले मानव को चंद्रमा पर उतारेगा। अमेरिकी संस्था नासा जिसका जन्म ही स्पुतनिक के सफल प्रक्षेपण के बाद हुआ था, उसने अपनी ताकत अपने महत्वाकांक्षी अपोलो कार्यक्रम में लगा दिया।

लेकिन इसी बीच, यूरोप और चीन ने भी अपने कदम को इस क्षेत्र में रख दिया। हालांकि यूरोप अभी भी स्वयं को चीन, रूस और अमेरिका के मुकाबले मजबूत नहीं कर पाया है, लेकिन चीन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ स्वयं को अमेरिका के निकट ला कर खड़ा कर दिया। हालांकि भारत ने भी बड़े बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, लेकिन चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत की स्थिति काफी दयनीय है और यह समय की भारत के नीति निर्माता इस बढ़ती समस्या को समझे और सह फैसले लिए जाए। आने वाले समय में अंतरिक्ष संबंधी अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत, शिक्षा, पर्यावरण और इसके अलावा लगभग हर क्षेत्र में अंतरिक्ष की सबसे अहम भूमिका होने वाली है और जो देश इस क्षेत्र को सही से विकसित करने में सफल होगा उसका वैश्विक शक्तियों के ढांचों पर काफी मजबूत पकड़ होगी।

किसकी कितनी शक्ति : अगर हम अभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप्टिकल इमेजिंग में अमेरिका के पास 454, चीन के पास 270 और रूस के पास 48 सैटेलाइट्स हैं जो सक्रिय हैं। नेविगेशन और पोजिशनिंग के मामले में चीन के पास 150, अमेरिका के पास 42 और रूस के पास 33 सैटेलाइट्स सक्रिय हैं। रडार इमेजिंग में अमेरिका के पास 31, चीन के पास 66 और रूस के पास केवल छह सैटेलाइट्स हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस के मामले में अमेरिका के पास 81, चीन के पास 109 और रूस के पास 10 सैटेलाइट्स सक्रिय हैं। टेक्नोलाजी और ट्रेनिंग के मामले में अमेरिका के पास 169, चीन के पास 89 और रूस के पास 59 सैटेलाइट्स हैं। मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम में अमेरिका के पास लगभग 44 सैटेलाइट्स हैं, जबकि रूस के पास केवल तीन और चीन के पास नौ सैटेलाइट्स हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि यह होड़ चीन और अमेरिका के बीच में बहुत अधिक गहरी हैं और कोई तीसरी वैश्विक शक्ति आसपास भी नहीं हैं।

चीन की बढ़ती ताकत : पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अंतरिक्ष मामलों में काफी प्रगति की है। उदाहरण के लिए उसने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग जो 2021 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और अभी हाल ही में मई में चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर लाए गए बीजों से उगे चावल के नमूनों की पहली खेप सफलतापूर्वक काट ली है। यह विकास के चरण में एक अलग विकसित होती होड़ है जो चीन स्वयं को अमेरिका के समकक्ष देखना चाहता है। हालांकि चीन के पास अभी भी अमेरिका के मुकाबले काफी कम सैटेलाइट हैं।

हाल के आंकड़ों पर ध्यान दें तो चीन के पास लगभग एक हजार सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में हैं जो कि अमेरिका के लगभग 10 हजार सैटेलाइट्स हैं, लेकिन यदि एलन मस्क के स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को हटा दें, तो चीन और अमेरिका के बीच यह अंतर काफी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर हम नेविगेशन से जुड़ी सैटेलाइट्स की बातें करते हैं तो चीन इसमें काफी आगे है। चीन के 'बैदाऊ' के पास कुल मिलाकर 56 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन अमेरिका के सबसे जानी मानी जीपीएस के पास केवल 33 सैटेलाइट्स हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के अपने 'नाविक' के पास कुल 11 सैटेलाइट्स हैं जिनमें से आठ ही सक्रिय हैं। रूस की ग्लासनास सिस्टम और यूरोप की गैलीलियो के पास भी कम सैटेलाइट्स हैं। और यही कारण है कि चीन की नेविगेशन की परिशुद्धता काफी अधिक है जो कि लगभग कुछ सेंटीमीटर्स हैं, जबकि जीपीएस की परिशुद्धता लगभग 10-15 मीटर की है।

चीन से पाकिस्तान को मदद : ऐसा माना जाता है कि आपरेशन सिंदूर के समय चीन ने पाकिस्तान को अपने नेविगेशन सैटेलाइट्स का प्रयोग करके उसकी सेना को मदद दी थी। चीन ने अभी पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में भी ईरान को मदद दी है और यह इस बात से भी साफ होता है कि ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों में जून 2025 के मुकाबले अभी के मामले में अधिक सफलता मिली है। इसका कारण चीन की नेविगेशन शक्ति के प्रयोग से ही यह संभव हो पाया है। चूंकि, अंतरिक्ष एक बहुआयामी क्षेत्र है और आज की आधुनिक दुनिया का लगभग हर हिस्सा उससे जुड़ा हुआ है तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर काफी निवेश किया जाए जिससे आने वाले संकट को टाला जा सके। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अनुसार, 2025 के आखिरी हफ्ते में कई चीनी उपग्रह आपरेटरों ने दो लाख से अधिक सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के लिए आवेदन किए जो कि चीन 2035 तक अंतरिक्ष में भेजना चाहता है।

भारत के लिए निरंतर बढ़ती संभावनाएं

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसकी बढ़ती ताकत को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि भारत जैसा विशालकाय देश स्वयं को कैसे मजबूत रखता है और अपने हितों की पूर्ति किस ढंग से करता है। भारत के पास अभी केवल 53 सक्रिय सैटेलाइट्स ही हैं। इसमें से नाविक के अभी 11 सैटेलाइट्स हैं जो चीन और अमेरिका के मुकाबले कहीं अधिक कम हैं। वस्तुतः भारत अपने 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए स्वयं मजबूत करने में लगा है, उसके लिए अंतरिक्ष सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें निवेश की जरूरत है। दुनिया में युद्ध अपने चरम पर है जिसमें रूस और यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में लगभग सारी बड़ी वैश्विक शक्तियां शामिल हैं, लेकिन इन युद्धों में सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वह है कि युद्ध करने के तरीकों में बदलाव आया है।

आज के युद्ध ड्रोन, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरनेट मीडिया से लड़े जा रहे हैं और इन सबकी कुंजी अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट्स से जुड़ते हैं। ड्रोन और मिसाइल्स एक नेविगेशन प्लेटफार्म का प्रयोग करते हैं और अगर कोई देश उस क्षेत्र में विकसित नहीं है तो वह देश अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा है। भारत जिस जीपीएस का प्रयोग अपने हर तरह के प्रयोग के लिए करता है वह सीधे अमेरिका की सेना के हाथों से चलते हैं और कठिन परिस्थितियों में अमेरिका उसका प्रयोग भारत के खिलाफ भी कर सकता है। ऐसे में भारत के 'नाविक' की शुरुआत इस पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है और ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें निवेश की जरूरत अभी भारत को है।

भारत को अपने नेविगेशन सिस्टम के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जिसमें अंतरिक्ष में सैन्य हथियारों को रखने, मिसाइल वार्निंग सिस्टम को लगाने जैसे सुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में ध्यान देना होगा। भारत को अपनी तकनीकी और सैन्य स्वायत्तता पर भी ध्यान देना होगा और मजबूती हासिल करनी होगी। यदि भारत लागत-प्रभावी प्रक्षेपण तकनीकों और वैश्विक सहयोग में अपनी बढ़त बनाए रखता है, तो वह न केवल चीन-अमेरिका की इस होड़ में संतुलन बनाए रख पाएगा, वैश्विक अंतरिक्ष की इस प्रतिस्पर्धा के युग में एक अग्रणी महाशक्ति के रूप में उभर सकेगा।

(राहुल पाण्डेय)

खरी-खरी

मार्निंग वाक की महिमा

राजेंद्र कुमार सिंह

वैसे मार्निंग वाक करना मेरा एक तरह का शगल है। यदि मैं न जाऊं तो लगता है जैसे आज की दिनचर्या में कुछ छूट गया। इसलिए मैं बहुत लंबे समय से इसे नियमित रूप से करता आ रहा हूं। मैं जिस रास्ते से रोज जाता हूं, उसी रास्ते के मुख्य मोड़ पर राम उद्गार जी मिल जाते हैं। उनका तांबे का कारोबार है। मिलते ही वे अपना रोज वाला संवाद दोहराते हैं- "यार, तुम्हें सुबह-शाम हमेशा वाक करते देखता हूं। तुम रोज एक ही काम करते हो। क्या उकताते नहीं? एक ही जगह, एक ही रास्ते को रोज मापते रहते हो। कौन-सी नीति अपनाते हो?"

उनका वक्तव्य पूरा होते ही मैं जवाब देता- "भाई, नया रास्ता कहां से लाऊं? दो-तीन रास्ते हैं, कभी इस पर, कभी उस पर चल लेता हूं।"

इतना कहकर मैं आगे निकल जाता। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुड़कर देखता तो वे उसी तरह मुझे घूर रहे होते। मुझे देखकर कुछ कहना उनकी आदत बन गई थी। इधर राम उद्गार जी एक सप्ताह से नहीं दिखे तो मेरा माथा ठनका। पता किया तो खबर मिली- "बेचारे डायबिटीज और फैटी लिवर के शिकार हो गए हैं। डाक्टर ने कहा है कि वे बार्डर लाइन पर हैं। यदि नियमित रूप से घूमना-फिरना शुरू नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।"

फिर एक दिन जिस मैदान में मैं टहलने जाता हूं, वहीं मैंने दूर से राम उद्गार जी को चलते देखा। उन्होंने पूछा- "कैसे हो, सिंह साहब?"

"मैं तो ठीक हूं।" मैंने तुरंत एक तीखा सवाल उछाल दिया- "राम उद्गार जी, ये उल्टी बयार कब से बहने लगी?" इतना सुनते ही वे बोले- "बीमारी की चपेट में आ गया, सिंह साहब।" मैं उसी लहजे में बोला- "जब तीन-चौथाई फसल सूखने के कगार पर आ गई, तब खाद-पानी डालना शुरू किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। मैं टंच हूं।"

मैंने चुटकी ली, "ठीक होने में समय लगेगा, पर यह ऐसी बीमारी है कि एक बार चपेट में आ जाए और ध्यान न दिया जाए तो वह समेट भी लेती है। इसलिए अपना ध्यान रखिए।"

पोस्ट

एअर इंडिया टर्बुलेंस प्रकरण सीट बेल्ट की महत्ता को ही नए सिरे से रेखांकित करने वाला है। हवाई यात्रा के दौरान यात्री सीट बेल्ट लगाने को लेकर लापरवाही न करें।
अमन शर्मा@AmanKayamHai_

सात साल पहले अनुच्छेद 370 की समाप्ति का निर्णय सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक रहा। जम्मू-कश्मीर और समूचे राष्ट्र के लिए तो यह उत्तम ही रहा, इससे दुनिया को एक सही संदेश भी गया।
वेद प्रकाश मलिक@Vedmalik1

अनुच्छेद 370 की समाप्ति और माओवाद को पूरी तरह मात देना गृह मंत्रालय की बड़ी सफलताएं हैं, लेकिन मणिपुर और लद्दाख के मामले को सही तरीके से नहीं संभाला गया।
प्रकाश सिंह@singh_prakash

एफसीआरए संशोधन विधेयक ने मतांतरण कराने वाले माफिया और उनके पश्चिमी आकाओं की नींद उड़ा दी है। मोदी सरकार ने उन्हें ठीक उसी जगह चोट पहुंचाई है, जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर भारत को डेमोग्राफिक आपदा और इस देश से नफरत करने वालों की साजिशों से बचाना है, तो प्रधानमंत्री को पीछे नहीं हटना चाहिए।
आनंद रंगनाथन@ARanganathan72

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने के मामले में मेटा संस्थापक की माफी पर्याप्त है?

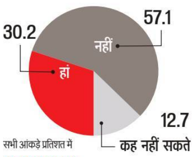

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या एक निश्चित राशि के यूपीआइ लेनदेन पर शुल्क लगने से नकदी पर निर्भरता बढ़ेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

कट्टरपंथी देख लें निज कुकृत्य का हाल,
उबल रहा उनपर अभी 'हिंदु राष्ट्र' नेपाल।
'हिंदु राष्ट्र' नेपाल भग रहे हैं घुसपैठी,
भारत में ही सिर्फ आपकी दुम है ऐंठी!
यहां इन्हें बीमार कर रही सेक्युलर ग्रंथी,
चढ़े शीश पर नाच रहे हैं कट्टरपंथी!!
-ओम प्रकाश तिवारी

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

समस्याओं के समाधान की निकले राह

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में चल रहा छात्रों के धरना-प्रदर्शन और आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जंतर मंतर की ही तरह यहां भी छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब तक यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कहीं भी सरकार या सत्ता पक्ष के नेता के खिलाफ किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं की गई है। बीते माह दिल्ली में हुए आंदोलन को सबने देखा कि किस तरह देश विरोधी नारे से लेकर कई नेताओं द्वारा शरजील इमाम की रिहाई की बात मंच से होने लगी। इस बीच, झारखंड के छात्रों ने राजनीति और नेताओं से अपनी दूरी बनाए रखी और अपनी मांगों पर लगातार धरना-अनशन कर रहे हैं।

छात्रों के आंदोलन का असर भी दिख रहा है और झारखंड सरकार ने भी अपनी ओर से छात्रों से वार्ता की पहल शुरू कर दी है। बातचीत के लिए चार मंत्रियों की टीम बना दी गई है, उधर छात्रों ने भी वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों की घोषणा कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेपीएससी दो दशकों में अपनी दागदार छवि से बाहर क्यों नहीं आ सका? सरकार के सामने असल चुनौती यह है कि वह इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाए। अभी आंदोलनरत कुछ छात्र सीबीआइ जांच की मांग कर रहे हैं। सीआइडी पहले से ही जांच कर रही है और अब तक 19 गिरफ्तार हो चुके हैं। इस्तीफा दे चुके जेपीएससी चेयरमैन से घंटों-घंटों पूछताछ कर रही है। आंदोलनरत छात्रों ने राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखी है। यह अच्छी बात है। इधर, सत्ता गठबंधन दल में शामिल कांग्रेस ने सरकार को सात सुझाव दिए हैं। कांग्रेस भी समयबद्ध व निष्पक्ष जांच की मांग के साथ विवादित एजेंसियों की जांच, भर्ती परीक्षा कानून 2023 का सख्ती से पालन की मांग कर रही है।

परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पिछले लगभग दो सप्ताह से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र। फाइल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का दल छात्रों से मिला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों की मांग जायज है। नियुक्ति परीक्षा में वे भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच का समर्थन करते हैं। छात्रों का भविष्य संवारने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी छात्रों की मांगों को जायज बताते हैं और छात्र हित में आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं।

इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं, छात्र आंदोलन जल्द समाप्त हो। विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। छात्र विधानसभा मार्च की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इससे स्थिति और तनावपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं राज्यपाल से मिलकर स्थिति से अवगत करा चुके हैं।

पिछले 23 वर्षों से झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हमेशा विवादों में रही हैं। वर्ष 2002 में इसका गठन हुआ और वर्ष 2003 की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा। दूसरी से चौथी जेपीएससी परीक्षा में कापी जांच, उम्र की अनदेखी, आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा। छठी में पासिंग मार्क्स और रिजल्ट प्रकाशन में भारी अनियमितता बरती गई। 11वीं से 14वीं तक उत्तर कुंजी में विसंगति से लेकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पेपर लीक के आरोप लगे हैं। बीते 26 वर्षों में 14 परीक्षाएं भी ठीक से नहीं हो सकी हैं। इसमें केवल वर्तमान सत्तापक्ष का दोष नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में भी यही आरोप लगा।

वैसे देखा जाए तो यहां मामला सिर्फ छात्रों का ही नहीं है। विश्वविद्यालयों में लंबे समय से प्रोन्नति रुकी हुई है। इसका परिणाम यह है कि रांची विश्वविद्यालय में गिनती के प्रोफेसर बचे हुए हैं। इसलिए, प्रशासनिक पद या तो प्रभार में चल रहे हैं या बाहर से लोग मंगाए जा रहे हैं। इस संस्थान का हाल यह है कि यहां का क्लर्क भी सबसे बड़ा अधिकारी समझता है। कई नेताओं के भाई, बच्चे, रिश्तेदार पास हो गए और होनहार सड़क पर ही रह गए। ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने इस संस्थान की पवित्रता की रक्षा करना भी बड़ी चुनौती है। सरकार को ऊपर से नीचे तक अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। सदस्यों की नियुक्ति भी ईमानदार लोगों की हो। इसमें किसी प्रकार के अपने चहेतों को न रखा जाए। यह युवाओं के भविष्य ही नहीं, राज्य के भविष्य का सवाल है।

मंथन

शास्त्री कोसलेंद्रदास
अध्यक्ष, दर्शन संकाय, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मनुस्मृति से जुड़े मिथक

भारतीय सामाजिक एवं विधिक परंपरा में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे राजनीति में घसीटने से बचना चाहिए। मनुस्मृति के मर्म को समझे बिना उसका अंधविरोध उचित नहीं

भारतीय बौद्धिक परंपरा में यदि किसी ग्रंथ पर सबसे अधिक विवाद बना हुआ है, तो वह मनुस्मृति है। एक पक्ष इसे विश्व का प्राचीनतम विधि-ग्रंथ और सामाजिक व्यवस्था का आधार मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे जाति, वर्ण और स्त्री-विषयक असमानताओं का स्रोत बताकर अस्वीकार करता है। प्रश्न है कि मनुस्मृति को बार-बार ललकारा क्यों जाता है? उसके पक्ष और विपक्ष में आवाज उठाने के निहितार्थ क्या हैं?

धर्मशास्त्र के अनुसार स्मृतियों का मूल उद्देश्य समाज को नियमबद्ध करना था। चौथी शताब्दी के बौद्ध संन्यासी अमर सिंह ने 'अमरकोष' में स्मृति ग्रंथ का अर्थ धर्म संहिता बताया है। वैदिक सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में लागू करने के लिए राजा मनु ने धर्म, कर्तव्य, शासन, न्याय, परिवार, उत्तराधिकार और सामाजिक अनुशासन से संबंधित अनेक नियम निर्धारित किए। इसी कारण अनेक भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसे प्राचीन विधिशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इसमें सामाजिक न्यायों का विस्तृत प्रतिपादन है।

मनुस्मृति भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें वेदों के सिद्धांतों को सामाजिक और व्यावहारिक जीवन के अनुरूप व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय परंपरा में वेदों के बाद स्मृतियों का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और मनुस्मृति उनमें सर्वाधिक प्रभावशाली एवं प्राचीन ग्रंथों में परिगणित है। मनुस्मृति पर उपलब्ध सबसे प्राचीन और विद्वत्तापूर्ण व्याख्या कश्मीर के मेधातिथि की है, जिनका काल डा. गंगानाथ झा के अनुसार नौवीं शताब्दी ठहरता है। उनकी टीका से स्पष्ट है कि मनुस्मृति तत्कालीन समाज, परंपराओं और विधि-व्यवस्था की सबसे उपयोगी पुस्तक थी।

मेधातिथि के बाद बंगाल के कुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति पर विस्तृत व्याख्या की, जिसे आज भी सर्वाधिक प्रामाणिक टीका माना जाता है। वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति के अधिकांश संस्करण इसी व्याख्या पर आधारित हैं और आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी इसे विशेष महत्व दिया है। मनुस्मृति का पहला मुद्रित संस्करण वर्ष 1813 में कलकत्ता (अब कोलकाता) से प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। जर्मन विद्वान डा. जार्ज बुलर द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद मनुस्मृति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उन्होंने अपनी भूमिका में इस ग्रंथ के इतिहास, पाठ भेदों और विभिन्न मतों का विस्तार से विवेचन किया है। वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति में 12 अध्याय और कुल 2694 श्लोक हैं।

विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुस्मृति में अधिकारों और सामाजिक दायित्वों का निर्धारण अनेक स्थानों पर जन्माधारित वर्ण-व्यवस्था के आधार पर दिखाई देता है। आधुनिक भारत का संवैधानिक दर्शन समानता, स्वतंत्रता और अवसर की समान उपलब्धता पर आधारित है। इसलिए जब मनुस्मृति के कुछ श्लोक आधुनिक संवैधानिक मूल्यों से टकराते प्रतीत होते हैं, तब उसकी आलोचना स्वाभाविक हो जाती है। डा. भीमराव आंबेडकर द्वारा मनुस्मृति-दहन इसी वैचारिक असहमति का प्रतीक था। उनका विरोध संपूर्ण भारतीय ज्ञान-परंपरा या संस्कृत भाषा से नहीं, बल्कि उन सामाजिक व्यवस्थाओं से था, जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते थे।

मनुस्मृति में ऐसे अनेक सिद्धांत हैं, जिन्हें भारतीय समाज ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः' जैसा प्रसिद्ध वचन स्त्री-सम्मान का उद्घोष करता है। माता-पिता की सेवा, सत्य, संयम, शुचिता, आत्मनियंत्रण, शिक्षा और सदाचार को मनु ने धर्म का आधार माना है। अतः मनुस्मृति केवल विवादास्पद कथनों का संग्रह नहीं, बल्कि अनेक नैतिक और सामाजिक आदर्शों का ग्रंथ भी है।

समकालीन राजनीति में मनुस्मृति का उल्लेख प्रायः प्रतीक के रूप में होता है। सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक असमानताओं की चर्चा में इसे बार-बार उद्धृत किया जाता है, किंतु गंभीर शास्त्रीय विमर्श का आग्रह है कि किसी भी ग्रंथ का मूल्यांकन उसके समग्र स्वरूप, ऐतिहासिक संदर्भ और प्रामाणिक पाठ के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल कुछ चुनिंदा उद्धरणों के आधार पर।

प्रश्न यह नहीं है कि मनुस्मृति का अंध-समर्थन किया जाए या उसका पूर्ण निषेध, बल्कि यह है कि उसके कौन-से सिद्धांत कालजयी हैं और कौन-से समय की कसौटी पर अप्रासंगिक हो चुके हैं। भारतीय परंपरा का स्वभाव परिष्कार और पुनर्व्याख्या का है। इसलिए मनुस्मृति को पूर्वाग्रह के स्थान पर तर्क, इतिहास और शास्त्रीय विवेक के आधार पर पढ़ना और परखना ही उचित होगा। यही दृष्टि स्वस्थ बौद्धिक संवाद और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

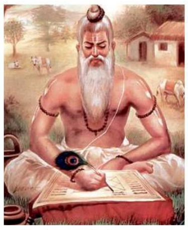

भारतीय परंपरा का प्राचीन ग्रंथ। प्रतीकात्मक

मनुस्मृति पर अस्पृश्यता का आरोप लगाने वाले प्रायः उसके मूल स्वरूप की उपेक्षा करते हैं। मनु के अनुसार केवल श्मशान में रहने वाला शवदाहक चांडाल ही विशेष परिस्थितियों में अस्पृश्य है, शेष समाज का कोई वर्ग नहीं। मनुस्मृति का मूल उद्देश्य सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक स्थिरता, नैतिक आचरण और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करना है। इसे केवल विवादों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके विधिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए।

अप्रैल-जुलाई में स्टील उत्पादन चार प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली : स्टील मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई 2026) के दौरान देश में तैयार स्टील का उत्पादन चार प्रतिशत बढ़कर 5.43 करोड़ टन रहा है। अप्रैल-जून 2025 के दौरान देश में 5.22 करोड़ टन रहा था। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में तैयार स्टील की खपत 7.8 प्रतिशत बढ़कर 5.59 करोड़ टन रही है। (आइएएनएस)

बैंक की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली के स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं है जो नैतिक मूल्यों पर चुनौती पेश करती हो। सबकुछ ठीक है, बैलेंस शीट एकदम साफ-सुथरी है।
– राजीव कुमार, गैर कार्यकारी चेयरमैन, एचडीएफसी बैंक

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलो ग्राम	डालर	क्रूड प्रति बैरल
78,954.76	24,636	₹ 1,53,800	₹ 2,34,800	₹ 95.22	$ 79.52
▲ 373.76	▲ 11.35	▲ ₹ 3,800	▲ ₹ 2,100	▲ ₹ 0.14	

एक नजर में

दो वर्ष तक नहीं बेची जाएगी एलआइसी की हिस्सेदारी

नई दिल्ली : सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआइसी के सीईओ और एमडी आर दोराईस्वामी ने गुरुवार को कहा कि सरकार की ओर से अगले 18-24 महीनों में कंपनी का शेयर बिक्री आफर लाने की संभावना कम है। इसका कारण यह है कि एलआइसी के पास सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम पूरा करने के लिए 2032 तक का समय है। सरकार ने हाल ही में एलआइसी की 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। अप्रैल-जून 2026 तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 23 प्रतिशत बढ़कर 13,492 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 10,987 करोड़ रुपये था। (प्रेट्र)

सात सप्ताह के उच्च स्तर पर सोना, चांदी भी बढ़ी

नई दिल्ली : मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते गुरुवार को दिल्ली में सोना 3,800 रुपये बढ़कर 1,53,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह सोने का सात सप्ताह का उच्च स्तर है। इससे पहले 18 जून को सोना 1,53,440 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह, चांदी की कीमत भी 2,100 रुपये बढ़ी है और अब दिल्ली में इसका मूल्य 2,34,800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। (प्रेट्र)

केकेआर खरीदेगी मेडिकवर एबी का भारतीय कारोबार

नई दिल्ली : वैश्विक निवेश फर्म केकेआर ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्यकेयर और डायग्नोस्टिक सेवा प्रदाता मेडिकवर एबी के भारतीय अस्पताल कारोबार को खरीदेगी। यह सौदा कंपनी के 1.2 अरब यूरो के मूल्यांकन पर होगा। मेडिकवर ने एक बयान में कहा कि उसने और आंशिक शेयरधारकों ने मेडिकवर हास्पिटल्स इंडिया (एमएचआइ) में अपनी 100 प्रतिशत इक्विटी केकेआर को बेचने के लिए समझौता किया है। इस सौदे से मेडिकवर को 74 करोड़ यूरो नकद मिलेंगे और इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी। (प्रेट्र)

अमेरिकी दबाव में न लगे यूपीआइ पर शुल्क

जीटीआरआइ ने कहा- वीजा और मास्टरकार्ड के मुनाफे की रक्षा करने की भारत को जरूरत नहीं

- यूपीआइ और रुपे की मुफ्त सेवा पर आपत्ति जताता रहा है अमेरिकी प्रशासन
- ब्राजील की डिजिटल भुगतान सेवा पिक्स पर भी एतराज जता चुका है अमेरिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह अमेरिकी दबाव में यूपीआइ पर किसी तरह का शुल्क लगाने का फैसला नहीं करे। गुरुवार को जीटीआरआइ की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूपीआइ पर किसी तरह का शुल्क लगता है तो इसे सीधे तौर पर अमेरिका की वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों के वित्तीय हितों की रक्षा करना माना जाएगा। जीटीआरआइ की यह रिपोर्ट जिस दिन आई है, उसके कुछ घंटे बाद ही गुरुवार को लोकसभा ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 को मंजूरी प्रदान कर दी। यह विधेयक सरकार को डिजिटल लेनदेन की कीमत निर्धारण के तरीके को बदलने की शक्ति देता है।

अभी बैंक और भुगतान-प्रणाली प्रदाता कंपनी यूपीआइ और रुपे डेबिट कार्ड जैसे माध्यमों के लिए उपयोगकर्ताओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। विधेयक केंद्र सरकार को अधिसूचना के जरिये यह तय करने का अधिकार देता है कि कौन-कौन से इलेक्ट्रानिक भुगतान मोड या लेनदेन मुफ्त रहेंगे। यह सरकार को बाद में जीरो-एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) ढांचे में बदलाव करने के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान करता है। रिपोर्ट में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की तरफ से भारत के यूपीआइ और रुपे फ्रेमवर्क व ब्राजील की डिजिटल भुगतान ढांचे 'पिक्स' की आलोचना का जिक्र है। यूएसटीआर ने आरोप लगाया था कि भारत व ब्राजील की घरेलू डिजिटल भुगतान प्रणालियां अमेरिकी भुगतान प्रदाताओं को तरजीह नहीं देतीं। इस मामले में ब्राजील ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया, जिसके बाद ज्यादातर ब्राजीलियाई सामानों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया गया है। इलेक्ट्रानिक भुगतान को भी इसमें शामिल किया गया। ब्राजील ने पिक्स में कोई बदलाव नहीं किया और इसकी सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं। भारत के मामले में यूएसटीआर का कहना है कि यहां रुपे को तरजीह दी जा रही है। यूपीआइ लांच के बाद इसके जरिये भुगतान लगातार बढ़ रहा है जिससे वीजा और मास्टरकार्ड का संभावित कारोबार प्रभावित हो रहा है। असलियत में भारत ने जब वर्ष 2012 में रुपे को लांच किया था तब इसकी वजह यहीं बताई गई थी कि यहां के बैंक वीजा और मास्टरकार्ड को काफी ज्यादा राशि का भुगतान कर रहे हैं। असलियत में वीजा और मास्टरकार्ड का माडल बैंकों, प्रोसेसर्स और नेटवर्क को मर्चेंट लेनदेन से फीस कमाने पर आधारित है।

यूपीआइ प्लेटफार्म के इस्तेमाल में भी अमेरिकी कंपनियां हावी

जीटीआरआइ ने यह भी कहा है कि अमेरिकी कंपनियों का राजस्व प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी भी यूपीआइ प्लेटफार्म का इस्तेमाल में अमेरिकी कंपनियां ही हावी हैं। गूगल पे और वालमार्ट की स्वामित्व वाली फोनपे संयुक्त तौर पर 80 प्रतिशत से ज्यादा यूपीआइ लेनदेन प्रोसेस कर रही हैं। यही नहीं अमेरिका डेटा लोकलाइजेशन नियमों (यानी ग्राहकों से जुड़े हर तरह के आंकड़ों को भारत में ही स्टोर करने की व्यवस्था) का भी विरोध करता है। ऐसे में जीटीआरआइ ने कहा है कि विदेशी कंपनियों को खुश करने के लिए यूपीआइ को बदलने की जरूरत नहीं है। शुल्क संबंधी फैसला यूपीआइ चलाने की लागत और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। रुपे को सरकारी समर्थन जारी रहना चाहिए।

टाटा संस 'बड़ी एनबीएफसी' में बरकरार

- आरबीआइ ने 17 'ऊपरी स्तर' की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ताजा सूची जारी की
- केंद्रीय बैंक ने कहा-इससे कंपनी के रजिस्ट्रेशन सरेंडर के लंबित आवेदन पर असर नहीं

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने टाटा संस को अपनी 'ऊपरी स्तर' या बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' की सूची में बनाए रखा है। बैंक ने कहा कि इस होल्डिंग कंपनी को सूची में शामिल करने से एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के उसके लंबित आवेदन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने अपने 'स्केल-बेस्ड रेगुलेशन' फ्रेमवर्क के तहत 17 'ऊपरी स्तर' की एनबीएफसी की ताजा सूची जारी की है। इस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआइ एनबीएफसी और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों पर ज्यादा नियामकीय निगरानी रखता है।

400 अरब डालर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को पहली बार 2022 में 'ऊपरी स्तर' के एनबीएफसी के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण का मतलब यह था कि टाटा संस को सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसमें स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के साथ गवर्नेंस, पूंजी और डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों को पूरा करना शामिल था। इसके जवाब में टाटा संस ने वित्तीय कारोबार में अपनी पहुंच को कम करने और समूह के कुछ हिस्सों को पुनर्गठित करने के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही आरबीआइ के वर्गीकरण से छूट भी मांगी। पारंपरिक एनबीएफसी के उलट टाटा संस एक निवेश कंपनी के तौर पर काम करती है। इसका मुख्य काम लोन देना नहीं, बल्कि टाटा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करना है। इसकी सूचीबद्ध कंपनियों जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी और इंडियन होटल्स कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है और इसे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से मिलता है। अभी तक टाटा संस एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है, लेकिन कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारक शापूरजीपलोनजी की तरफ से सूचीबद्ध होने का दबाव है। आरबीआइ ने टाटा संस की एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के आवेदन पर फैसला लेने के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है।

सूची में सरकारी एनबीएफसी आरईसी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन भी शामिल हैं। आरबीआइ एनबीएफसी को आकार, कामकाज और वित्तीय प्रणाली के लिए संभावित जोखिम के आधार पर चार श्रेणियों में बांटता है।

जुलाई में वाहनों की खुदरा बिक्री 26 प्रतिशत बढ़ी

- उद्योग संगठन फाडा के अनुसार-पिछले महीने देश में कुल 25.91 लाख वाहन बिके
- पिछले साल जुलाई में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 20,58,325 इकाई रही थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने गुरुवार को कहा कि जुलाई में सभी तरह के वाहनों की कुल घरेलू खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 25.89 प्रतिशत बढ़कर 25,91,138 इकाई हो गई। यह मांग में उस तेजी को बनाए हुए है जो पिछले साल के आखिर में जीएसटी में बदलाव के बाद शुरू हुई थी। जुलाई 2025 में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 20,58,325 इकाई थी।

पिछले महीने यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 4,16,555 इकाई रही, जबकि जुलाई, 2025 में यह 3,49,674 इकाई थी। वहीं दोपहिया वाहनों की बिक्री 28.25 प्रतिशत बढ़कर 18,18,289 इकाई हो गई। जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 14,17,767 इकाई थी। इसी तरह, तिपहिया की बिक्री 16.16 प्रतिशत बढ़कर 1,33,778 इकाई रही, जो जुलाई, 2025 में 1,15,166 इकाई थी। वाणिज्यिक गाड़ियों की खुदरा में बिक्री भी 24.04 प्रतिशत बढ़कर पिछले महीने 99,666 इकाई रही। उद्योग संगठन के प्रेसिडेंट साई गिरधर ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन (सीएनजी-24.67%, हाइब्रिड 8.02%, ईवी 7.9%) की हिस्सेदारी 40.59% तक पहुंच गई है, जो पेट्रोल की 41.68% हिस्सेदारी से सिर्फ 1.09 प्रतिशत अंक पीछे है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

सक्रिय डाटा सेंटर क्षमता में दुनिया में 15वें स्थान पर मुंबई

भारत समेत दुनियाभर में डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर डाटा संरक्षित करने की नीति के चलते भी भारत में तेजी से डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, परिचालन डाटा सेंटर क्षमता में मुंबई दुनियाभर में 15वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद 27वें स्थान पर है। रिपोर्ट में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया-प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के 36 प्रमुख वैश्विक डाटा सेंटर बाजारों की तुलना की गई है।

मुंबई में 774 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर संचालित

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई परिचालन डाटा सेंटर क्षमता श्रेणी में 15वें और पाइपलाइन यानी भविष्य में बनाए जाने वाले बनाए जाने वाले डाटा सेंटर श्रेणी में 11वें स्थान पर है। अभी मुंबई में 774 मेगावाट की सक्रिय आइटी क्षमता है और करीब पांच गीगावाट क्षमता वाले डाटा सेंटर पाइपलाइन में हैं। इससे यह भारत के गेटवे डाटा सेंटर बाजार और एशिया-प्रशांत के प्रमुख डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। 151 मेगावाट के साथ सक्रिय परिचालन क्षमता में हैदराबाद दुनियाभर में 27वें स्थान पर रहा है। वहीं, 2.2 गीगावाट क्षमता की पाइलाइन के साथ यह इस श्रेणी में 19वें स्थान पर रहा है।

शीर्ष पांच में उत्तरी अमेरिका के शहर

परिचालन आइटी क्षमता श्रेणी में शीर्ष पांच स्थान पर उत्तरी अमेरिका के शहर हैं। इसमें पहले स्थान पर ऐशबर्न, उसके बाद कोलंबस, डलास, फीनिक्स और अटलांटा हैं।

दो संकेतों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट

- **सक्रिय क्षमता** : यह सक्रिय डाटा सेंटरों में वर्तमान में स्थापित परिचालन क्षमता को दर्शाती है।
- **पाइपलाइन क्षमता** : यह निर्माणाधीन, प्रतिबद्ध और विकास के प्रारंभिक चरणों में मौजूद क्षमता को दर्शाती है।

ऐसे तय होती है डाटा सेंटर की क्षमता

किसी भी डाटा सेंटर की क्षमता उसमें इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली के आधार पर तय होती है। इसकी गणना मेगावाट या एमडब्ल्यू में की जाती है। उदाहरण के लिए : यदि किसी डाटा सेंटर में एक समय में एक मेगावाट बिजली का इस्तेमाल हो सकता है तो उसकी कुल क्षमता एक मेगावाट होगी। इसमें सर्वर, कूलिंग उपकरण और बैकअप में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली क्षमता शामिल है।

वैश्विक रैंकिंग में भारत की उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश कितनी तेजी से एक रणनीतिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है। मुंबई का विश्व के प्रमुख परिचालन बाजारों में स्थान पाना कनेक्टिविटी, उद्यम मांग और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में वर्षों के निवेश को दर्शाता है। हालांकि, यदि भारत को विश्व के शीर्ष दस डाटा सेंटर बाजारों में शामिल होना है तो अब मांग निर्माण से इन्फ्रास्ट्रक्चर सक्षम करने की ओर ध्यान देना होगा।
– **शिशिर बैजल**, सीएमडी, नाइट फ्रैंक इंडिया

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

राष्ट्रीय फलक

फुटवियर उद्योग पीएलआइ योजना का ले लाभ : गिरिराज सिंह

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

- भारत मंडपम में 10वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला शुरू
- हाल नंबर पांच (भूतल) और हाल नंबर छह में लगाए गए स्टाल

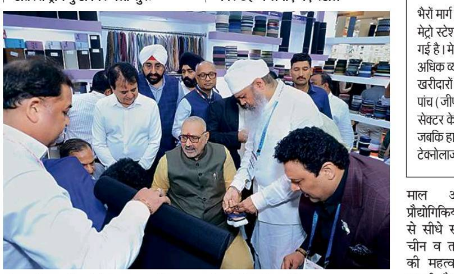

अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेले के उद्घाटन मौके पर स्टाल देखते मंत्री गिरिराज सिंह। जागरण

भारत मंडपम में गुरुवार को 10वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला 2026 शुरू हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) व कंफेडेरशन आफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री (सीआइएफआइ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय बी2बी मेले का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह ने फुटवियर उद्योग में 'टेक्निकल टेक्सटाइल्स' की तेजी से बढ़ती भूमिका पर विशेष बल देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक व नवाचार ही इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने देश के फुटवियर निर्माताओं से आह्वान किया कि वे विनिर्माण क्षमताओं, गुणवत्ता व वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने उद्योग में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाने, तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने तथा इस मेले को एक ऐसे वैश्विक मंच के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो दुनियाभर के खरीदारों, प्रदर्शकों और निवेशकों को आकर्षित कर सके। गिरिराज सिंह ने विशेष रूप से गैर-चमड़ा फुटवियर श्रेणी में अपार संभावनाओं का उल्लेख किया। मंत्री ने कुछ स्टालों का दौरा कर मशीनरी, कच्चा माल और आधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शकों से सीधे संवाद किया। इस वर्ष मेले में चीन व ताइवान समेत विदेशी कंपनियों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भी देखी जा सकती है। मेले में फुटवियर, मशीनरी, आधुनिक उपकरण, फुटवियर उत्पाद, सिंथेटिक मटीरियल (पीवीसी, पीयू, ईवीए), फैब्रिक्स, सोल्स, एडहेसिव्स और केमिकल्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख ब्रांड्स व निर्माता हिस्सा ले रहे हैं।

मेले में प्रवेश की व्यवस्था

भैरों मार्ग स्थित गेट नंबर तीन व चार और मेट्रो स्टेशन की ओर गेट नंबर 10 से की गई है। मेले में देश-विदेश से 15,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुकों और खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। हाल पांच (जीएफ) में फुटवियर और संबंधित सेक्टर के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि हाल छह में मशीनरी और टेक्नोलाजी का प्रदर्शन है।

सार्वजनिक की जाएगी टप्पेबाजों और शोहदों की पहचान : योगी

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- कहा, शिवभक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए उर्स आयोजन को सीमित रखना स्वागतयोग्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाह फैलाने वालों व उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा है कि कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पिछले दिनों घटित महिला अपराधों से जुड़ी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन शक्ति अभियान को और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तैनात 45 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित की जाए। शोहदों और टप्पेबाजों की पहचान सार्वजनिक की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए।

गुरुवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, महिला सुरक्षा, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का संदेश दे रही है। सरकार के साथ अनेक सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हैं, जो समाज की सकारात्मक सहभागिता को दर्शाता है। मेरठ के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीमावर्ती राज्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रवींद्र गौड़ ने बताया कि अब तक लगभग 70 हजार कांवड़ यात्री गाजियाबाद से गुजर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई उम्मीद, सहमति से सुलझ जाएगा रानी और प्रिया कपूर विवाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर चल रहा विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मध्यस्थ एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से दाखिल प्रारंभिक मध्यस्थता रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और कहा, 'अब तक मध्यस्थता की कार्यवाही छह सत्रों में हुई है। मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है। हमें खुशी है कि मध्यस्थता काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है और सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं।' शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि मध्यस्थ ने मध्यस्थता के लिए दो नवंबर तक का समय देने का अनुरोध किया है।

शुल्क से यूपीआइ ट्रांजेक्शन प्रणाली को सुरक्षित बनाने में मिलेगी मदद

प्रथम पृष्ठ से आगे

बिल के माध्यम से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत यूपीआइ ट्रांजेक्शन पर बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था अभी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बैंकों को यूपीआइ सेवा का संचालन करने में सालाना करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है।

अभी 700 से अधिक बैंक व वित्तीय संस्था यूपीआइ सेवा मुहैया कराते हैं। सूत्रों का कहना है कि शुल्क मिलने से बैंकों को यूपीआइ ट्रांजेक्शन प्रणाली को मजबूत और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआइ प्लेटफार्म से कुल 24,161.69 करोड़ ट्रांजेक्शन किए गए, जिनका मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए बताया गया। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इन 314 लाख करोड़ में से 71 प्रतिशत राशि पी-टू-पी यानी कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन की थी। ट्रांजेक्शन की 29 प्रतिशत राशि पर्सन टू मर्चेंट (पी-टू-एम) के बीच की थी। पिछले वित्त वर्ष में पर्सन टू मर्चेंट स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजेक्शन में सिर्फ चार प्रतिशत ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये से अधिक के रहे। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन में 59 प्रतिशत ट्रांजेक्शन 500 रुपये तक के थे।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में पी-टू-पी स्तर पर हुए कुल ट्रांजेक्शन में 59 प्रतिशत ट्रांजेक्शन 500 रुपये तक के थे।

पी-टू-पी स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजेक्शन में 20 प्रतिशत ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये से अधिक के थे। पी-टू-पी को शुल्क से मुक्त रखने की बात कही जा रही है, इसलिए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद नहीं कर सकते बैंक

- आरबीआइ ने कहा-बैंक उन डिवाइस को बंद करा सकते हैं, जिसका फाइनेंस उन्होंने किया हो

प्रतीकात्मक

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने गुरुवार को कहा कि बैंक पर्सनल, कार और होम लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि, बैंक उन डिवाइस को बंद करा सकते हैं, जिनका फाइनेंस उन्होंने किया हो।

आरबीआइ ने कहा कि जिन खास मामलों में लोन वसूली की प्रक्रिया के तहत डिवाइस को डिसेबल करने की इजाजत है, वहां बैंकों को सीधे ऐसा करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए। लोन की बकाया राशि की वसूली और रिकवरी एजेंसियों को काम पर रखने और उनसे जुड़े व्यवहार के मामलों पर केंद्रीय बैंक के नियम ग्राहकों की उन शिकायतों के बाद आए हैं, जिनमें उन्हें परेशान करने, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये और अभद्र भाषा के इस्तेमाल की बात कही गई थी। आरबीआइ के एक सर्कुलर के अनुसार, ये नियम एक जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

प्रस्तावित नियमों के तहत बैंक किसी भी ऐसी तकनीक आधारित तंत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा जो वसूली के लिए ग्राहक के मोबाइल (जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप) को डिसेबल करता हो। आरबीआइ ने आगे कहा है कि अगर संबंधित मोबाइल डिवाइस को बैंक ने लोन के जरिये फाइनेंस किया है तो वह मोबाइल डिवाइस को डिसेबल करने का तरीका अपना सकता है।

हालांकि, आरबीआइ ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों में बैंक को डिवाइस को सीधे डिसेबल करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए। हालांकि, बैंक उन फंक्शन को रोक या डिसेबल नहीं कर सकता है, जिन्हें जरूरी माना जाता है। जैसे इनकमिंग काल, एसएमएस और इमरजेंसी एसओएस फीचर का इस्तेमाल। इससे पहले मई में केंद्रीय बैंक ने लोन की वसूली और रिकवरी एजेंटों को काम पर रखने में नियामकीय संस्थाओं के व्यवहार से जुड़े नियमों पर एक मसौदा जारी किया था। आरबीआइ को इस मसौदे पर कई सुझाव मिले थे।

सिंगुर विवाद सुलझाने और नए निवेश पर टाटा समूह से बातचीत शुरू

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुंबई जाकर टाटा समूह के शीर्ष अधिकारियों से की मुलाकात

बंगाल सरकार ने सिंगुर भूमि विवाद का समाधान निकालने और राज्य में टाटा समूह के नए निवेश का रास्ता खोलने के लिए कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुंबई जाकर टाटा समूह के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तापस राय ने कहा कि सरकार टाटा समूह को बड़े स्तर पर फिर से बंगाल लाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में टाटा मोटर्स को मुआवजा देने के साथ समूह की अन्य कंपनियों के नए निवेश और परियोजनाओं पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।

वर्ष 2023 में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने टाटा मोटर्स के पक्ष में 765 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्ष 2008 में सिंगुर में नैनो कार संयंत्र लगभग 90 प्रतिशत तैयार हो चुका था, लेकिन तत्कालीन विपक्ष के आंदोलन के बाद टाटा मोटर्स ने परियोजना वापस ले ली थी। इसके बाद कंपनी ने हुए नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी।

वहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट में बुधवार को सिंगुर विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की। राज्य के महाधिवक्ता सुरोजित नाथ मित्रा ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई है। टाटा मोटर्स ने भी स्थगन की मांग का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने सभी मामलों की सुनवाई टाल दी।